



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1001]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2006/भाद्र 16, 1928
No. 1001]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2006/BHADRA 16, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2006

का.आ. 1456(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 21 जुलाई, 2006 के सं. का.आ. 1161(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) के तहत यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संगत नियमों के तहत विधिवत गठित जांच बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और प्राधिकरण ने उक्त बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में, उक्त सार्वजनिक सूचना में यथा उल्लिखित संशोधन की, कुछ परिवर्तनों के साथ सिफारिश की है;

3. और यतः केन्द्र सरकार ने मामले को सभी संगत पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन :

भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 1-8-1990 में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा :-

(1) अंग्रेजी पाठ के पृष्ठ 165 पर (दायीं तरफ) अनुच्छेद 10.0 मिश्रित उपयोग विनियम, के अंतर्गत दिनांक 28-3-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 425(अ) द्वारा यथा-संशोधित विद्यमान प्रावधानों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

10.0 मिश्रित उपयोग विनियम:

इस अध्याय में कुछ अनुमेय प्रयोजनों हेतु भूमि की मिश्रित उपयोग नीति आती है। यह नीति, जिन प्रयोजनों हेतु इसे नियोजित किया गया था, उनसे भिन्न भूमि उपयोग की अनुमति देने की आवश्यकता को मानती है और उन शर्तों को निर्दिष्ट करती है, जिनके अंतर्गत इसे विभिन्न स्थितियों में लागू किया जा सकता है। उक्त नीति को लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य पद्धति और ऐसे क्षेत्रों में ऐसे अनिच्छित उपयोग के प्रभाव का सामना करने के लिए किए जाने वाले शमनीय उपाय भी बताए गए हैं।

10.1 मिश्रित उपयोग के नियंत्रक सिद्धांत

- (i) इस अध्याय के प्रयोजनों हेतु मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय कार्यकलाप के प्रावधान से है।
- (ii) नीति का लक्ष्य ऐसे कार्यकलाप हेतु सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता और आवासीय क्षेत्रों में उक्त कार्यकलाप के पर्यावरण प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना है।
- (iii) मिश्रित उपयोग की नीति आवासों के निकटस्थ क्षेत्र में व्यावसायिक कार्यकलापों तक पहुंचने की अनुमति देती है और शहर में विभिन्न जोनों में आने-जाने की आवश्यकता को कम करती है। तथापि, साथ ही साथ, भीड़भाड़, बढ़ते हुए यातायात और नागरिक सुविधाओं पर बढ़ते हुए दबाव से संबंधित विपरीत प्रभाव को संभालने और कम करने के उद्देश्य से इसे विनियमित करने की आवश्यकता है।
- (iv) मिश्रित उपयोग की अनुमति देने वाले अध्यासेहो सिद्धांतों का प्रयोजन सामुदायिक आवश्यकताओं को मानना तथा उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना तथा सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन और पार्किंग की उचित व्यवस्था करना है।
- (v) मिश्रित उपयोग की अनुमति लुटियंस बंगला क्षेत्र, सिविल लाइन्स, सरकारी आवास, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को सांस्थानिक व स्टाफ आवासों और विरासत संरक्षण समिति द्वारा सूचीबद्ध किए गए भवनों/अहातों में नहीं दी जाएगी।

10.2 आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग:**10.2.1 अलग-अलग दृष्टिकोण :**

- (i) मिश्रित उपयोग नीति में अलग-अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न हो गई है कि दिल्ली देश की राजधानी होने तथा आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण यहां आवासीय क्षेत्रों के प्रकार(टाइपोलॉजी) में काफी भिन्नता है। लुटियंस-दिल्ली के भाग के रूप में और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए नियोजित विकास की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित नियोजित आवासीय कालोनियों के अतिरिक्त चार दोवारी शहर, विशेष क्षेत्रों और शहरीकृत गांवों में प्राधिकृत आवासीय क्षेत्र हैं। अन्य नियोजित क्षेत्रों में पुनर्वास कालोनियां, दिल्ली विकास अधिनियम से पूर्व बसी कालोनियां, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पुनर्वास कालोनियां शामिल हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में नियमित

की गई अनधिकृत कालोनियां, अनधिकृत कालोनियां तथा स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी समूह भी है।

(ii) इसके अतिरिक्त निवासियों द्वारा स्वयं आवश्यक या वांछनीय समझे गए गैर आवासीय कार्यकलाप की सीमा निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उस क्षेत्र में विकास की पुरानी पद्धति के आधार पर भिन्न-भिन्न है। कुछ कालोनियों को, अपनी आजीविका के अमिन्न भाग के रूप में गैर आवासीय कार्यकलाप की जरूरत हो सकती है, जबकि कुछ अन्य कालोनियां अपनी कालोनियों और आसपास के क्षेत्रों के विशेष आवासीय स्वरूप को बनाए रखना चाहेंगी।

(iii) अतः दिल्ली में मिश्रित उपयोग नीति को लागू करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है। अपनाया जाने वाला अलग-अलग दृष्टिकोण संपत्ति कर निर्धारण के यूनिट एरिया सिद्धांत के रूप में दिल्ली नगर निगम द्वारा अपनाए गए क से छ तक कालोनियों के वर्गीकरण के आधार पर होगा।

10.2.2 मिश्रित उपयोग की किस्में

इस अधिसूचना के प्रावधानों के अधीन आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग की निम्नलिखित तीन व्यापक किस्में अनुमेय होंगी:-

- (i) अधिसूचित मिश्रित उपयोग भागों से लगे प्लॉटों में, पैरा 10.6 में दी गई शर्तों के अनुसार फुटकर दुकानों के रूप में वाणिज्यिक कार्यकलाप।
- (ii) पैरा 10.3.2 में निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार वाली सड़कों से लगे प्लॉटों में पैरा 10.7 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, पैरा 10.7.1 में सूचीबद्ध सामान्यतः सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में अन्य कार्यकलाप।
- (iii) पैरा 10.8 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार व्यावसायिक कार्यकलाप।

उपर्युक्त किस्म के मिश्रित उपयोग, परवर्ती पैराग्राफों में निर्दिष्ट सामान्य शर्तों और निबंधनों के अधीन होंगे।

10.3 वर्तमान शहरी क्षेत्रों और शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में मिश्रित भूमि उपयोग का निर्धारण:

दिल्ली के शहरीकृत/शहरी क्षेत्रों तथा शहरीकरण योग्य क्षेत्रों, दोनों में, मिश्रित उपयोग क्षेत्रों/भागों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:

10.3.1 पहले से शहरीकृत / शहरी क्षेत्रों में से निम्नलिखित क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग अनुमेष होगा :-

- i. दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अंतर्गत राक्षम प्राधिकरण द्वारा पहले अधिसूचित और अनुबंध-1 में निर्दिष्ट (निर्दिष्ट भूभागों / मार्गों की सूची) सभी मार्गों / भूभागों पर।
- ii. पूर्व में घोषित व्यावसायिक क्षेत्रों/ मार्गों अथवा जहां दिल्ली मास्टर प्लान - 1962 में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, उन आवासीय क्षेत्रों और मार्गों / भूभागों में, दिल्ली मास्टर प्लान-1962 में अनुमेष सीमा तक, ऐसा उपयोग जारी रहेगा।
- iii. दस्तावेजी प्रमाण की शर्त पर 1962 से पूर्व आवासीय क्षेत्रों में मौजूद वाणिज्यिक कार्यकलाप।
- iv. भविष्य में मिश्रित भूमि उपयोग की पहचान / अधिसूचना पैरा 10.3.2 में दिए गए मानदण्ड के आधार पर तथा पैरा 10.3.3 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार किया जायेगा।

10.3.2 विभिन्न श्रेणियों की कालोनियों में अनुमेष मिश्रित उपयोग की सीमा को नीचे लिखे अनुसार और अधिक स्पष्ट किया जाता है :-

1. श्रेणी क और ख में आने वाली कालोनियों में :

क और ख श्रेणियों के अधीन आने वाली कालोनियों में निम्नलिखित के सिवाय कोई व्यावसायिक कार्यकलाप अनुमेष नहीं होगा :-

- पैरा 10.8 में दी गई शर्तों के अधीन व्यावसायिक कार्यकलाप।
- मास्टर प्लान सड़कों जिन्हें क्रमशः मिश्रित उपयोग मार्गों और व्यावसायिक मार्गों के रूप में अधिसूचित किया गया है, से सटे भूखण्डों में एक भूखण्ड की गहराई तक मिश्रित उपयोग और व्यावसायिक कार्यकलाप क्योंकि ऐसी सड़कें कालोनियों की आन्तरिक सड़कें नहीं हैं (बशर्त कि मिश्रित उपयोग मार्गों अथवा व्यावसायिक मार्गों के रूप में कालोनियों से सटी मास्टर प्लान सड़कों को अधिसूचित करने के लिए संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अनुरोध आवश्यक नहीं होगा)।
- "अन्य कार्यकलाप" नियमित भूखण्ड विकास में न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार की सड़कों से सटे भूखण्डों में पैरा 10.7 में दी गई, शर्तों के अधीन पैरा 10.7.1 में यथा परिभाषित गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होमों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित है क्योंकि ये कार्यकलाप "सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के प्रकार हैं। नए बैंक और फिटनेस केन्द्र इस अधिसूचना की तारीख से अनुमेष नहीं होंगे। तथापि दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अधीन इस संबंध में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार बैंक और फिटनेस केन्द्र जो इस अधिसूचना की तारीख को पहले से ही मौजूद हैं, और न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार की सड़कों से सटे भूखण्डों में हैं, अनुमेष रहेंगे।
- नियमित रिहायशी भूखण्ड विकास में कालोनी के भीतर न्यूनतम 18 मी0 मार्गाधिकार वाले ऐसे मिश्रित उपयोग मार्गों पर पैरा 10.6 के अनुसार फुटकर दुकाने जिन्हें पैरा 10.3.3 के अनुसार अधिसूचित किया गया है यदि पैरा 10.10 के अनुसार संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से विशेष अनुरोध किया जाता है।

नोट :

दिल्ली मास्टर प्लान -2001 के अन्तर्गत पूर्व में अधिसूचित क और ख श्रेणी की कालोनियों के भीतर मिश्रित उपयोग मार्गों पर व्यवसायिक कार्यकलाप तत्काल प्रभाव से बन्द हो जाएंगे (मास्टर प्लान सड़कों से सटे भूखण्डों के सिवाय) ।

2. ग और घ श्रेणियों में आने वाली कालोनियों में :

- अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध अधिसूचित मिश्रित उपयोग मार्गों से सटे भूखण्डों में पैरा 10.6 में दी गई शर्तों के अनुसार फुटकर दुकानों के रूप में मिश्रित उपयोग अनुमेय रहेगा ।
- पैरा 10.7 की शर्तों के अधीन नियमित भूखण्ड विकास में न्यूनतम 18 मी० आर ओ डब्ल्यू पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी० आर ओ डब्ल्यू तथा , नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, विशेष क्षेत्रों और शहरी गांवों में 9 मी० मार्गाधिकार की सड़कों से सटे भूखण्डों में पैरा 10.7 के अनुसार " अन्य कार्यकलाप " अनुमेय होंगे ।
- भविष्य में नियमित रिहायशी भूखण्ड विकास में न्यूनतम 18 मी० मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी० मार्गाधिकार तथा पैरा 10.3.3 के अनुसार नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, पुरानी दिल्ली, विशेष क्षेत्र और शहरी गांवों में 9 मी० मार्गाधिकार के मिश्रित उपयोग मार्गों की अधिसूचना पैरा 10.10 के अनुसार संबंधित रेजीडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशनों के परामर्श के अधीन होगी ।
- पैरा 10.3.3 के अनुसार पैदल शॉपिंग मार्गों में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा ।
- पैरा 10.8 में नियत शर्तों के अनुसार व्यवसायिक गतिविधियां अनुमेय होंगी ।

3. ड.घ और छ श्रेणियों में आने वाली कालोनियों में :

- अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध अधिसूचित मिश्रित उपयोग मार्गों से सटे भूखण्डों में पैरा 10.6 में दी गई शर्तों के अनुसार फुटकर दुकानें अनुमेय रहेंगी ।
- पैरा 10.7 की शर्तों के अधीन नियमित भूखण्ड विकास में न्यूनतम 13.5 मी० मार्गाधिकार पुनर्वास कालोनियों में 9 मी० मार्गाधिकार तथा नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, पुरानी दिल्ली, विशेष क्षेत्र और शहरी गांवों में 6 मी० मार्गाधिकार की सड़कों से सटे भूखण्डों में पैरा 10.7 के अनुसार " अन्य कार्यकलाप " अनुमेय होंगे ।
- पैरा 10.8 में दी गई शर्तों के अधीन व्यवसायिक कार्यकलाप अनुमेय होंगे ।
- भविष्य में नियमित रिहायशी भूखण्ड विकास में न्यूनतम 13.5 मी० मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 9 मी० मार्गाधिकार तथा नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, पुरानी दिल्ली विशेष क्षेत्र और शहरी गांवों में 6 मी० मार्गाधिकार के मिश्रित उपयोग मार्गों की अधिसूचना पैरा 10.3.3 के अनुसार होगी ।
- पैरा 10.3.3 के अनुसार पैदल शॉपिंग मार्गों में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा ।

4. सभी श्रेणियों की कालोनियों में ग्रुप हाऊसिंग

- केवल व्यवसायिक कार्यकलाप अनुमेष होगा। ग्रुप हाऊसिंग की ले-हाउट प्लान में विशेष रूप से उल्लिखित फुटकर दुकानें अनुमेष होंगी।

5. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र (लुटियन बंगला जोन, सरकारी आवास, संस्थागत सार्वजनिक और निजी एजेन्सी के स्टाफ आवास तथा हेरीटेज संरक्षण समिति द्वारा सूचीबद्ध भवनों/क्षेत्रों के सिवाए) में आने वाली कालोनियों के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा मौजूदा मिश्रित उपयोग मार्गों/भूभागों को अधिसूचित किया जायेगा। मिश्रित उपयोग मार्गों/भूभागों की भावी अधिसूचना फील्ड स्तरीय सर्वेक्षण करने के बाद तथा संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएसनों के परामर्श से जारी की जायेगी ताकि सामुदायिक आवश्यकताओं, पर्यावरणीय प्रभाव और यातायात परिचालन/पर्याप्त पार्किंग का आकलन किया जा सके।

10.3.3 भविष्य में शहरी क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग मार्गों की अधिसूचना

i) मिश्रित उपयोग मार्ग के रूप में किसी मार्ग अथवा भूभाग का निर्धारण करने के लिए न्यूनतम मार्गाधिकार निम्नवत होगा:

“क” और “ख” कालोनियों में: नियमित भूखण्ड विकास में 18 मीटर मार्गाधिकार यदि संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएसन का विशेष अनुरोध है।

“ग” और “घ” कालोनियों में: रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएसन के परामर्श से नियमित रिहायशी भूखण्ड विकास में 18 मीटर मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मीटर मार्गाधिकार तथा नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, पुरानी दिल्ली, विशेष क्षेत्र तथा शहरी गाँवों में 9 मीटर मार्गाधिकार।

“ड”, “च” और “छ” कालोनियों में: नियमित भूखण्ड विकास में 13.5 मीटर मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 9 मीटर मार्गाधिकार तथा पुरानी दिल्ली, नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, विशेष क्षेत्रों और शहरी गाँवों में 6 मीटर मार्गाधिकार।

ii) नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, शहरी गाँवों, विशेष क्षेत्र तथा पुरानी दिल्ली में 9 मीटर (अथवा “ड”, “च” और “छ” श्रेणी की कालोनियों में 6 मीटर) से कम के मार्गों को यदि मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित किया जाता है, तो पैदल शॉपिंग मार्ग (पी एस एस) के रूप में घोषित किया जायेगा तथा मोटरयुक्त वाहनों को उस पर चलने नहीं दिया जायेगा।

टिप्पणी:

- (क) कालोनियों से सटी मास्टर प्लान सड़कों को मिश्रित उपयोग सड़कें अधिसूचित करने के लिए संबंधित आरडब्ल्यूए का अनुरोध अथवा संबंधित आरडब्ल्यूए के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है क्योंकि ये सड़कें कालोनियों की आंतरिक सड़कें नहीं हैं।
- (ख) संबंधित आरडब्ल्यूए का विशेष अनुरोध अथवा परामर्श पैरा 10.10 द्वारा शासित होगा।
- (iii) मिश्रित उपयोग सड़कों को अधिसूचित करने के लिए स्थानीय निकाय अधिसूचना जारी होने के समुचित समय के अंदर शीघ्र ही उपर्युक्त चौड़ाई वाली सभी सड़कों का सर्वेक्षण कराएंगे यदि यह पहले न किया गया हो, ताकि मिश्रित उपयोग सड़कों के रूप में इस प्रकार की सड़कों की पहचान हो सके।
- (iv) फील्ड सर्वेक्षण से सड़क पर मौजूद गैर रिहायशी उपयोग के विस्तार, सड़क के जिस भाग को अधिसूचित किया जाना है, नागरिक सुविधाओं की अतिरिक्त आवश्यकता और यातायात व पार्किंग के लिए प्रावधान का मूल्यांकन किया जाएगा।
- (v) फील्ड सर्वेक्षण पूरा होने के तत्काल बाद संबंधित अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्थानीय निकाय/ प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।

10.3.4 भविष्य में शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग सड़कों की अधिसूचना :

नए शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में, निम्नलिखित क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग की अनुमति होगी :-

- (i) नए विकसित आवासीय क्षेत्रों में उपर्युक्त निर्दिष्ट मिश्रित उपयोग केवल 18 मी. मार्गाधिकारों वाले मार्गों पर स्थित आवासीय प्लॉटों पर ही अनुमेय होगा।
- (ii) ऐसे गांवों में जो शहरी घोषित किए जाते हैं और विकास प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं उनमें इस प्रकार के समाकलन हेतु तैयार की गई स्थानीय क्षेत्रीय योजना/लेआउट प्लान में निर्दिष्ट क्षेत्रों/सीमाओं में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा।
- (iii) ऐसे नए क्षेत्रों में लेआउट प्लान में ऐसे विस्तार क्षेत्रों / प्लॉटों को निर्दिष्ट किया जाएगा और निजी विकास के मामले में लेआउट प्लान के लिए अनुमति प्रदान करने के समय उन्हें मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्रों के मामले में आवंटन अथवा नीलामी द्वारा निपटान के समय अधिसूचित किया जाएगा।

10.4 मिश्रित उपयोग को नियंत्रित करने वाले सामान्य निबंधन एवं शर्तें :

उपर्युक्त पैरा 10.3.2 में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों की कालोनियों के लिए निर्धारित शर्तों के संदर्भ में और बशर्ते कि प्लॉट अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़क (फुटकर दुकानों के मामले में) अथवा न्यूनतम मार्गाधिकार (अन्य मिश्रित उपयोग कार्यकलापों के मामले में) वाली सड़क से सटा हो , तो निम्नलिखित शर्तों व निबंधनों के अधीन मिश्रित उपयोग अनुमेष होगा: -

आवासीय भूखण्ड विकास में:

- (i) यदि किसी आवासीय प्लॉट में केवल एक रिहायशी इकाई है तो इस इकाई में केवल एक ही प्रकार के मिश्रित उपयोग (अर्थात् पैरा 10.6 के अनुसार फुटकर दुकान अथवा व्यावसायिक कार्यकलाप अथवा पैरा 10.7 में सूचीबद्ध अन्य कार्यकलापों में से कोई एक) की अनुमति दी जाएगी।
- (ii) यदि किसी आवासीय प्लॉट में एक से अधिक रिहायशी इकाइयाँ हैं तो प्रत्येक रिहायशी इकाई में केवल एक ही प्रकार के मिश्रित उपयोग (पैरा 10.6 के अनुसार फुटकर दुकान अथवा व्यावसायिक कार्यकलाप अथवा पैरा 10.7 में सूचीबद्ध अन्य कार्यकलापों में से कोई एक) की अनुमति होगी।

ग्रुप हाऊसिंग में :

- (iii) ग्रुप हाऊसिंग में, केवल व्यावसायिक कार्यकलाप अनुमेष है। ग्रुप हाऊसिंग के ले-आउट नक्शे में फुटकर दुकान का प्रावधान यदि विशेषरूप से किया जाता है तो उनकी अनुमति दी जाएगी।

अन्य शर्तें एवं निबंधन :

- (iv) मार्गों या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं होगी।
- (v) प्लॉट/आवासीय इकाई को मिश्रित उपयोग में रखने के बाद भी विशेष आवासीय उपयोग के लिए यथा लागू विकास नियंत्रण मानदण्ड लागू रहेंगे।
- (vi) यदि अधिसूचित मार्ग, मुख्य योजना सड़क है, और यदि सेवा सड़क उपलब्ध है अथवा स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तो उस मामले में मिश्रित उपयोग परिसर तक ऐसी सेवा सड़क से पहुंचा जा सके और मुख्य कैरिजवे से सीधे नहीं।
- (vii) भूखंडीय विकास में, आगे के सैटबैक पर चारदीवारी नहीं होगी, ताकि उसका अतिरिक्त पार्किंग के लिए उपयोग किया जा सके।

(viii) परिसरों के अंदर 2.0 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। जहां तक उपलब्ध नहीं है, पार्किंग के विकास की लागत प्लॉट के आर्बित्री/स्वागी द्वारा देय होगी। यह शर्त उन मामलों में भी लागू होगी जहां आवासीय परिसरों का उपयोग केवल व्यावसायिक कार्यों के लिए हो रहा है।

(ix) मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत मार्ग की अधिसूचना के परिणाम स्वरूप यातायात और पार्किंग पर अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित मिश्रित उपयोग के चिह्नित मार्गों पर सामूहिक पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। यदि कोई पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है तो उक्त मार्ग पर भूमि/प्लॉट ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा या तो पार्किंग सुविधाओं के निर्माण के लिए वरीयतः बहुतलीय पार्किंग के लिए अधिग्रहीत किया जाएगा। इस प्रकार की पार्किंग सुविधाओं का विकास या तो ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा और कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल के रूप में सार्वजनिक निजी साझेदारी को भी शामिल किया जा सकता है।

10.5 अनुमेय और गैर अनुमेय उपयोग

किसी भी व्यापार अथवा कार्यकलाप जिसमें किसी प्रकार का हानिकार, जोखिम भरा, ज्वलशील, असंगत और प्रदूषणकारी पदार्थ या प्रणाली हो, को अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.6 फुटकर दुकानें

(i) मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित प्लॉटों और मार्गों पर फुटकर दुकानें केवल भूतल पर अधिकतम अनुमेय भूतल कवरेज तक अनुमत होगी।

(ii) निम्नलिखित कार्यकलापों को मिश्रित उपयोग के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जाएगी :

क. भवन निर्माण सामग्री (लकड़ी, लकड़ी के उत्पाद (फर्नीचर को छोड़कर) मार्बल, लौह एवं इस्पात, (बजरी सीमेंट व रेत) जलाने वाली लकड़ी (फायरवुड), कोयला और अग्नि के जोखिम वाले और अन्य भारी सामग्री वाली फुटकर दुकानें।

ख. ऑटोमोबाइल की मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप, टायर रिसोलिंग और रीट्रीडिंग, बैटरी चार्जिंग वाली दुकानें।

ग. भण्डारण, गोदाम और भाण्डागार।

घ. कबाड़ी की दुकान

ड. शराब की दुकान

घ. मुद्रण, रंगाई एवं वॉलपेपिंग

छ. कोई अन्य कार्यकलाप जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए।

नोट:

1. पूर्णतः तैयार मार्बल उत्पाद के व्यवसायी जो कटिंग और पॉलिशिंग का कार्यकलाप नहीं करती हों, शामिल नहीं हैं।
2. ड., च तथा छ श्रेणी कालोनियों में अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कों में कम से कम 50 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉटों में बजरी, रेत और सीमेंट की फुटकर दुकानों की अनुमति होगी बशर्ते कि सामग्री पूरी तरह प्लॉट परिसर में ही रखी जाए।
3. ऑटोमोबाइल के मामले में सरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप ऐसे प्लॉटों पर अनुमेष होगी जो 30 मीटर या अधिक मार्गाधिकार वाले मिश्रित उपयोग मार्गों से लगे हुए हैं।

10.7 अन्य कार्यकलाप

10.7.1 पैरा 10.4 में उल्लिखित सामान्य शर्तों तथा पैरा 10.7.3 में उल्लिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन, 10.7.2 में यथा-निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार वाली सड़कों के साथ लगे रिहायशी भूखंडों में, चाहे वह सड़क मिश्रित उपयोग मार्ग के रूप में अधिसूचित है या नहीं, निम्नलिखित सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक क्रियाकलापों की भी अनुमति दी जाएगी:-

- (क) प्री-प्राइमरी स्कूल (नर्सरी/मांटेसरी स्कूल, क्रेच सहित)
- (ख) नर्सिंग होम (क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पैथोलोजी लेब तथा डायग्नोस्टिक सेंटर सहित)
- (ग) गेस्ट हाउस (लॉजिंग हाउस सहित), चाहे कमरों की संख्या कितनी भी हो
- (घ) बैंक
- (ङ) फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/मेडिटेशन सेंटर सहित)

10.7.2 किसी मार्ग का न्यूनतम मार्गाधिकार अथवा सड़क का हिस्सा, जिस पर उपर्युक्त अन्य क्रियाकलाप अनुमत्य हैं, इस प्रकार हैं :-

“क” और “ख” कालोनियों में : नियमित भूखंडीय विकास में 18 मी० मार्गाधिकार

टिप्पणी

* तथापि, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले से चल रहे बैंक और फिटनेस सेंटरों के अलावा अन्य बैंक और फिटनेस सेंटरों की अनुमति नहीं होगी।

“ग” और “घ” कालोनियों में : नियमित रिहायशी भूखंडीय विकास में 18 मी० मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी० मार्गाधिकार, नियमित - अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, वाल्ड सिटी, विशेष क्षेत्रों तथा शहरी गांवों, और पैदल शॉपिंग मार्गों में 9 मी० मार्गाधिकार

“ङ”, “च” और “छ” कालोनियों में : नियमित भूखंडीय विकास में 13.5 मी० मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 9 मी० मार्गाधिकार तथा वाल्ड सिटी, नियमित - अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, विशेष क्षेत्रों तथा शहरी गांवों और पैदल शॉपिंग मार्गों में 6 मी० मार्गाधिकार

10.7.3 उपर्युक्त सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक कार्यकलाप पूर्ववर्ती पैराग्राफों में निर्धारित सामान्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होंगे:-

- (i) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित विशेष शर्तों के अधीन निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार वाले मार्गों पर जिन भूखंडों पर ये कार्यकलाप अनुमत्य होंगे, उनका न्यूनतम आकार” हैं

कार्यकलाप अनुमत्य होंगे, निर्धारित भूखंडीय नियमों में 200 वर्ग मी० तथा पुनर्वास कालोनियों, नियमित-अनियमित कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों (रिहबिलीटेशन कालोनी), वाल्ड रिटी, विशेष क्षेत्रों व शहरी भागों में 75 वर्ग मी० होगा। तथापि, इन कालोनियों के साथ-साथ ड, न और छ श्रेणी की कालोनियों में चल रहे क्लिनिक, डिस्पेंसरीयों तथा पैथोलोजी लैब के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार 50 वर्ग मी० होगा।

- (ii) बैंक एफएआर के 2/3 भाग पर 600 वर्ग मी० की शर्त पर अनुमति होंगे, जबकि गेस्ट हाउस और नर्सिंग होम तल क्षेत्र के 3/4 भाग तक अनुमति होंगे।
- (iii) तथापि, मास्टर प्लान सड़कों और जोनल प्लान सड़कों के साथ लगते भूखंडों में चल रहे नर्सिंग होम निर्मित क्षेत्र के 100% तक अनुमति होंगे और भूखंड के आकार की सीमा उन पर लागू नहीं होगी।
- (iv) विशेष क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार की सड़कों के साथ लगते भूखंडों तथा मास्टर प्लान सड़कों व जोनल प्लान सड़कों के साथ लगते भूखंडों पर, जो मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं, निर्मित क्षेत्र के 100% तक अनुमति होंगे और भूखंड के आकार की सीमा उन पर लागू नहीं होगी।
- (v) प्री-प्राइमरी स्कूल तथा फिटनेस सेंटर (वाणिज्यिक मार्गों के साथ लगते भूखंडों को छोड़कर) केवल भूतल पर अनुमत्य तल कवरेज तक सीमित होंगे।
- (vi) उपर्युक्त कार्यकलाप किन्हीं अन्य निबंधनों व शर्तों के अधीन होंगे, जो उन पर लागू संबंधित विधानों/अधिनियमों में यथा निर्धारित हो।
- (vii) भूखंडों के आबंटी/स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पार्किंग की व्यवस्था करें ताकि पार्किंग से सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण/फैलाव न हो।

नोट: ** भूखंड के आकार में $\pm 5\%$ का अन्तर हो सकता है।

10.7.4 बैंकट हॉल की अनुमति केवल औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में होगी न कि रिहायशी उपयोग जोन में। तल कवरेज, तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर), ऊंचाई और वेसमेंट के संबंध में विकास नियंत्रण मानक उस परिसर के लिए विशिष्ट उपयोग हेतु मास्टर प्लान मानकों के अनुसार लागू होंगे।

10.8 व्यावसायिक कार्यकलाप

पैरा 10.4 में विनिर्दिष्ट सामान्य निबंधनों व शर्तों के अधीन भूखंडीय विकास और ग्रुप हाउसिंग में व्यावसायिक कार्यकलापों की अनुमति निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत होगी:-

- i. व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति होगी, यदि निवासी ये कार्यकलाप स्वयं करे।
- ii. व्यावसायिक कार्यकलापों का तात्पर्य उन कार्यकलापों से है, जिनमें डॉक्टर, वकील, वास्तुकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे व्यावसायिक कौशल पर आधारित सेवाएं शामिल हैं।
- iii. ग्रुप हाउसिंग, तथा बहु आवासीय यूनिटों वाले भूखंडीय विकास में किसी भी तल पर व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति होगी, बशर्ते कि यह कार्यकलाप प्रत्येक आवासीय यूनिट के अनुमत्य अथवा स्वीकृत तल क्षेत्र अनुपात, जो भी कम हो, का अधिक से अधिक 50% हो।
- iv. एकल रिहायशी यूनिट वाले भूखंडीय विकास के मामले में व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति केवल एक ही तल पर होगी, लेकिन उस भूखंड पर अनुमत्य अथवा स्वीकृत तल क्षेत्र अनुपात, जो भी कम हो, के 50% से कम पर अनुमति होगी।

10.9 मिश्रित उपयोग परिसरों का पंजीकरण तथा प्रभारों का भुगतान

- i. मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत पहले से आने वाले अथवा मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत लाए जाने वाले रिहायशी परिसरों के मामले में यदि भूखंडीय विकास है तो भूखंड/रिहायशी यूनिट के स्वामी/आबंटी/निवासी तथा यदि ग्रुप हाउसिंग है तो रिहायशी यूनिट को इस संबंध में एक फार्म भरकर ऐसे मिश्रित उपयोग की घोषणा करनी होगी और उस फार्म को संबंधित स्थानीय निकाय के पास जमा कराना होगा तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों पर एकमुश्त पंजीकरण प्रभार जमा कराना होगा।
- ii. मिश्रित उपयोग वाले परिसरों को संबंधित स्थानीय निकाय को, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों पर, जिस अवधि के लिए सम्पत्ति को मिश्रित उपयोग में लाया गया है, उसके लिए हर साल मिश्रित-उपयोग प्रभारों का भुगतान भी करना होगा। पूर्व मूल्यांकन वर्ष (अप्रैल-मार्च) के संबंध में यह भुगतान सम्पत्ति के स्वामी/आबंटी द्वारा हर साल 30 जून से पूर्व स्वैच्छिक रूप से किया जाएगा।
- iii. मिश्रित उपयोग नीति के अन्तर्गत गैर-रिहायशी कार्यकलापों के लिए रिहायशी परिसर का उपयोग करने के लिए भवन में कोई परिवर्तन करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक कि आबंटी/स्वामी ने संशोधित भवन योजना की स्वीकृति न ले ली हो और आवश्यक शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान न कर दिया हो।
- iv. संबंधित स्थानीय निकाय मिश्रित उपयोग वाली परिसम्पत्तियों, चाहे उसके पास पंजीकृत हो या न हो, की परीक्षण जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- v. संगत अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध अन्य दण्डात्मक कार्रवाई के अलावा, पंजीकरण न की गई अथवा इस अधिसूचना के निबंधनों का उल्लंघन करने वाली सम्पत्तियों को मिश्रित उपयोग के लिए वार्षिक परिवर्तन प्रभार का 10 गुना जुर्माना स्थानीय निकाय को अदा करना होगा।

10.10 रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ परामर्श:

- (i) रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) किसी कानून यथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत दिनांक 21.7.2003 के पहले पंजीकृत निकाय होगा।
- (ii) मिश्रित उपयोग वाले मार्गों को घोषित करने के उद्देश्यों के लिए संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा परामर्श किया जायेगा।
- (iii) रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ अर्थपूर्ण परामर्श के लिए स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक प्रयास किये जायेंगे। इस तरह के प्रयासों में शामिल हो सकते हैं : - प्रस्तावित परामर्शों का व्यापक प्रचार, परामर्श के रिकार्ड का रखरखाव और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और जनता तक उन रिकार्डों की पहुंच उपलब्ध कराना।
- (iv) संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ परामर्श व्यापक हो सकता है परन्तु यह मिश्रित उपयोग मार्गों की पहचान तक सीमित होगा और व्यक्तिगत मामलों में अनुमति प्रदान करने के लिए नहीं। तथापि, संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को सार्वजनिक परेशानियों और गैर अनुमेय उपयोगों की शिकायतों के मामलों में अपनी सुनवाई कराने का अधिकार होगा।

10.11 किन मामलों में मिश्रित उपयोग बना किया जा सकता है/ वापस लिया जा सकता है/ प्रतिबंधित किया जा सकता है।

10.11.1 किसी भी ऐसी शर्त, जिसके अंतर्गत ऐसा मिश्रित उपयोग अनुमेय/अनुमत है, के उल्लंघन के मामले में संबंधित स्थानीय निकाय मिश्रित उपयोग की अनुमति अथवा पंजीकरण को रद्द अथवा निलंबित कर सकती है।

10.11.2 निम्नलिखित गैर-रिहायशी कार्यकलाप, जिन्हें मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहायशी क्षेत्रों में अनुमेय होंगे :-

- (i) रिहायशी उपयोग जोनों में रिहायशी परिसरों में चल रहे विद्यालय दिनांक 18 मई, 2007 तक चलते रहेंगे। संबंधित स्थानीय निकाय तत्पश्चात विद्यालयों को चलते रहने की अनुमति दे सकता है बशर्ते दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के उप खण्ड 8(2) क (दिनांक 1.8.1990 को भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित सां.आ. 606 (अ) के तहत पृष्ठ 152-153) के संबंध में स्थानीय निकाय द्वारा अपनी क्षमता के भीतर उपयोग परिसरों/ भू-विन्यास योजना में आवश्यक परिवर्तन किए जायें तथा इस उद्देश्य के लिए विद्यालयों द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय के पास आवेदन करना अपेक्षित होगा।
- (ii) इसके अलावा रिहायशी परिसरों में चल रहे कोचिंग सेंटर तथा ऐसे ही शिक्षण संस्थान वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के अंत तक या 18 मई, 2007 तक, इनमें से जो भी पहले हो, चलते रहेंगे।

10.12 व्यावसायिक सड़कों एवं क्षेत्र :-

10.12.1 निम्नलिखित अधिसूचित मिश्रित उपयोग वाले मार्गों/ मिश्रित उपयोग वाले मार्गों के विस्तार को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक मार्गों या व्यावसायिक क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है :-

- (क) जहां नियमित भूखण्ड विकास वाले क्षेत्र में 24 मीटर से अधिक मार्गाधिकार वाली सड़कों पर कम से कम 300 मीटर लंबी सड़क से लगे प्लॉटों में से 70% से अधिक प्लॉटों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा हो (बशर्तें 'क' और 'ख' श्रेणी की कॉलोनियों में किसी मार्ग को व्यावसायिक मार्ग के रूप में अधिसूचित नहीं किया जायेगा),
- (ख) जहां पैरा 10.3.1 के अनुसार दिल्ली मास्टर प्लान 1962 के तहत घोषित पुनर्वास कालोनियों, अनधिकृत -नियमित कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों (रीसेटलमेंट कालोनी), प्राचीनबद्ध शहर, विशेष क्षेत्र एवं ग्राम तथा स्थानीय व्यावसायिक मार्गों में 24 मीटर मार्गाधिकार से कम चौड़ी सड़कों पर कम से कम 100 मीटर लम्बी सड़क से लगी हुई संपत्तियों में से 70 % से अधिक संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा हो, तथा
- (ग) (ड.), (च) तथा (छ) श्रेणी की कालोनियों में जहां एक हेक्टेयर के संसक्त क्षेत्र के भीतर 80% रिहायशी प्लॉटों का मिश्रित उपयोग हो रहा हो या 300 दुकानें हो ।

10.12.2 ऐसे मार्गों/ विस्तारों (स्ट्रेट्स) की पहचान इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि के बाद यथोचित समयावधि के भीतर तथा यथोचित शीघ्रता से स्थानीय निकाय द्वारा कराए गए फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर की जायेगी ।

10.12.3 पहचान किये जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों/ मार्गों की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा :-

- (i) ऐसे क्षेत्रों/ मार्गों के लिए स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण के अनुमोदन से संशोधित ले-आउट प्लान तैयार करना ।
- (ii) ऐसे क्षेत्रों/ मार्गों के ले-आउट प्लान में परिचालन, पार्किंग, खुले स्थानों की पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान और अन्य योजना मानदण्डों का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
- (iii) किसी मार्ग को व्यावसायिक क्षेत्र/ मार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने के परिणामस्वरूप यातायात और पार्किंग पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए सामान्य पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किए जायेंगे । यदि पार्किंग के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है तो जहां संभव हो उभर्युक्त मार्ग/क्षेत्र में भूमि/प्लॉट ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराया जाये या पार्किंग सुविधाओं, अधिमानतः बहुस्तरीय पार्किंग के निर्माण के लिए भूमि/प्लॉट

का अधिग्रहण किया जाये। ऐसे पार्किंग सुविधाओं का विकास या तो ट्रेडर्स एसोसिएशन या स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यान्वयन के मॉडल के तौर पर इसमें सरकारी-निजी साझेदारी भी हो सकती है।

- (iv) इस खण्ड के तहत किसी व्यावसायिक मार्ग/क्षेत्र को अधिसूचित किए जाने के बाद व्यावसायिक मार्गों पर स्थित प्लॉटों के मालिकों/आवंटियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए लागू विकास नियंत्रण मानकों के तहत अनुमेय क्षेत्र से अधिक कवरेज के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर अतिरिक्त परिवर्तन प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित होगा। ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों/मार्गों में प्लॉटों के आवंटियों/मालिकों के लिए यह केवल एक बार की सुविधा है तथा इसे भविष्य में व्यावसायिक मार्गों/क्षेत्रों में विकास नियंत्रण मानकों में छूट के रूप में नहीं समझा जाये।
- (v) अन्य कोई शर्त जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।

[सं. के-13011/2/2006-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

अनुलग्नक-1

दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में गलियों का मिला जुला उपयोग

1. क्षेत्र "क" भाग "ग" (चार दीवारी शहर)

क्र.सं.	
1.	चाँदनी चौक रोड (100 फुट मार्गाधिकार)
2.	नेताजी सुभाष मार्ग (80 फुट मार्गाधिकार)
3.	अन्सारी रोड (60 फुट मार्गाधिकार)
4.	खारी बावली (80 फुट मार्गाधिकार)
5.	नया बाजार रोड (30 फुट मार्गाधिकार)
6.	श्रद्धानन्द मार्ग (80 फुट मार्गाधिकार)
7.	अजमेरी गेट बाजार (60 फुट मार्गाधिकार)
8.	चर्च मिशन रोड (60 फुट मार्गाधिकार)
9.	एस.पी.एम. मार्ग (120 फुट मार्गाधिकार)
10.	एच.सी.सेन. रोड (100 फुट मार्गाधिकार)
11.	अजमेरी गेट रोड, बाजार सीताराम, गली कूचा पाती राम, गली आर्य समाज, गली काली मस्जिद, गली कटरा अनिखान
12.	बाजार दिल्ली दरवाजा
13.	नेताजी सुभाष मार्ग, सर सइयद अहमद मार्ग, गली कूचा चालान, गली पटौदी हाउस, गली कला महल
14.	गली चूड़ीवालान चावड़ी बाजार, बाजार मटिया महल, सीताराम बाजार, गली पंडित प्रेम नारायण
15.	अजमेरी गेट रोड, फाजिल रोड, गली शाह तारा, गली कूचा पंडित, गली शाह गंज, फराश खाना रोड लाल कुआं बाजार
16.	फराश खाना रोड, समोसा वाली गली, फाजिल रोड, नया बांस रोड, बाजार खारी बावली, कटरा दरिया रोड, गली बताशावाली, गली कूचा नवाब
17.	नेताजी सुभाष मार्ग, दयानंद रोड अन्सारी रोड
18.	कटरा बारीयान रोड, लाल कुआं रोड, गली बल्लीमारान, गली कासिम जान, चावरी बाजार, नई सड़क, चाँदनी चौक ।
19.	नई सड़क, चाँदनी चौक, एसप्लेनेड रोड, दरिबा कला बाजार गुलियान, चावरी बाजार, छाता शाहजी, गली खजूर, गली कटरा कुशल राय, गली अनार वाली, किनारी बाजार, मालीवाड़ा रोड ।
20.	चाँदनी चौक, कटरा नील, चर्च मिशन रोड, कटरा नटवर हरिया
21.	एच.सी. सेन रोड, चाँदनी चौक
22.	बड़ा बाजार रोड

2. क्षेत्र "क" (चार दीवारी शहर के अतिरिक्त)

क्र.सं.		
1	रानी झांसी रोड (आजाद मार्केट से फिल्मिस्तान तक)	गोशाला रोड के पास वाले क्रॉसिंग से फिल्मिस्तान तक (पूर्व की ओर)
2	कुतुब रोड (सिंगाड़ा चौक से पुल मिठाई तक)	सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर बाजार के जंक्शन से पुल मिठाई और रोड के पश्चिम की ओर
3	सदर थाना रोड	सदर थाना से फूटा रोड
4	ईदगाह रोड	सिंगाड़ा चौक से सदर थाना रोड के क्रॉसिंग (रोड के उत्तरी साइड पर)
5	आजाद मार्केट रोड	आजाद मार्केट रोड से पुल मिठाई तक
6	चमेलियन रोड	रानी झांसी रोड क्रॉसिंग से महाराजा अग्रसेन मार्ग जंक्शन तक
7	महाराजा अग्रसेन मार्ग	रानी झांसी रोड जंक्शन से कुतुब रोड क्रॉसिंग तक (सदर बाजार)
8	मेन पहाड़गंज रोड	चेम्स फोर्ड रोड जंक्शन से रामकृष्ण आश्रम तक
9	देश बंधु गुप्ता रोड	पहाड़ गंज पुलिस स्टेशन क्रॉसिंग से शीला सिनेमा के सामने
10	राजगुरु रोड (गुरुवाला रोड)	देश बंधु गुप्ता रोड जंक्शन से मेन बाजार पहाड़गंज रोड जंक्शन तक
11	नेहरू बाजार रोड	पंचकुइया रोड जंक्शन से मेन पहाड़ गंज बाजार रोड जंक्शन तक

3. क्षेत्र "ख"

क्र.सं.		
1	देश बंधु गुप्ता रोड	फैज रोड क्रॉसिंग से प्रस्तावित 30 मी० रोड के जंक्शन तक (नक्शे में रोड नं०-4)
2	बैंक स्ट्रीट	फैज रोड क्रॉसिंग से रामकृष्ण मार्ग क्रॉसिंग तक
3	हरध्यान सिंह रोड	वही-----
4	आर्य समाज रोड	फैज रोड क्रॉसिंग से प्रस्तावित 30 मी० चौड़ी रोड क्रॉसिंग तक (नक्शे में रोड नं०-4)
5	पदम सिंह रोड	सत्वावन गर्ल्स स्कूल रोड क्रॉसिंग से गुरुद्वारा रोड क्रॉसिंग तक
6	न्यू रोहतक रोड (दक्षिण साइड)	फैज रोड क्रॉसिंग से जोशी रोड जंक्शन तक
7	रोड नं० 4 (प्रस्तावित 30 मी० चौड़ी रोड पूर्व साइड)	डी.बी. गुप्ता रोड क्रॉसिंग से पदमसिंह रोड जंक्शन तक

8	न्यू पूसा रोड	डी.टी. गुप्ता रोड जंक्शन से टेक रोड जंक्शन तक
9	रामकृष्णदास मार्ग	डी.टी. गुप्ता रोड जंक्शन से नक्शे में रोड नं० 31 के जंक्शन तक
10	विष्णु मंदिर मार्ग	नक्शे में डी.बी. गुप्ता रोड नं० 31 के जंक्शन से
11	सरस्वती मार्ग	डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
12	अजमल खां रोड	टेक रोड जंक्शन से पूसा लेन जंक्शन तक
13	गुरुद्वारा रोड	डी.टी. गुप्ता रोड जंक्शन से पदम सिंह मार्ग जंक्शन तक
14	लक्ष्मी द्वार मार्ग	आर्य समाज रोड जंक्शन से पूसा लेन जंक्शन तक
15	अबुल अजीज रोड	टेक गली जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
16	कृष्ण दास रोड	डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
17	सत्वरामन आर्य गर्ल्स स्कूल मार्ग (पश्चिम साइड)	आर्य समाज रोड जंक्शन से पूसा लेन जंक्शन तक
18	जोशी रोड	न्यू रोहतक रोड जंक्शन से डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन तक
19	अबुल रहमान रोड	डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
20	इलाही वक्श मार्ग	वही
21	फैज रोड (पश्चिम साइड)	वही

4. क्षेत्र "ग".

1	रोशननारा रोड	1.00
2	जी.टी. रोड	2.18
3	शक्ति मार्ग (नागिया पार्क के निकट)	0.32
4	सत्यवती रोड	0.15
5	मंडेला रोड	0.06
6	कोलाहपुर रोड	0.06
7	मल्कागंज रोड	0.88

5. क्षेत्र "घ "

1.	टेम्पल रोड, भोगल
2.	शाही हॉस्पिटल रोड, भोगल
3.	सैटल रोड, भोगल
4.	मस्जिद रोड, भोगल
5.	गुरुद्वारा रोड, लाजपत नगर-4
6.	रिंग रोड के साथ नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 सर्विस रोड
7.	ब्लॉक "ओ " व के लाजपत नगर-2 के मध्य मेन रोड (24 मी0 चौड़ी)
8.	सैटल मार्केट और लाजपत नगर-2
9.	अलंकार सीनेमा रोड/पुष्पा मार्केट रोड (लाजपत नगर)
10.	भीष्म पितामह रोड (डिफेंस कालोनी)
11.	दुकान प्लॉटों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे का निर्मित भाग

6. क्षेत्र "ड. "

1.	शॉपिंग सेंटर, कृष्णा नगर	
2.	छोटा बाजार, शाहदरा	
3.	मेन गांधी नगर बाजार	
4.	बड़ा बाजार, शाहदरा	
5.	अनाज मंडी, शाहदरा	
6.	विश्वास नगर, शॉपिंग एरिया	
7.	सीलमपुर का शॉपिंग एरिया/सलीमपुर	
8.	फर्श बाजार, शाहदरा	
9.	रेलवे रोड, शाहदरा	
10.	मेन रोड गांधी नगर	मार्जीनल बांध से झील बस टर्मिनल तक
11.	मेन विकास मार्ग	मार्जीनल बांध से पटपड़गंज रोड तक
12.	विजय चौक रोड (लक्ष्मी नगर मेन रोड)	विकास मार्ग से पटपड़गंज रोड
13.	पटपड़गंज रोड	जी.एच.बी.एस. और पुनर्वास कालोनियों के अतिरिक्त झील बस टर्मिनल से मधुबन रेलवे क्रॉसिंग तक
14.	रोड नं0 57	सी.जी.एच.एस. और सुविधा केन्द्रों के अतिरिक्त जी.टी. रेलवे लाइन से परवाना रोड तक
15.	भोलानाथ नगर रोड	रोड नं0 57 से बाबूराम स्कूल तक
16.	मंदिर मार्ग रोड	रघुनाथ मंदिर से रोड नं0 57 तक
17.	रोड नं0 35 ए	पुल क्षेत्र और मदर डेरी प्लॉट के अतिरिक्त विकास मार्ग से मदर डेरी तक
18.	60 फुटा चौड़ा रोड	तेलीवाड़ा से बाबूराम स्कूल तक

10	गौजपुर क्षेत्र में प्रस्तावित मास्टर प्लान रोड नं० 67	रोड नं० 66 से घोडा चौक
20	लोनी रोड	जी.टी. रोड से रोड नं० 68 तक
21	जी.टी.- रोड	राधू सिनेमा से लोनी रोड तक
22	रोड नं० 66	जी.टी. रोड से केवल पश्चिम साइड पर रोड नं० 68 तक
23	ब्रह्मपुरी मेन रोड	घोडा चौक से न्यू सीलमपुर मार्केट रोड
24	यमुना विहार रोड	घोडा चौक से डी.टी.सी. डिपो तक
25	60 फुटा चौड़ा रोड बलबीर नगर (बाबर पुर रोड)	पूर्वी यमुना नहर से जी.टी. रोड तक
26	100 फुटा रोड नं० 68	पूर्वी यमुना नहर रेलवे लेवल क्रॉसिंग तक
27	वजीरा बाद रोड	मार्जिनल बांध यमुना विहार योजना तक (केवल दक्षिण साइड)

7. क्षेत्र "च"

(क)	नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 (रिंग रोड पर सामने का भाग)
(ख)	कालकाजी मेन रोड (ब्लॉक जी और एच तथा ई और एफ के मध्य)
(ग)	मालवीय नगर (मेन मार्केट रोड)
(घ)	गोविंदपुरी और गोविंदपुरी विस्तार के मध्य का रोड
(ड.)	दुकान प्लॉट, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार

8. क्षेत्र "छ"

क	लक्ष्मण सत्त्वानिया, न्यू मोती नगर चौक मेन नजफगढ़ रोड से बाहरी रिंग रोड क्रॉसिंग तक गणेश नगर।
ख	कीर्ति नगर मायापुरी चौक से कीर्ति नगर पटेल नगर चौक के मध्य।
ग	लाजवंती गार्डन चौक से नांगल राय तक।
घ	सुभाष नगर से दीन दयाल उपाध्याय हास्पिटल।
ड.	तिलक नगर चौक से नांगल राय फ्लाई ओवर, जेल रोड।
च	एच ब्लॉक, बाली नगर नजफगढ़ रोड से बी. ब्लॉक बाली नगर तक।

8. क्षेत्र "ज"

1.	रोड नं० 43 रानी बाग	200 फुट
2.	मेन बाजार, ऋषि नगर	50 फुट
3.	मेन बाजार (रोड रानी बाग)	50 फुट
4.	मेन रोड राजा पार्क	100 फुट
5.	मेन रोड, शास्त्री नगर	200 फुट
6.	मेन रोड त्रिनगर	50 फुट
7.	रोड नं० 41 रोहिणी	45 मी०

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2006

S.O. 1456(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi, 2001, were published in the Gazette of India, Extraordinary as public notice vide S.O. No. 1161 (E) dated 21st July 2006, by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act 1957 (61 of 1957) inviting objections and suggestions as required under sub-section (3) of Section 11 A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

2. Whereas the objections and suggestions received with regard to the proposed modifications were considered by a Board of Inquiry duly constituted by Delhi Development Authority under the relevant rules, and the Authority, after considering the report of the said Board, has recommended the modification of the Master Plan of Delhi 2001 as envisaged in the said public notice, with certain changes;

3. And Whereas the Central Government has, after carefully considering all relevant aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2001;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi 2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

In Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 1.8.1990 the following shall be incorporated:-

(i) On page 165(RHS) under CLAUSE 10.0 MIXED USE REGULATIONS the existing provisions, as modified vide notification S.O. No. 425(E) dated 28.3.2006 shall be substituted by the following:-

10.0 MIXED USE REGULATIONS

This chapter covers the policy for mixed use of land for certain permissible purposes. The policy acknowledges the need for permitting use of land for purposes other than that for which it was originally envisaged and lays down the conditions under which this may be applied in different situations. The general procedure to be followed for implementation of the said policy, and mitigating measures to be taken to counter the effect of such non-intended use in such areas are also described.

10.1 GOVERNING PRINCIPLES FOR MIXED USE

- i. Mixed use for the purposes of this Chapter means the provision for non-residential activity in residential premises.
- ii. The policy aims to balance the socio-economic need for such activity and the environmental impact of the said activity in residential areas.
- iii. Mixed use allows access to commercial activities in the proximity of the residences and reduces the need for commuting across zones in the city. However at the same time, it needs to be regulated in order to manage and mitigate the associated adverse impact related to congestion, increased traffic and increased pressure on civic amenities.
- iv. The over-riding principles for permitting mixed use are the need to acknowledge and make adequate provision for meeting community needs, mitigating environmental impact and providing for safe and convenient circulation and parking.
- v. Mixed-use shall not be permitted in the Lutyens Bungalow Zone, Civil Lines, Government housing, Institutional and staff housing of public and private agencies and buildings/precincts listed by the Heritage Conservation Committee.

27835206-1

10.2. MIXED USE IN RESIDENTIAL AREAS:**10.2.1. DIFFERENTIATED APPROACH:**

i). The need for a differentiated approach to mixed use policy arises from the fact that Delhi, being the country's capital and an important centre of economic activity has a large diversity in the typology of residential areas. Apart from the planned residential colonies built as part of Lutyens' Delhi as well as through the process of planned development undertaken by the Delhi Development Authority, there are authorized residential areas in the Walled City, Special areas and urban villages. Other planned areas include resettlement colonies and pre-Delhi Development Act colonies, including post-partition rehabilitation colonies. There are also regularized-unauthorized colonies; unauthorized colonies as well as slums and jhuggi jhonpuri clusters in various parts of Delhi.

ii). Moreover, the extent of non-residential activity seen as being necessary or desirable by the residents themselves varies from area to area based on the socio-economic status of the residents as well as the past pattern of development in that area. While certain colonies may need non-residential activity as an integral part of their livelihood, some others may wish to preserve the residential character of their colonies and neighborhood.

iii). Hence it is proposed to follow a differentiated approach in the application of the mixed use policy in Delhi. The

differentiated approach would be based on categorization of colonies from A to G as adopted by MCD for Unit Area method of property tax assessment.

10.2.2. TYPES OF MIXED USE

Subject to the provisions of this notification, the following three broad types of mixed use shall be permissible, in residential premises:

- i) Commercial activity in the form of retail shops as per conditions given in para 10.6 in plots abutting notified mixed use streets.
- ii) "Other activity" broadly in the nature of 'Public and Semi-Public' facilities listed in para 10.7.1 and as per conditions specified in para 10.7, in plots abutting roads of minimum ROW prescribed in para 10.3.2.
- iii) Professional activity as per conditions specified in para 10.8.

The above mentioned types of mixed use shall be subject to the general terms and conditions specified in the succeeding paragraphs.

10.3 IDENTIFICATION OF MIXED USE AREAS IN EXISTING URBAN AREAS AND URBANIZABLE AREAS:

The identification of mixed use areas / streets in both the urbanized/urban as well as urbanizable areas of Delhi would be as follows:

- 10.3.1. In already urbanized /urban areas, mixed use shall be permissible in the following areas:

278361/06-2

- i. On all streets/ stretches already notified by the competent authority under MPD 2001 and indicated in **Annexure-I** (List of identified stretches / Streets).
- ii. Residential areas and Streets/ stretches earlier declared as commercial areas/ streets or where commercial use was allowed in MPD 1962 shall continue such use at least to the extent as permissible in MPD 1962.
- iii. Commercial activity existing from prior to 1962 in residential areas, subject to documentary proof thereof.
- iv. Identification and Notification of mixed use streets in future, shall be based on the criteria given in para 10.3.2 and as per procedure prescribed in para 10.3.3, and given wide publicity by the local bodies concerned.

10.3.2. The extent of mixed use permissible in various categories of colonies is further clarified as follows:

1. **In colonies falling in categories A and B:**

No commercial activities will be permissible in the colonies of A & B categories **except** the following:

- Professional activity, subject to conditions given in para 10.8.
- Mixed use and Commercial activity up to one plot depth, in plots abutting Master Plan roads that are notified as mixed use streets, and Commercial streets respectively, since such roads are not internal to the colonies (provided that the request of the RWA concerned shall not be necessary for notifying the Master Plan Roads abutting the colonies, as mixed use streets or Commercial Streets).

- "Other activity" restricted to Guest Houses, Nursing Homes and Pre-primary Schools, as defined in para 10.7.1, subject to conditions contained in para 10.7, in plots abutting roads of minimum 18m ROW in regular plotted development, since these activities are in the nature of 'Public and Semi-Public' facilities. New Banks and Fitness Centres will not be permissible with effect from the date of this notification. Banks and Fitness Centres, which already exist, in accordance with notifications issued in this regard under Master Plan for Delhi 2001, from time to time, and are on plots abutting roads of minimum 18m ROW, on the date of notification, shall, however, remain permissible.
- Retail shops in terms of para 10.6, on such mixed use streets with a minimum 18 m ROW, within the colony, in regular residential plotted development, as are notified in terms of para 10.3.3, if there is a specific request of the RWA concerned, in terms of para 10.10.

Note:

Commercial activity on mixed use streets, within A & B category colonies, earlier notified under MPD 2001 shall cease with immediate effect (other than in plots abutting Master Plan roads).

2. In colonies falling in categories C and D:

- Mixed use in the form of Retail shops shall continue to be permissible as per conditions in para 10.6, in plots abutting notified mixed use streets listed in Annexure I.

- "Other activity" in terms of para 10.7 shall be permissible in plots abutting roads of minimum 18 m ROW in regular plotted development, 13.5 m ROW in rehabilitation colonies and 9m ROW in Walled City, Regularized-Unauthorized colonies, resettlement colonies, Special areas, and Urban Villages, subject to conditions in para 10.7.
- Notification of mixed use streets in future, of minimum 18 m ROW in regular residential plotted development, 13.5 m ROW in rehabilitation colonies and 9 m ROW in Regularized-unauthorized colonies, resettlement colonies, Walled city, Special Area and urban villages in terms of para 10.3.3 shall be subject to consultation with RWAs concerned in terms of para 10.10.
- Mixed use shall be permissible in Pedestrianised Shopping streets as per para 10.3.3.
- Professional activities shall be permissible as per conditions laid down in para 10.8.

3. **In colonies falling in categories E, F and G:**

- Retail shops shall continue to be permissible as per conditions in para 10.6., in plots abutting notified mixed use streets listed in Annexure I.
- "Other activity" in terms of para 10.7 shall continue to be permissible in plots abutting roads of minimum 13.5 m ROW in regular plotted development, 9 m ROW in rehabilitation colonies and 6m ROW in Walled City, Regularized-Unauthorized colonies, resettlement

colonies, Special areas, and urban Villages subject to conditions in para 10.7.

- Professional activities shall be permissible subject to conditions in para 10.8.
- Notification of mixed use streets in future, of minimum 13.5 m ROW in regular residential plotted development, 9 m ROW in rehabilitation colonies and 6 m ROW in Regularized-Unauthorised colonies, resettlement colonies, walled City, Special Area and urban villages shall be in terms of para 10.3.3.
- Mixed use shall be permissible in Pedestrianised Shopping streets as per para 10.3.3.

4. **Group housing in all categories of colonies:**

- Only professional activity shall be permissible. Retail shops specifically provided for in the lay out plan of group housing would be permissible.

5. **In respect of colonies falling in NDMC area**

(excluding Lutyens Bungalow Zone, Government housing, institutional and staff housing of public and private agencies and buildings/precincts listed by the Heritage Conservation Committee), existing mixed use streets / stretches will be notified by NDMC. Future notification of mixed use streets/ stretches will be done on a field level survey to assess the community needs, environmental impact and traffic circulation/ adequate parking and in consultation with Residents Welfare Associations concerned.

27834I/06-3

10.3.3. Notification of mixed use streets in urban areas in future:

- i). The minimum ROW for identification of a street or stretch of road as mixed use street would be as follows:

In A&B Colonies: 18m ROW in regular plotted development, if there is a specific request of the RWA concerned.

In C&D colonies: 18 m ROW in regular residential plotted development, 13.5 m ROW in rehabilitation colonies and 9 m ROW in Regularised-Unauthorised colonies, resettlement colonies, Walled City, Special area and urban villages; in consultation with RWA concerned.

In E,F&G Colonies: 13.5 m ROW in regular plotted development, 9 m ROW in rehabilitation colonies and 6m ROW in Walled City, Regularized-Unauthorized colonies, resettlement colonies, Special areas, and Urban Villages.

- ii) Streets of less than 9 m (or 6 m in E, F & G category colonies) ROW in Regularised-Unauthorised colonies, resettlement colonies, urban villages, Special Area and Walled City, if notified for mixed use, shall be declared as Pedestrian Shopping Streets (PSS) and will not be open to motorized transport.

Note:

- (a) Request of the RWA concerned or consultation with RWAs concerned, shall not be necessary for notifying the Master Plan Roads abutting the colonies as mixed use streets, since such roads are not internal to the colonies.
- (b) Specific request of or consultation with RWA concerned shall be governed by para 10.10

iii) For the notification of mixed use streets, local bodies shall be required to carry out within a reasonable time of the Notification coming into force; and with due expedition, a survey of all streets of the above-mentioned width, if not already done, with a view to identifying stretches of such streets as mixed use streets.

iv) The field survey shall assess the extent of existing non-residential use on the street, the stretch of the street to be notified, the additional requirement of civic amenities and the provision for traffic circulation and parking.

v) The notification shall be issued by the local body/ Authority, with the approval of the Competent Authority under the relevant Act, immediately after the field survey is completed.

10.3.4. Notification of mixed use streets in urbanizable areas in future:

In new urbanizable areas, mixed use shall be permissible in the following areas:

- i) In newly developed residential areas, mixed use as specified above shall be permitted only on residential plots abutting 18 m. ROW roads.
- ii) In villages that are declared as urban and get integrated into the process of development, mixed use shall be permissible in areas/ stretches identified in the local area plan/ lay out plan prepared for such integration.
- iii) The layout plan in such new areas shall earmark such stretches/ plots and notify them under the Mixed Use Policy at the time of grant of permission for layout plan in the case of private development and at the time of disposal by allotment or auction in the case of areas developed by DDA.

10.4 GENERAL TERMS AND CONDITIONS GOVERNING MIXED USE:

In terms of the conditions prescribed for different categories of colonies, in para 10.3.2, and provided that the plot abuts a notified mixed use street (in the case of retail shops) or a road of prescribed minimum ROW (in the case of other mixed use activities), mixed use shall be permitted, subject to the following general terms and conditions:

In residential plotted development:

- (i) Where there is only one dwelling unit in a residential plot, only one type of mixed use (i.e., retail shop as per para 10.6 OR professional activity OR one of the other activities listed in para 10.7) shall be permissible in that unit.

- (ii) Where there are more than one dwelling units in a residential plot, each of the dwelling units will be permitted to have only type of mixed use activity (either retail shop as per para 10.6, OR professional activity OR any one of the other activities listed in para 10.7)

In group housing:

- (iii) In group housing, only professional activity is permissible. Retail shops shall be permissible if specifically provided for in the lay out plan of group housing.

Other terms and conditions:

- (iv) No encroachment shall be permitted on the streets or public land.
- (v) Development control norms as applicable for the particular residential use will continue to be applicable, even if the plot/ dwelling unit is put to mixed use.
- (vi) If the notified street is a Master Plan Road, and if a service road is available or provided for by local bodies, then, the mixed use premises should be approached from such service road and not directly from the main carriageway,
- (vii) In plotted development, front setback should not have boundary wall, so that it can be used for additional parking.
- (viii) Parking @ 2.0 ECS per 100 sqm shall be provided within the premises. Where this is not available, cost of development of parking, shall be payable by the plot

278302/06-4

allottee/ owner to the local body concerned. This condition shall apply even if residential premises are used only for professional activity.

- (ix) Common parking areas would be earmarked on notified mixed use streets taking into account the additional load on traffic and parking consequent upon notification of the street under Mixed Use Policy. If no parking space is available, land/ plot on the said street may be made available by Traders association, wherever possible, or acquired for construction of parking facilities, preferably, multi level parking. Development of such parking facilities shall be done by either the traders Association or by local bodies and may include public-private partnership as a model for implementation.

10.5 PERMISSIBLE AND NON-PERMISSIBLE USES:

Any trade or activity involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non-compatible and polluting substance or process shall not be permitted.

10.6 RETAIL SHOPS

- i. Retail shops shall be permitted on plots abutting streets notified for mixed use only on the ground floor and up to the maximum permissible ground floor coverage.
- ii. The following activities shall not be allowed under Mixed Use:
 - a) Retail shops of building materials (timber, timber products (excluding furniture), marble, iron and

steel, (gravel, cement and sand)², firewood, coal and any fire hazardous and other bulky materials.

- b) Repair shops of automobiles repair and workshop, tyre resoling and re-treading, and battery charging³.
- c) Storage, go-down and warehousing.
- d) Junk shop
- e) Liquor shop
- f) Printing, dyeing and varnishing
- g) Any other activity that may be notified from time to time by Government.

Note:

1. Will not include business of finished marble products where cutting and polishing activity of marble is not undertaken.
- ² Retail shops of gravel, sand and cement shall be permissible in residential plots of at least 50 sqm, in notified mixed use streets in E, F, and G category colonies, provided that the material is kept entirely within the plot premises.
- ³ The repair shops and workshops in case of automobiles shall not be prohibited on plots abutting mixed use streets or commercial streets of right of way (ROW) of 30 m or more

10.7 OTHER ACTIVITY

10.7.1 Subject to the general conditions given in para 10.4 and additional conditions given in para 10.7.3, the following public and semi-public activities shall also be permitted in the residential plots abutting roads of minimum ROW prescribed in 10.7.2, whether or not the road is notified as mixed use street:

- (a) Pre-primary school (including Nursery/Montessori School, Crèche.)
- (b) Nursing home (including clinic, dispensary, pathology lab and diagnostic centre)
- (c) Guest house (including lodging houses) irrespective of number of rooms.
- (d) Bank
- (e) Fitness Centre (including Gymnasium, yoga/ meditation centre)

10.7.2. The minimum ROW of a street or stretch of road on which the above-mentioned other activities are permissible is as follows:

In A&B Colonies*: 18m ROW in regular plotted development;

Note

*Banks and fitness centres shall however, not be permissible, except those already operating on the date of this notification.

In C&D colonies: 18 m ROW in regular residential plotted development, 13.5 m ROW in rehabilitation colonies and 9 m ROW in Regularized-Unauthorised colonies, resettlement colonies, Walled City, special area and urban villages; and in Pedestrianised Shopping Streets.

In E, F & G Colonies: 13.5 m ROW in regular plotted development, 9 m ROW in rehabilitation colonies and 6m ROW in Walled City, Regularised-Unauthorised colonies, resettlement colonies, Special areas, and urban Villages and in Pedestrianised Shopping Streets.

10.7.3. The above mentioned public and semi-public activities shall be subject to the following additional conditions in addition to general conditions prescribed in preceding paras:

- (i) Subject to the specific conditions mentioned in succeeding paras, the minimum size** of the plot on which these activities shall be permissible, on streets of prescribed minimum ROW, shall be 200 sqm in regular plotted development, 75 sqm in rehabilitation colonies, regularized-unauthorized colonies, resettlement colonies, Walled City, special area & urban villages. However, the minimum plot size shall be 50 sqm for clinic, dispensaries and pathology labs running in these colonies and also in E, F and G Category colonies.
- (ii) Banks shall be permissible on $2/3^{\text{rd}}$ of FAR subject to 600 sqm, while Guest House and Nursing Homes will be permissible up to $3/4^{\text{th}}$ of the floor area.
- (iii) However, Nursing Homes operating in plots abutting Master Plan roads and Zonal Plan roads shall be

2783GE/06-5

permissible up to 100% of built up area and the limits on the size of the plot would not apply.

- (iv) Guest Houses operating in plots abutting streets of prescribed minimum ROW in Special Area and in plots abutting Master Plan roads and Zonal Plan roads shall be permissible up to 100% of built up area and the limits on the size of the plot shall not apply.
- (v) Pre-primary school and fitness centre (other than those on plots abutting Commercial streets) shall be restricted only to the ground floor up to the permissible ground coverage.
- (vi) The above mentioned activities shall also be subject to any other specific terms and conditions, as may be prescribed in the relevant Statutes/ Acts applicable to them.
- (vii) It shall be the responsibility of the plot allottee/ owner to make arrangements for parking so that the parking does not encroach/ spill over on public land.

Note:

****Variation of $\pm 5\%$ in plot size may be disregarded.**

10.7.4. **Banquet hall** shall be permissible only in industrial areas and commercial areas and not in the residential use zone. Development control norms in respect of Ground coverage, FAR, height and basement shall be applicable as per Master Plan Norms for the specific land use for that premises.

10.8. PROFESSIONAL ACTIVITY

Subject to the general terms and conditions specified in para 10.4, professional activity is permissible in plotted development and group housing under the following specific conditions:

- i. Professional activity shall be permitted if carried out by the resident him/her self.
- ii. Professional activities shall mean those activities involving services based on professional skills namely Doctor, Lawyer, Architect, and Chartered Accountant.
- iii. In group housing, and plotted development with multiple dwelling units, professional activity shall be permitted on any floor subject to maximum of 50% of the permissible or sanctioned FAR, whichever is less, of each dwelling unit
- iv. In the case of plotted development with single dwelling unit, professional activity shall be permissible on any one floor only, but restricted to less than 50% of the permissible or sanctioned FAR, whichever is less on that plot.

10.9 REGISTRATION OF MIXED USE PREMISES AND PAYMENT OF CHARGES:

- i. In respect of a residential premises already under mixed use or intended to be put to mixed use, the owner/allottee/ resident of the plot/ dwelling unit, in case of plotted development and dwelling unit in the case of group housing, shall be required to declare such mixed-use by filling up a form in this respect and

depositing it with the local body concerned and pay one-time registration charges at rates to be notified with the approval of the Central Government.

- ii. The premises under mixed use shall also be liable for payment of mixed-use charges every year to the local body concerned, at the rates notified with the approval of Central Government, for the period during which the property is put to mixed use. Such payment will be made by the property owner/ allottee voluntarily before 30th June of every year in respect of the previous assessment year (April- March).
- iii. No modification to the building for using residential premises for non-residential activities, under the mixed use policy, shall be permitted unless the allottee/ owner has obtained sanction of revised building plans and has paid necessary fees or charges.
- iv. The local body concerned shall be responsible for the conduct of test check of properties under mixed use, whether registered with it or not.
- v. In addition to other penal action available under the relevant Act, properties found to be under mixed use, without registration or in violation of the terms of this notification shall be liable to pay, to the local body, a penalty amounting to 10 times the annual conversion charges for mixed use.

10.10 CONSULTATION WITH RWAs

- i. The Resident Welfare Association (RWA) shall be a body registered before 21.7.2006, under any Statute, such as Societies Registration Act.
- ii. Consultation with the RWA concerned for the purposes of declaring mixed use streets shall be done by the local bodies concerned.
- iii. Genuine efforts for meaningful consultations with RWAs shall be made by the local bodies. Such efforts may include wide publicity to the proposed consultations, maintenance of record of consultation and providing access to those records to RWA concerned and public.
- iv. Consultation with the RWA concerned shall be limited to identification of mixed use streets, and not for grant of permission in individual cases. However RWAs shall have a right to be heard in cases of complaints of public nuisance and non-permissible uses.

10.11 UNDER WHAT CONDITIONS MIXED USE CAN BE DENIED/ WITHDRAWN/ RESTRICTED:

10.11.1. Permission or registration for mixed use can be cancelled or suspended by the concerned local body in case of violation of any of the conditions under which such mixed use is permissible/ permitted.

10.11.2. The following non-residential activities, not covered under the mixed use policy, shall be permissible in residential areas under the following conditions:

278347/06-6

(i) Schools operating in residential premises in the Residential use zones shall continue till 18th May 2007. The local body concerned may allow the schools to continue thereafter, subject to necessary changes being made in the use-premises/ lay-out plan, by the local body, within its competence, in terms of Sub clause 8 (2) A of the Master Plan for Delhi 2001 (Page 152 -153 under S.O. 606 (E) in the Gazette of India Extraordinary dated 1.8.1990), and for this purpose the schools shall be required to apply to the local body concerned.

(ii) In addition, Coaching centres and similar educational institutions, running in residential premises, shall be allowed to continue till the end of the current academic year or till 18th May 2007, whichever is earlier.

10.12 COMMERCIAL STREETS AND AREAS:

10.12.1. The following streets/ stretches of streets or areas may be notified as Commercial Streets or Commercial areas by the local authority:

(a) where more than 70% of the plots abutting roads of ROW exceeding 24m, in a stretch of at least 300m, in regular plotted development are under commercial use, on (provided that no street in colonies in A and B categories shall be notified as commercial street).

(b) where more than 70% of the properties abutting roads of less width than 24m ROW, in a stretch of at least 100m, in rehabilitation colonies, Regularized-Unauthorized colonies, resettlement colonies, Walled City, Special Area and urban

Villages and local commercial streets declared under MPD 1962 as per para 10.3.1; and

(c) In E, F and G category colonies, where, [If] 80% of residential plots are under mixed use, or if there are 300 shops, within a contiguous area of 1 hectare.

10.12.2. Identification of such streets/ stretches is to be done on the basis of field survey to be conducted by the local body within a reasonable period of time and with due expedition of the date of this notification coming into force.

10.12.3 After identification is done, notification of commercial stretches/ streets by the local body/ authority with the approval of the Competent Authority would necessitate compliance to the following terms and conditions:

- i) Preparation of revised lay-out plan/ Scheme for such areas/ streets with the approval of the local body/ Authority;
- ii) The lay-out plan/ Scheme for such areas/ streets should indicate adequate provision for circulation, parking, open spaces and other planning norms;
- iii) Common parking areas would be earmarked taking into account the additional load on traffic and parking consequent upon notification of the street as commercial area/ street. If no parking space is available, land/ plot on the said street/ area may be made available by Traders association, wherever possible, or acquired for construction of parking facilities, preferably, multi level parking. Development of such parking facilities may be done by either the traders Association or by local bodies and may include public-private partnership as a model for implementation.

278342/06-7

iv) On notification of a Commercial street/ area under this clause, such streets/ areas shall be considered as non-hierarchical commercial centres as mentioned in Development Code in Master Plan 2001. The plot owners / allottees on these commercial streets/ areas shall have to pay Special conversion charges at rates approved by the Central Government, in respect of the built up area used for commercial purpose, provided that such built up area shall not exceed the residential development control norms applicable to the plot. This is only a one-time facility for plot allottees/ owners in such Commercial areas/ streets and shall not be construed as relaxation of the development control norms in future.

v). Any other condition that may be prescribed by Government from time to time.

[No.K-13011/2/2006/DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

Annexure - I

MIXED USE STREETS IN VARIOUS ZONES OF DELHI

1. Zone 'A' & part 'C' (Walled City)
 1. Chandni Chowk road (100 ft R/W)
 2. Netaji Subhash Marg (80 ft. R/W)
 3. Ansari Road (60 ft. R/W)
 4. Khari Baoli (80 ft. R/W)
 5. Naya Bazar Road (80 ft. R/W)
 6. Shardanand Marg (80 ft. R/W)
 7. Ajmeri Gate Bazar (60 ft. R/W)
 8. Church Mission Road (60 ft. R/W)
 9. S.P.M. Marg (120 ft. R/W)
 10. H.C Sen Road (100 ft. R/W)
 11. Ajmeri Gate Road Bazar Sita Ram, Gali Kucha Pati Ram, Gali Arya Samaj, Gali Kali Masjid, Gali Katra Anikhan.
 12. Bazar Dilli Darwaza
 13. Netaji Subhash Marg, Sir Syed Ahmad Marg, Gali Kuncha Chalan, Gali Pataudi House, Gali Kala Mehal,
 14. Gali Churiwalan Chawri Bazar, Bazar Matia Mahal, Sita Ram Bazar, Gali Pandit Prem Narainh
 15. Ajmeri Gate Road, Fasil Road, Gali Shah Tara, Gali Kucha Pandit, Gali Sahaganj Farashkhana Road, Lal Kuan Bazar.
 16. Farash Khana Road, Samosa Wali Gali, Fasil Road, Naya Bans Road, Bazar Khari Baoli, Katra Dariyan Road, Gali Batashawali, Gali Kucha Nawab.
 17. Netaji Subhash Marg, Dayanand Road, Ansari Road
 18. Katra Bariyan Road, Lal Kuan Road, Gali Ballimaran, Gali Kashim Jaan, Chawri Bazar, Nai Sarak, Chandni Chowk.
 19. Nai Sarak, Chandni Chowk Esplanade Road, Dariba Kalan Bazar Gulian, Chawhi Bazar, Chatta Shahji, Gali Khajoor, Gali Katra Kushal Rai, Gali Anar Wali, Kinari Bazar, Maliwara Road.
 20. Chandni Chowk, Katra neel, Church Mission Road, Katra Natwar Area.
 21. H.C. Sen Road, Chandni Chowk
 22. Bara Bazar Road.

2. Zone - A (Part other than Walled City):

1.	Rani Jhanzi Road (Azad Market Chowk to Filmistan)	From crossing with Gaushala Road to Filmistan (On East side)
2.	Qutub Road (Singhara Chowk to Pul Mithai)	From junction near Sr. Sec. School Sadar Bazar to Pul Mithai and Western side of the road.
3.	Sadar Thana Road	Sadar Thana to Phoota Road
4.	Idgah Road	Singhara Chowk to crossing with Sadar Thana Road (on North side of the road)
5.	Azad Market Road	Azad Market Road to Pul Mithai
6.	Chamelian Road	From crossing with Rani Jhansi Road to junction with Maharaja Agrasen Marg.
7.	Maharaja Agrasen Marg	From junction with Rani Jhansi Road to crossing with Qutub Road (Sadar Bazar)
8.	Main Paharganj Road	From junction with Chemsford Road to Ram Krishna Ashram
9.	Desh Bandhu Gupta Road	Paharganj Police Station Crossing to opposite Sheila Cinema.
10.	Rajguru Road (Guru Wala road)	Junction with Desh Bandhu Gupta Road to junction with main bazaar Paharganj Road
11.	Nehru Bazar Road	From junction with Panchkuin Road to junction with main Paharganj Bazar road

3. Zone - B:

1.	Desh Bandhu Gupta Road	From crossing with Faiz Road to junction with proposed 30 mtr Road (road No.4 in the layout plan)
2.	Bank Street	From crossing with Faiz road to crossing with Rama Krishna Marg
3.	Hardhyan Singh Road	-do-
4.	Arya Samaj Road	From crossing with Faiz Road to crossing with proposed 30 mtrs. wide road (Road No.4 in the layout plan).

5.	Padam Singh Road	From crossing with Satbravan Girls School road to Crossing with Gurudwara Road
6.	New Rohtak Road (South Side)	From crossing with Faiz Road to junction with Joshi road
7.	Road No.4 (Proposed 30M wide Road (East Side))	From crossing with D.B.Gupta Road to junction with Padam Singh Road
8.	New Pusa Road	From junction with D.B.Gupta Road to junction with Tank Road
9.	Ram Krishan Dass Marg	From junction with D.B.Gupta Road to junction with Road No.31 of the layout plan
10.	Vishnu Mandir Marg	From junction with D.B.Gupta Road No.31 of the layout plan
11.	Saraswati Marg	From junction with D.B.Gupta Road to junction with Arya Samaj Road
12.	Ajmal Khan Road	From junction with Tank Road to junction with Pusa Lane
13.	Gurudwara Road	From junction with D.B.Gupta Road to junction with Padam Singh Road
14.	Laxmi Dwar Marg	From junction with Arya Samaj Road to junction with Pusa Lane
15.	Abdul Aziz Road	From junction with Bank Street Road to junction with Arya Samaj Road
16.	Krishna Dass Road	From junction with D.B.Gupta Road to junction with Arya Samaj Road
17.	Satbharavn Arya Girls School Marg (West Side)	From junction with Arya Samaj Road to junction with Pusa Lane
18.	Joshi Road	From junction with New Rohtak Road to junction with D.B. Gupta Road
19.	Abdul Rehman Road	From junction with D.B.Gupta Road to junction with Arya Samaj Road
20.	Ilahi Baksh Marg	-do-
21.	Faiz Road (West Side)	-do-

4. Zone - C:

1.	Roshnara Road	1.00
2.	G.T.Road	2.18
3.	Shakti Marg (Nagia Park round about)	0.32
4.	Satyawati Road	0.15
5.	Mandella Road	0.06
6.	Kolhapur Road	0.06
7.	Malka Ganj Road	0.88

5. Zone - D :

1. Temple Road, Bhogal
2. Shahi Hospital Road, Bhogal
3. Central road, Bhogal
4. Masjid Road, Bhogal
5. Gurudwara Road, Lajpat Nagar-IV
6. New Delhi South Extn. Part-I Service Road along Ring Road.
7. Main Road (24 M wide) between blocks 'O' & 'K', Lajpat Nagar-II
8. Central Market & Lajpat Nagar-II
9. Alankar Cinema Road/Pushpa Market Road (Lajpat Nagar)
10. Bhisham Pitamah Road (Defence Colony)
11. In addition, shops, plots forming part of an approved layout of the competent authority.

6. Zone - E :

1. Shopping Centre, Krishna Nagar
2. Chhota Bazar, Shahdara
3. Main Gandhi Nagar Bazar
4. Bara Bazar, Shahdara
5. Anaj Mandi, Shahdara
6. Shopping Area of Viswas Nagar
7. Shopping Area of Seelampur/ Salimpur
8. Farash Bazar, Shahdara

- | | |
|---|---|
| 9. Railway Road, Shahdara | |
| 10. Main Road Gandhi Nagar | From Marginal Bandh to Jheel Bus Terminal |
| 11. Main Vikas Marg | From Marginal Bandh to Patparganj Road |
| 12. Vijay Chowk Road (Laxmi Nagar Main Road) | From Vikas Marg to Patparganj Road |
| 13. Patparganj Road | From Jheel Bus Terminal to Madhuvan Railway Crossing excluding the GHBS and Rehabilitation Colonies |
| 14. Road No.57 | From GT Railway Line to Parwana Road excluding CGHS and facility centres |
| 15. Bhola Nath Nagar Road | From No.57 to Babu Ram School |
| 16. Mandir Marg Road | From Raghunath Mandir to Road No.57 |
| 17. Road No.35A | From Vikas Marg to Mother Dairy excluding bridge area and Mother Dairy Plant |
| 18. 60 ft. wide Road | From Teliwara to Babu Ram School |
| 19. Proposed Master Plan Road No.67 in Maujpur area | From Road No.66 to Ghonda Chowk |
| 20. Loni Road | From G.T. Road to Road No.68 |
| 21. G.T. Road | From Radhu Cinema to Loni Road |
| 22. Road No.66 | From G.T. Road to Road No.68 on Western side only. |
| 23. Brahmpuri Main Road | From Ghonda Chowk to New Seelampur Market, Road |
| 24. Yamuna Vihar Road | From Ghonda Chowk to DTC Depot. |
| 25. 60 ft wide road Balbir | From Eastern Yamuna |

- Nagar (Bābur Pur Canal to G.T. Road Road)
26. 100 ft. Road No.68 From Eastern Yamuna canal upto Railway level crossing
27. Wazirabad Road From Marginal Bund upto Yamuna Vihar Scheme (on South side only)

7. Zone - F :

- (a) New Delhi South Ext. Part-II (Portion fronting on Ring Road)
- (b) Kalkaji Main Road (Between Block G&H and E&F).
- (c) Malviya Nagar (Main Market Road)
- (d) Road between Govindpuri and Govindpuri extension
- (e) Shop-plots, forming part of an approved layout plan of the competent authority

8. Zone - G :

- a) Main Najafgarh Road from Laxman Sylvania, New Moti Nagar Chowk to Outer Ring Road Crossing i.e. Ganesh Nagar
- b) Between Kirti Nagar Maya Puri Chowk to Kirti Nagar Patel Nagar Chowk
- c) Lajwanti Garden Chowk to Nangal Raya
- d) Subhash Nagar to Din Dayal Upadhyaya Hospital
- e) Tilak Nagar Chowk to Nangal Raya Flyover i.e. Jail Road
- f) H-Block, Bali Nagar Najafgarh Road to B-Block, Bali Nagar.

9. Zone - H :

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Road No.43, Rani Bagh | 200 ft. |
| 2. Main Bazar, Rishi Nagar | 50 ft. |
| 3. Main Bazar (Road Rani Bagh) | 50 ft. |
| 4. Main Road, Raja Park | 100 ft. |
| 5. Main Road, Shastri Nagar | 200 ft. |
| 6. Main Road, Tri Nagar | 50 ft. |
| 7. Road No.41, Rohini | 45 mt. |



No. K-20013/4/2006-DDVA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 24th August, 2006.

✓
9414-PC/MS
29/8/06

To

✓
The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023.

649-AD/ML
29-8-06

Sub: Amendment of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 - Disposal of Senior Secondary School sites.

PC-secy.

✓
LH/D

Sir,

Please refer to DDA's letter dated 3.2.2006 enclosing therewith a copy of the resolution relating to Agenda Item No.10/2006 of the Authority meeting held on 19.1.2006 on the above mentioned subject.

2. The proposal contained in Item No.10/06 of the Authority meeting held on 19.1.2006 has been approved by the Government and accordingly the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 have been amended vide notification dated 19.4.2006. A copy of the said notification is also enclosed herewith.

Yours faithfully,

[Signature]

(Prem Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Encl: As above.

Copy to:

1. The Secretary (Education), GNCTD, Old Secretariat, Delhi-110 054.
2. The Director (Education), GNCTD, Old Secretariat, Delhi-110 054. A copy of resolution relating to Item No.10/2006 of the Authority meeting held on 19.1.2006 and Amendment Notification dated 19.4.2006 are enclosed herewith for information.

Cd.
OSD(L)
DD (Secy.)

(Prem Kumar)
Under Secretary

15733
24/9/06
Office
all
concerned
29/8
DD (Secy.)
1/2/8/06
AD/ML
ca. Dev. Backers
1/8



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

No. 157]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2006/चैत्र 29, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) संशोधन नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में:-

- (i) उप-नियम(1) में "व्यक्ति निकायों" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति-निकाय, फर्मों, कंपनियों" शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) उप-नियम(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) प्राधिकरण योजनाओं के अनुरूप तथा इन नियमों के उपबंधों के अधीन नजूल भूमि का व्ययन निम्नलिखित संस्थाओं को नीलामी द्वारा करेगा:-

- (क) अस्पताल,
- (ख) औषधालय (डिस्पेंसरी)
- (ग) नर्सिंग होम
- (घ) उच्चतर अथवा तकनीकी शिक्षा संस्थान,
- (ङ.) सामुदायिक हॉल,
- (च) क्लब,
- (छ) विद्यालय,

परन्तु इस उप-नियम की कोई बात उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय निकाय को भूमि के आवंटन को प्रभावित नहीं करेगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 में;

- (i) "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "नियम 4 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीय प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) स्पष्टीकरण को लोप किया जायेगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"8. नियम 4 के उप नियम(2), नियम 5, 6, और 7 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी प्रयोजन के लिए नजूल भूमि का आवंटन ऐसे प्रीमियम के भुगतान पर किया जाएगा जितना कि इन नियमों के यथास्थिति अध्याय-3 या अध्याय-4, के उपबंधों के अनुसार या तो नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा अवधारित किया जाए।"

5. उक्त नियमों के नियम 16 में, आरंभिक पैरा में "व्यक्ति जिनके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्रवर्ग" भी हैं, शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्रवर्ग भी हैं, कम्पनी और फर्म" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 20 में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु इस नियम की कोई बात नियम 4 के उपनियम(2) के उपबंधों को लागू नहीं होगी।"

7. उक्त नियमों के नियम 42 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात्:

"परन्तु इस नियम में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण, रिहायशी प्रयोजन अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नीलामी अथवा निविदा के माध्यम से फ्रीहोल्ड आधार पर नजूल भूमि आवंटित कर सकता है।"

"यह और भी कि फ्रीहोल्ड आधार पर आवंटन के मामले में आवंटिती प्रारूप ख क में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा।"

8. उक्त नियमों में प्रारूप ख के पश्चात निम्नलिखित प्रारूप अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

फार्म ख क
(नियम 42 देखें)
हस्तांतरण विलेख

(नीलामी अथवा निविदा के जरिए प्रीहोल्ड आधार पर आबंटित रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए)

यह हस्तांतरण विलेख एक पक्षधर के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली के जरिए विक्रेता कहा गया है (इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशी भी हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्य तथा भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो) और दूसरे पक्षधर के रूप में श्री/श्रीमती/मैसर्स..... निवासी..... जिसे इसमें आगे "क्रेता" कहा गया है (इसके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ से अन्य तथा भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो, उसके वारिस, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशी भी शामिल होंगे) के बीच किया गया।

.....में स्थित..... दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र सं० एफ--(.....) / के अधीन रूप..... का प्रतिफल लेकर क्रेता को आबंटित किया गया था जो कि उक्त आबंटन पत्र में उल्लिखित सीमान निबंधनों और शर्तों के अधीन प्राप्त किया गया है और उक्त आबंटन अब भी वैध तथा कायम है और उक्त क्रेता ने विक्रेता को उसे आवंटित की गई उक्त संपत्ति, जिसका वास्तविक कब्जा उन्हें तारीख..... को सौंपा गया था, में प्रीहोल्ड स्वामित्व अधिकारों के लिए अंतरण विलेख निष्पादित करने हेतु आवेदन किया है तथा उसमें आगे दी गई शर्तों व निबंधनों के अधीन उक्त संपत्ति के संबंध में यह विलेख तदनुसार निष्पादित किया जा रहा है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि आवंटन के समय संदत्त..... सं०(शब्दों में.....) की राशि (जिसकी प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरूप, पूर्वोक्त विलेख और यहां इसमें आगे उल्लिखित सीमाओं के अधीन विक्रेता द्वारा आवसीय योजना के प्लॉट सं०..... में उक्त क्रेता प्रीहोल्ड स्वामित्व के लिए अनुदत्त हस्तांतरण, विक्रय, निर्माण और अंतरण, समनुदेशन तथा आशवासन पूर्वोक्त क्रेता को करता है।

1. विक्रेता उक्त संपत्ति में या उसके अन्तर्गत सभी खानों और खनिज पदार्थों को, चाहे वे किसी भी स्वरूप के हों, अपने पास सुरक्षित/रखेगा और इसके साथ-साथ विक्रेता उसके अधिकारियों और कर्मचारों को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वे उक्त संपत्ति के किसी भाग में या सभी जगह तलाशी लेने के लिए, उसे पाने के लिए, विक्रय योग्य बनाने के लिए, उस समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग में किसी भी समय प्रवेश कर सकें और उक्त संपत्ति के अन्तर्गत या उस पर या विक्रेता की भूमि से संलग्न किसी भूमि पर उक्त खानों और खनिज पदार्थों को ले जा सकें तथा उक्त समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग की सतह का और उस संपत्ति के अंतर्गत आने वाले किन्हीं भवनों या उस पर इसके बाद बनाए जाने वाले भवनों का

निर्धारण कर सकें ताकि आदेशानुसार उसकी ओर से किए गए नुकसान के लिए क्रेता को उचित मुआवजा दिया जा सके बशर्ते उक्त संपत्ति के संबंध में भू-राजस्व या देय अन्य करों का भुगतान कर दिया गया हो, जो विधिपूर्ण रूप से उक्त संपत्ति के संबंध में देय हो या देय हो सकते हों, और सभी सार्वजनिक अधिकार या उससे प्रभावित होने वाले भोगाधिकार भी दे दिए गए हों।

2. संपत्ति के इस विलेख के पूरा होते हुए भी, मास्टर प्लान/जोनल विकास प्लान/ले-आउट प्लान के उपबंधों के उल्लंघन की किसी भी प्रकार से अनदेखी नहीं की जाएगी तथा दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-14 या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

3. क्रेता भवन, जल-निकास संबंधी तथा समुचित नगरपालिका या तत्समय प्रवर्त अन्य प्राधिकरणों के उप-नियमों का अनुपालन करेगा।

4. उक्त प्लॉट का आवंटन 'यथावत' आधार पर किया जाता है तथा क्रेता द्वारा इस प्लॉट में अथवा उसके आसपास कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/अतिक्रमण/अवैध निर्माण विक्रेता (डीडीए) की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता जो इस आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं अथवा कुछ शर्तों व निबंधनों के अधीन मंजूर भी कर सकते हैं।

सभी प्रकार के शुल्क, कर, प्रभार, निर्धारण, नगरपालिका अथवा अन्यथा और किसी भी प्रकार के प्रभार को आवंटिती/क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

5. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि इस विलेख को किसी तथ्य को छिपाकर या गलत और गुमराह करने वाले ब्यौरे देकर या कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है तो विक्रेता की ओर से यह विलेख अमान्य हो जाएगा तथा विक्रेता को इस विलेख को रद्द करने तथा क्रेता द्वारा अदा की गई राशि को जप्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में विक्रेता का विनिश्चय अंतिम तथा क्रेता के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी स्थिति में उसे वापस नहीं लिया जाएगा।

6. क्रेता द्वारा आवंटन/नीलामी/निविदा की शर्तों व निबंधनों का अनुपालन किया जाएगा।

7. विक्रेता को आवंटन/नीलामी/निविदा अथवा इस विलेख की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में इस विलेख को रद्द करने का अधिकार होगा।

8. इस लिखत के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रीकरण प्रभार क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

यह हस्तांतरण इस विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रवृत्त माना जाएगा।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

G.S.R. 220(E).— In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 58, read with sub-section (3) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Development Nazul Land) Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Amendment Rules, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, -
 - (i) in sub-rule 1, for the words "body of persons", the words "body of persons, firms, companies," shall be substituted;
 - (ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Authority shall, in conformity with plans and subject to the provisions of these rules, dispose the Nazul land by auction to the following institutions :-

 - a) hospitals;
 - b) dispensaries;
 - c) nursing homes;

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को श्री..... ने अपनी ओर से तथा विक्रेता के आदेश और निर्देश के अनुसार उसके हस्ताक्षर करवाए हैं तथा क्रेता श्री/श्रीमती..... ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है:

आवासीय प्लॉट सं०..... ब्लॉक सं०..... माप.....
वर्ग मी./गज..... के ले-आउट प्लान में है और जो निम्नलिखित प्लॉटों से घिरा है:-

भूखण्ड के उत्तर में..... है।
भूखण्ड के पूर्व में..... है।
भूखण्ड के दक्षिण में..... है।
भूखण्ड के पश्चिम में..... है।

भारत के राष्ट्रपति(विक्रेता) की ओर से तथा उनके आदेश तथा निर्देश के अनुसार श्री/श्रीमती..... ने हस्ताक्षर किए।

(विक्रेता)

1. श्री/श्रीमती..... की उपस्थिति में
श्री/श्रीमती..... ने हस्ताक्षर किए।

(क्रेता)

निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए:-

1. श्री/श्रीमती.....
श्री/श्रीमती.....

[फा. सं. के-20013/4/2006/डीडीवीए]

पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम सं.सा.का.नि. तारीख 28 सितंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं०(1) सा.का.नि. 97 तारीख 27 जनवरी, 1989(2) सा.का.नि. 677(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1991(3) सा.का.नि. 486(अ) तारीख 5 जुलाई, 2002(4) सा.का.नि. 806(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2002 और(5) सा.का.नि. 801(अ) तारीख 9 दिसम्बर, 2004 द्वारा किए गए।

1164 GE/2006-2

- d) higher or technical education institutions;
- e) community halls;
- f) clubs;
- g) schools:

Provided that nothing in this sub-rule shall affect the allotment of land to the Central Government, a State Government, a Union territory and the local body for the said purpose."

3. In the said rules, in rule 5, -

- (i) for the words "The Authority may", the words "Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 4, the Authority may" shall be substituted;
- (ii) the Explanation shall be omitted.

4. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. Save as otherwise provided in sub-rule (2) of rule 4, rules 5, 6 and 7, allotment of Nazul land for any purpose shall be made on payment of such premium as may be determined either by auction or by tender in accordance with the provisions of Chapter III or Chapter IV, as the case may be, of these rules."

5. In the said rules, in rule 16, in the opening paragraph, for the words "individuals, including the following categories of individuals", the words "individuals including the following categories of individuals, companies and firms" shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 20, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that nothing in this rule shall apply to the provisions of sub-rule (2) of rule 4."

7. In the said rules, in rule 42, the following provisions shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in this rule, the Authority may allot Nazul land on free hold basis either through auction or by tender for residential purpose or commercial purpose:

Provided further that in the case of allotment on free hold basis, the allottee shall execute a conveyance deed in Form BA."

8. In the said rules, after Form B, the following form shall be inserted, namely:-

FORM BA

(See rule 42)

CONVEYANCE DEED

(For Residential and Commercial Properties allotted on Freehold basis through Auction or Tender)

This deed of conveyance made on this.....day of..... between President of India, hereinafter called "THE VENDER" through DDA, Vikas Sadan, New Delhi (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successors in office and assigns) of the one part and Shri/Smt/M/S.....R/o

..... hereinafter called "The purchaser" (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his/her heirs, administrators, representatives and permitted assigns) of the other part.

WHEREAS..... situated in was allotted to the purchaser by Delhi Development Authority vide allotment letter No.F() / dated against a consideration of Rs.

.....(Rupees.....) which has been received subject to limitation, terms and conditions mentioned in the said letter of allotment.

AND WHEREAS representing that the said allotment is still valid and subsisting, the said purchaser has applied to the Vendor to execute the Conveyance Deed for free hold ownership rights in the said demised property allotted to him and physical possession whereof has been handed over to him on/...../..... and this deed is being executed accordingly of the said demised property subject to terms and conditions appearing hereinafter.

NOW THIS INDENTURE WITNESSES THAT in consideration of the sum of Rs/- (Rupees) Paid at the time of allotment and Rs (Rupees) was paid before the execution hereof (the receipt whereof the Vendor hereby admits and acknowledges), the aforesaid representation and subject to limitation mentioned hereinafter, the Vendor do hereby grants, conveys, sells, releases and transfers, assigns and assures unto the aforesaid purchaser free hold ownership, in the Scheme..... Plot No

1. The Vendor excepts and reserves unto himself all mines and minerals of whatever nature lying in or under the said property together with full liberty at all times for the Vendor, its agents and workmen, to enter upon all or any part of the property together to search for, win, make merchantable and carry away the said mines, and minerals under or upon the said property or any adjoining lands of the vendor and to lay-down the surface of all or any part of the said property and any building under or hereafter to be erected thereon making fair compensation to the purchaser for damage done unto him thereby, subject to the payment of land revenue or other imposition payable or which may become lawfully payable in respect of the said property and to all public rights or easement affecting the same.
2. That notwithstanding execution of this Deed, use of the property in contravention of the provisions of Master Plan/Zonal Development Plan/Layout plan shall not be deemed to have been condoned in any manner and Delhi Development Authority shall be entitled to take appropriate action for contravention of Section 14 of Delhi Development Act or any other law for the time being in force.
3. The purchaser shall comply with the building, drainage and other byelaws of the appropriate Municipal or other authorities for the time being in force.
4. The said plot is allotted on the basis of 'as is' and the purchaser cannot make any alteration/addition/encroachment/unauthorized construction in or

1164 97/2006-3

around the same without written permission of Vendor (DDA) who may refuse or grant the same subject to such terms and conditions as deems proper.

All fees, taxes, charges, assessments, Municipal or otherwise and other levies of whatsoever nature shall be born by the allottee/purchaser.

5. If it is discovered at any stage that the allotment or this deed has been obtained by suppression of any fact or by any misstatement, misrepresentation or fraud, then this deed shall become void at the option of the vendor, which shall have the right to cancel this deed and forfeit the consideration paid by the purchaser. The decision of the vendor in this regard shall be final and binding upon the purchaser and shall not be called in question in any proceedings.

6. That the purchaser shall abide by the terms and conditions of allotment/auction/tender, which shall be treated as a part of these presents.

7. That the vendor reserves the right to cancel this deed in event of breach of conditions of allotment/auction/tender and of this deed.

8. The stamp duty and registration charges upon this instrument shall be borne by the purchaser.

This transfer shall be deemed to have come into force with effect from the date of registration of the deed.

In witness where of Shri/Smt

.....
For and on behalf of and by the order and direction of the Vendor has hereunto set his/her hand Shri/Smt / M/s the purchaser, the hereunto set his/her hand day and year first above written.

THIS SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

All that in the layout plan of and consisting of sq.mtrs (Courtyard Area) or thereabouts bounded as follows.

NORTH
EAST
SOUTH
WEST

Signed by Shri/Smt.....

.....
for and on behalf of and by the order and direction of the President of India (vendor)

(VENDOR)

In the presence of:

(1) Shri/Smt.....

Signed by Shri/Smt.....

(PURCHASER)

In the presence of:

(1) Shri/Smt.....

(2) Shri/Smt.....

[F. No. K-20013/4/2006/DDVA]

P. K. PRADHAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R 872, dated the 26th September, 1981 and subsequently amended vide number (1) G.S.R. 97, dated the 27th January, 1989, (2) G.S.R. 677 (E), dated the 11th November, 1991, (3) G.S.R. 486(E), dated the 5th July, 2002, (4) G.S.R. 806 (E), dated the 3rd December, 2002, and (5) G.S.R. 801 (E), dated the 9th December, 2004.

अनुलग्नक ख
शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का. आ. 741(अ) :—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 को असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) 'समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है :—

'न्यूनतम 4 हेक्टे. सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर-नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली), द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसाइटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुपेय उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जाएगी।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा प्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन अथवा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाइयों के डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाइयों के धिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध करायी जानी है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारी के फ्रन्ट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी.) उपलब्ध कराया जायेगा।

* सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को तैयार करना :—

(क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्चरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(vii) पार्कों/ग्रीन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल,

दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियाँ, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियाँ पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहाँ भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय

द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा को भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000-डोडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 2006

No. F-1/C. L/Policy/INSITU/Jawahar Nagar/2006/018/616.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, *vide* Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741 (E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for re-development should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) More than 70% of the plots within the area (Industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-Divisional Magistrate Seelam Pur, the Industrial Cluster located at Jawahar Nagar (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May 2005.

A. Boundaries :

East : Balraj Nagar

West : Tunda Nagar

North : Ram Vihar

South : Jauhari Puri

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of re-development plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said Notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to be undersigned.

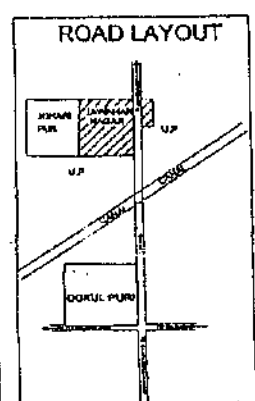
All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the re-development scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development Notification dated the 31st May, 2005 referred to above is Annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

S. C. PODDAR, Secy. and Commissioner (Industries)

JAWAHAR NAGAR

ANNEXURE A



SHIV VIHAR

D. P. SWEN
and Chas. Magnum
(Henderson)
Nash Hotel, Dallas, Tex.

2/8
Gibbs
[Signature]
[Stamp: RECEIVED]
[Text: 100-100000-100000]

RESIDENCE
JAWAHAR NAGAR
U.P

RESIDENCE
JAWAHAR NAGAR
U.P

RESIDENCE -
JAWAHAR NAGAR
U.P

BALRAJ NAGAR
U.P

...RANVEER NAGAR
U.P

RESIDENCE ..
TUNDANAGAR

RESIDENCE

RESIDENCE

KGHAJAN NAGAR

RESIDENCE
(INDIANAPOLIS)
- U.S.

RESIDENCE

RESIDENCE
(JAUHARI PURI)

RESIDENCE
(JAUHARI PURI)

RESIDENCE
(LAUHIAHUA RURI)

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

LEGENDS	
MAIN ROAD	—
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—

ANNEXURE-B
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification No. S. O. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli—Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha. contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions:

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan pollution control and environmental management development of services and parking and maintenance.

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulations shall include—

* Minimum 10% areas is to be reserved for circulation/roads/service lanes.

* Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.

* Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.

* Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.

* Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.

* Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-stations, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms.

* Preparation of:

(a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.

(b) Drainage plan as per norms.

(vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.

(viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme:—

Bungalow Zones (New Delhi and Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation and heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies,

Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges of change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority,

Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDA]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K- 13011/9/2006-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division IB)

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 3 Oct. 2006.

Subject: Extraordinary Gazette Notification regarding Development Control
Norms for residential plotted development.

A copy of Notifications dated 022.9.06 published in the Gazette of India
Extraordinary on the subject cited above are sent herewith for information and
necessary action.

668/AD/me
6/X/06
488-6-104
4/10/06

S. Mukherjee

(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telfax. No. 23061681

Copy to:

- ✓ 1. The Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
2. The Director General, CPWD (Works), Nirman Bhawan, N. Delhi.
3. The Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
4. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
5. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi
Road, New Delhi.
6. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, ITO, New Delhi.
7. The Principal Secretary, (UD), Government of NCT Delhi, O Wing,
Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.

PC-Secy

Com (P/S)

(Separate Copies)

for
files to
all members

DD (Sec) le
6/10

Ad (me)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1115]
No. 1115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2006/भाद्र 31, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2006/BHADRA 31, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

का.आ. 1591(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव था उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 21 जुलाई, 2006 के सं. का.आ. 1160(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) के तहत यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

- यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संगत नियमों के तहत विधिवत गठित जांच बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और प्राधिकरण ने उक्त बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में, उक्त सार्वजनिक सूचना में यथा उल्लिखित संशोधन की, कुछ परिवर्तनों के साथ सिफारिश की है;
- और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी संगत पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ;
- अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन:

दिनांक 23 जुलाई, 1998 के भारत की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा यथा संशोधित दिनांक 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र के अंग्रेजी पाठ के पृष्ठ 159 पर (दायीं तरफ), दिनांक 23 जुलाई, 1998 की उक्त अधिसूचना में निर्धारित मानदण्डों के संशोधन में रिहायशी भूखण्ड विकास(001) के संबंध में निम्नलिखित विकास मानदण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और ये निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन होंगे :-

रिहायशी भूखण्ड विकास(001)

क्र०सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग मीटर) (1)	अधिकतम भूमि कवरेज %	अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)	अधिकतम ऊँचाई मीटर में
1	32 से कम	90(2)	350	15
2	32 से अधिक 50 तक	90(2)	350	15
3	50 से अधिक 100 तक	90(2)	350	15
4	100 से अधिक 250 तक	75(3)	300(3)	15
5	250 से अधिक 500 तक	75	225	15
6	500 से अधिक 1000 तक	50	150	15
7	1000 से अधिक 1500 तक	40	120	15
8	1500 से अधिक 2250 तक	40	120	15
9	2250 से अधिक 3000 तक	40	120	15
10	3000 से अधिक 3750 तक	40	120	15
11	3750 से अधिक	40	120	15

नोट:

- क्षेत्र को वर्ग गज से वर्ग मीटर में परिवर्तित करने से उत्पन्न भूखण्ड आकार में 2% तक की विभिन्नता की अनदेखी करने तथा नीचे दिए गए पैरा (ii) के अनुसार भूखण्ड आकार की निम्नतर श्रेणी के लिए लागू मानदण्डों की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित स्थानीय निकाय सक्षम होगा।
- इस अधिसूचना में दिए गए प्रभावों का भुगतान करने पर इस अधिसूचना की तारीख को पहले से यथा मौजूद निर्माण के नियमितिकरण के लिए 100% भूमि कवरेज किया जा सकता है।
- 100 से 175 वर्ग मीटर तक के आकार के भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना में दिये गए प्रभावों का भुगतान करने पर इस अधिसूचना की तारीख को यथा मौजूद निर्माण के नियमितिकरण के लिए 100 प्रतिशत तल कवरेज और 350 तल क्षेत्र अनुपात पात्र होगा।

शर्तें और निबंधन

- (i) जब तक स्थानीय निकाय द्वारा अवस्थापना और सेवाओं को बढ़ाया नहीं जाता तथा क्षेत्र की ले-आउट योजना और सेवा योजना का तदनुसार उन्नयन नहीं किया जाता, तब तक दिनांक 15 मई, 1995 की अधिसूचना के अन्तर्गत अनुमेय रिहायशी इकाइयों से अधिक किसी अतिरिक्त रिहायशी इकाई की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसलिए, आवेदक, भूखण्ड स्वामी/आवंटी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि दिनांक 15 मई, 1995 की अधिसूचना के तहत अनुमेय रिहायशी इकाई से अधिक कोई अतिरिक्त रिहायशी इकाई सृजित नहीं की गई है अथवा सृजित की जानी है।
- (ii) किसी श्रेणी के किसी भी भूखंड में अनुमेय कुल कवरेज तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) अगली निम्नतर श्रेणी में सबसे बड़े भूखंड के लिए अनुमेय और उपलब्ध, कवरेज तथा तल क्षेत्र अनुपात से कम नहीं होगा।
- (iii) भूखंडों का उप विभाजन अनुमत्य नहीं है। तथापि, यदि एक रिहायशी भूखंड में एकसे अधिक भवन हैं तो निर्मित क्षेत्र तथा सभी ऐसे भवनों के तल कवरेज का योग उस भूखंड में निर्मित क्षेत्र तथा अनुमत्य तल कवरेज से अधिक नहीं होगा।
- (iv) मेजनीन तल तथा सर्विस तल, यदि निर्मित किया गया हो तो उसे तल क्षेत्र अनुपात में गिना जाएगा।
- (v) भूखंड विकास के मामले में यदि बेसमेंट का निर्माण किया गया है तो वह तल क्षेत्र अनुपात में शामिल नहीं होगा। बेसमेंट क्षेत्रफल यथा अनुमत्य और स्वीकृत निर्मित क्षेत्र के अनुसार भूतल पर कवरेज से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन आंतरिक आंगन (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे के क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है।
- (vi) रिहायशी भूखंड के भीतर पार्किंग स्थल निम्नलिखित अनुसार मुहैया कराया जाएगा:-
 क. 250 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में 2 समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)
 ख. 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों में प्रति 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए एक समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)
 बशर्ते कि यदि किसी भूखंड में उपर्युक्त पार्किंग मानदंडों के अनुसार अनुमेय कवरेज और तल क्षेत्र अनुपात नहीं है तो पूर्ववर्ती श्रेणी के पार्किंग मानदंड अनुमत्य होंगे।
- (vii) यदि पार्किंग के लिए प्रयुक्त गैर-निवास योग्य ऊंचाई (2.4 मीटर से कम) के स्टिल क्षेत्र के साथ भवन निर्मित किया गया है तो ऐसे स्टिल क्षेत्र को तल क्षेत्र अनुपात में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि भवन की ऊंचाई के लिए गिना जाएगा।

- (viii) जब तक अन्यथा निर्धारित न किया जाए तब तक न्यूनतम सैटबैक निम्नलिखित सारणी में दिए अनुसार होगा:-

क्र. सं.	भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में)	न्यूनतम सैटबैक (मीटर में)			
		सामने	पृष्ठ	साइड (1)	साइड (2)
1	100 से कम	0	0	0	0
2	100 से अधिक 250 तक	3	0	0	0
3	250 से अधिक 500 तक	3	3	3	0
4	500 से अधिक 2000 तक	6	3	3	3
5	2000 से अधिक 10000 तक	9	6	6	6
6	10000 से अधिक	15	9	9	9

- (क) यदि भूखण्ड में अनुमेय कवरेज उपर्युक्त सैटबैक के साथ नहीं की जाती है तो पूर्ववर्ती श्रेणी के सैटबैक की अनुमति होगी।
- (ख) भविष्य में निर्माण के मामले में 50 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखंड में कम से कम 2 मीटर x 2 मीटर खुले आंगन की व्यवस्था की जाएगी।
- (ix) जो भूखंड स्वामी/आवंटी 23 जुलाई, 1998 की राजपत्र अधिसूचना के अलावा उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त कवरेज, अतिरिक्त फ्लोर अथवा उसका एक भाग बनाना चाहते हैं, उनसे सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अधिसूचित दरों पर सुधार प्रभार (अथवा अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात प्रभार) लिया जाएगा। यह प्रभार दिनांक 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना द्वारा अनुमेय से अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात और दिनांक 15 मई 1996 की अधिसूचना द्वारा अनुमेय अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात के लिए देय प्रभार से अलग होगा।
- (x) जो भूखंड स्वामी /आवंटी इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुमेय अतिरिक्त कवरेज के संबंध में निर्माण नियमित कराना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा (ix) में उल्लिखित सुधार प्रभार के अलावा अर्थदण्ड और सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित प्रशमनकारी (कम्पाउंडिंग) प्रभार का भुगतान करना होगा।
- (xi) जो भूखंड स्वामी /आवंटी इस अधिसूचना के संबंध में अतिरिक्त ऊंचाई नियमित कराना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा (x) में उल्लिखित सुधार प्रभार के अलावा सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित अर्थदण्ड और विशेष प्रशमनकारी (कम्पाउंडिंग) प्रभारों का भुगतान करना होगा।

- (xii) इस प्रकार से प्राप्त राशि संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा एक एस्करो एकाउंट में जमा कराई जाएगी जिसे पार्किंग स्थलों के विकास, सुविधाओं/अवस्थापना को बढ़ाने तथा पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा और इस खाते के आय-व्यय का तिमाही विवरण स्थानीय निकायों द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (xiii) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और स्थानीय निकाय द्वारा अतिरिक्त निर्माण/ऊंचाई के नियमितीकरण के लिए स्वीकृति देने से पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा।
- (xiv) अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात तथा/अथवा ऊंचाई की स्वीकृति अथवा उसे नियमित कराने के इच्छुक प्रत्येक आवेदक को संरचना इंजीनियर से संरचना सुरक्षा का प्रमाणपत्र लेना होगा। यदि इस प्रकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा अन्यथा भवन को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन स्वामी को एक औपचारिक नोटिस दिया जाएगा कि वे एक उचित निर्धारित अवधि में संरचना की कमियों को सुधार लें अन्यथा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा और इसे भवन स्वामी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा गिरा दिया जाएगा।

[सं. के-13011/9/2006-डीडी आईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2006

S.O. 1591(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001, were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1160(E), dated 21st July, 2006 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections and suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

2. Whereas the objections and suggestions received with regard to the proposed modifications were considered by a Board of Enquiry duly constituted by Delhi Development Authority under the relevant rules, and the Authority, after having considered the report of the Board, has recommended the modification of the Master Plan 2001, as envisaged in the said public notice, with certain changes;

3. And whereas, the Central Government has, after carefully considering all relevant aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2001;

2997 G1/2d-2

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi- 2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

On page 159 (RHS) of the Gazette of India dated 1st August 1990, as modified vide Gazette of India Notification dated 23rd July 1998, the following development control norms shall be substituted in respect of Residential Plotted Development (001) in modification of norms laid down in the said Notification dated 23rd July 1998, and subject to the terms and conditions given below:-

Residential Plotted Development (001)

Sl. No.	Area of the plot (sqm) (1)	Maximum ground coverage %	Maximum FAR	Maximum height in metres
1	Below 32	90(2)	350	15
2	Above 32 to 50	90 (2)	350	15
3	Above 50 to 100	90 (2)	350	15
4	Above 100 to 250	75 (3)	300 (3)	15
5	Above 250 to 500	75	225	15
6	Above 500 to 1000	50	150	15
7	Above 1000 to 1500	40	120	15
8	Above 1500 to 2250	40	120	15
9	Above 2250 to 3000	40	120	15
10	Above 3000 to 3750	40	120	15
11	Above 3750	40	120	15

Note:

1. The local body concerned shall be competent to disregard variation of upto 2% in plot size, arising from conversion of area from sq.yard to sqm and to grant the norms applicable to the lower category of plot size in accordance to para (ii) below.
2. 100 % ground coverage shall be eligible for regularization of construction, already existing as on the date of this notification on payment of charges as given in this notification.
3. 100 % ground coverage and 350 FAR shall be eligible for regularization of construction already existing as on the date of this

notification on payment of charges as given in this notification, in respect plot size between 100 to 175 sqm..

Terms and conditions:

- (i) No additional dwelling unit beyond that permissible under notification dated 15th May 1995 shall be permitted, unless the Infrastructure and services have been augmented by the local body and the lay-out plan and services plan of the area have been accordingly upgraded. The applicant plot owner/ allottee shall therefore have to give an undertaking to the effect that no additional dwelling unit has been or is sought to be created beyond that permissible vide notification dated 15th May 1995.
- (ii) The total coverage and FAR permissible in any plot in a category, shall not be less than that permissible and available to the largest plot in the next lower category.
- (iii) Subdivision of plots is not permitted. However, if there are more than one buildings in one residential plot, the sum of the built up area and ground coverage of all such buildings, shall not exceed the built up area and ground coverage permissible in that plot.
- (iv) The mezzanine floor and service floor, if constructed, shall be counted in the FAR.
- (v) Basement in case of plotted development, if constructed, shall not be included in FAR. Basement area shall not extend beyond the coverage on the ground floor as per permissible and sanctioned built up area, but may extend to the area below the internal courtyard and shaft.
- (vi) Parking space shall be provided for within the residential plot as follows:
 - a. 2 Equivalent Car Space (ECS) in plots of size 250-300 sqm;
 - b. 1 ECS for every 100 sqm built up area, in plots exceeding 300 sqmProvided that if the permissible coverage and FAR is not achieved with the above-mentioned parking norms in a plot, the parking norms of the preceding category shall be allowed.
- (vii). If the building is constructed with stilt area of non-habitable height (less than 2.4m), used for parking, such stilt area shall not be included in FAR but would be counted towards the height of the building.

299765/06-3

- (viii) The minimum setbacks shall be as given in the following table unless otherwise prescribed.

S.No.	Plot size (in sqm)	Minimum Setbacks (in metre)			
		Front	Rear	Side (1)	Side (2)
1	Below 100	0	0	0	0
2	Above 100 and upto 250	3	0	0	0
3	Above 250 and upto 500	3	3	3	0
4	Above 500 and upto 2000	6	3	3	3
5	Above 2000 and upto 10000	9	6	6	6
6	Above 10000	15	9	9	9

- a) In case the permissible coverage is not achieved with the above-mentioned setbacks in a plot, the setbacks of the preceding category may be allowed.
- b) In the case of construction in the future, a minimum 2m X 2m open courtyard shall be provided for in residential plots of area of 50sqm to 100 sqm.
- (ix) Plot owners/ allottees seeking extra coverage, additional floor or part thereof, over and above Gazette Notification dated 23rd July 1998, as per above mentioned norms, shall be charged betterment levy (or additional FAR charges) at the rates notified with the approval of the Government, from time to time. This is in addition to the levy payable on the additional FAR allowed vide notification dated 23rd July 1998 and over the FAR allowed vide notification dated 15th May 1995.
- (x) Plot owners/ allottees seeking regularization of construction in terms of the additional coverage allowed under this notification, shall have to pay a penalty and compounding charges notified with the approval of the Government, over and above the betterment levy referred to in para (ix) above.
- (xi) Plot owners / allottees seeking regularization of additional height in terms of this notification, will have to pay penalty and special compounding charges notified with the approval of the Government, in addition to betterment levy referred to in para (x).
- (xii) The amount so collected shall be deposited in an ESCROW ACCOUNT by the local body concerned for incurring expenditure for developing

parking sites, augmentation of amenities/ infrastructure and environmental improvement programmes and a quarterly statement of the income and expenditure of the Account shall be rendered by the local bodies to the Government.

(xiii) Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed first before the local body grants sanction for regularization of additional construction/ height.

(xiv) Every applicant seeking sanction or regularization of additional FAR and / or height shall submit a certificate of structural safety obtained from a structural engineer. Where such certificate is not submitted or the Building is otherwise found to be structurally unsafe, formal notice shall be given to the owner by the local body concerned, to rectify the structural weakness within a reasonable stipulated period, failing which the building shall be declared unsafe by the local body concerned and shall be demolished by the owner or the local body.

[No. K-13011/9/2006-DD IB]
S. MUKHERJEE, Under Secy.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Meeting Cell)

No. F.1(Misc.)2006/MC/DDA/

Dated: 31.10.2006

The Officer on Special Duty to Lt. Governor, Delhi vide his reference dated 27.10.2006 (PUC-Page-1/C) has mentioned that during the discussion in the Authority Meeting on the agenda item pertaining to "Performance Budget", non-official members wanted a Monitoring Committee to be set up in DDA so that all the schemes on quarterly basis would be brought before the said Committee. It was also discussed that non-official members may be part of the Committee.

OSD to LG further mentioned that the Lt. Governor has desired that said Monitoring Committee should be set up within seven days.

A copy of the Resolution passed by the Authority vide Item No. 102/2006 dated 19.10.2006 is as below:

Sub: Performance Budget 2005-06.
F.4(3) Budget/PF/2005-06

The Lt. Governor thanked Shri Mahabal Mishra for his suggestions regarding the presentation of performance Budget in the Authority.

a) Shri Mahabal Mishra started the discussions and expressed concern over shortfall in expenditure against several heads. He sought specific details of activities taken up during the year and non-completion of various projects.

He pointed out that appointment of Consultants for the Common Wealth Games was being delayed for unexplained reasons and the related projects were also thus getting delayed. Shri Mishra advised that all pending decisions should be immediately taken in accordance with the guidelines of the Ministry of Finance and the CVC.

He also sought appointment of a Monitoring Committee to regularly review performance of DDA under different heads of account and for quarterly Performance Budget reviews by the Authority.

b) The Engineer Member gave details of the flats taken up for construction/completed during the years 2005-06 and 2006-07.

c) The Vice Chairman informed that the matter regarding appointment of Consultants for the Common Wealth Games will be discussed by the Committee of Secretaries on 31st October 2006. He assured that all the projects will be completed before the given deadlines.

d) Shri Mange Ram Garg suggested that DDA should compile upto date records of lands under unauthorized encroachment/possession without any further delay. He expressed resentment that letters written by the Authority members were not being replied and there were long delays in completion of various transactions in DDA. He also pointed out that DDA had not removed 260 unauthorized jhuggies inspite of repeated reminders for almost two years.

The Lt. Governor directed immediate action on all the points raised by the members without awaiting formal minutes of the meeting. He assured that separate meetings will be held to review the Budget Performance and appreciated the idea of quarterly reviews by the Authority.

Submitted for consideration and further orders please.

Dy. Director (Parl./MC)

Pr. Commr.-cum-Secretary

Vice Chairman

Asstt. Director (MC) 31/10/06

31/10/06

1852
11/11/06
982-200
31/10/06
982-FM
31/10/06

The monitoring Committee may consist of
Em, CAO, CE (Hqrs), concerned CE/SES. In addition VC
may please nominate one M.A. and one Councillor to the
Committee, who will constitute the non-official representation.

1.11.06

- 1 Mr Mahesh Mishra M.A.
 - 2 Mr Isswar Das M.Councillor
- are nominated.
Suitable orders be issued

Fm
11.11.06

8/11/2006

11-74
6/11/06

DDP/Secy
7/11
10/11/06

696 / AD/Secy
11/11/06

NIWA
DELHI-54

Draft order for constitution of Monitoring Committee on Performance
Budget has been prepared and placed opposite for approval
please.

May kindly advise who will be nominated as Member Secretary.

AD(MC) 10/11/06

Dy. Director (Part. Cell/MC)

Pr. Commr.-cum-Secretary

may kindly see before
it is issued

Finance member is also nominated
For information. Seen.

10/11/06
17/11/06

10/11/2006
10/11/06

16/11/06

VCDDA

17.11.06

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Meeting Cell)

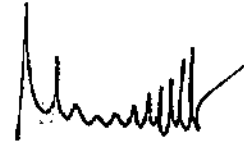
No. F.1(Misc.)2006/MC/DDA/133

Dated: 21st November, 2006

Sub: **Monitoring Committee on Performance Budget.**

A Monitoring Committee consisting of the following is hereby constituted to regularly review the Budget Performance of the DDA under different heads of account:

1. Finance Member
2. Engineer Member
3. Shri Mahabal Mishra, MLA
4. Shri Ishwar Dass, Councillor, MCD
5. Chief Engineer [Head Quarters]
- ✓ 6. Concerned Chief Engineer(s)
7. Chief Accounts Officer – Convener



[V M BANSAL]
Pr. Commr.-cum-Secretary

All Concerned.

Copy to: 1. OSD to Lt. Governor, Delhi.
2. OSD to Vice Chairman, DDA

Dy. Director (Meeting Cell)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

1731 GI/2006

No. 11013 D S 2002-Pol I
Government of India
Ministry of Urban Development

Room No. 335-C, Nirman Bhavan,
New Delhi-110001.

Dated 13th October 2006.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Minutes of the meeting held on 10.10.2006 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Secretary (UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi.

The undersigned is directed to enclose herewith the minutes of the meeting held on 10.10.2006 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Secretary (UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi. for information and necessary action.

(Tapan Mitra)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.2306 1010

1. DG(W), CPWD, Nirman Bhavan
2. Vice Chairman, DDA, *Vice Chairman, DDA, New Delhi*
3. JS(D&L), MoUD.
4. Director of Estates, Nirman Bhavan
5. L&DO, Nirman Bhavan.
6. ADG(TD), CPWD, Nirman Bhavan
7. ADG(Arch), CPWD.

Copy to:

1. Sr. PPS to Secretary(UD).
8. PS to AS(UD), MoUD
9. PA to Director(Works), MoUD

699-AD/MC
10/14/06

I was not present. Circulate to all concerned in DDA

DD

10/11

*Copy to Comm (Plg), Comm (Land)
Dir (Bldg), Dir (Works)*

DD (File) 10/11/06

Minutes of the Meeting held on 10.10.2006 at 11.00 am in the chairmanship of Secretary (UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi.

A meeting regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi was held under the chairmanship of Secretary (UD) on 10.10.2006 at 11.00 am. A List of the participants is enclosed.

At the outset, AS(UD) mentioned about the directions of Cabinet Committee on Accommodation dated 07.03.2002 and 07.01.2004 regarding construction of Office/Residential Complex for Regulatory Authorities and construction of accommodation for Chairpersons and members of Regulatory Authorities in Gurgaon or Noida respectively.

The following decisions were taken :-

1. Actual requirement of office and residential accommodation for the purpose needs to be compiled based on the information available with Directorate of Estates and information furnished by various Ministries. In case some Ministries have not responded, DO letters may be put up to the Secretaries of the concerned Ministries from Secretary (UD) asking them to furnish the details immediately (Action: Director of Estates to draft letters to concerned Secretaries).
2. Regarding the land available at Ghitori, details about land use in the present Master Plan and in the Master Plan 2021, use in Zonal Plan may be intimated at the earliest (Action : DDA)
3. The availability of land for the purpose within Delhi (at Narela, Rohini, Dwarka etc) covering an area of 50 to 75 acres taking into consideration the general suitability for residential and office purposes needs to be identified. The extent of water, sewerage, electricity, drainage, road and metro connectivity and other related infrastructure are to be examined and intimated to Director (Works).

In this context, Secretary (UD) expressed concern about the way the development is being planned at Dwarka. He stressed on the need to have an integrated approach towards development so that residential growth also takes into account the commercial and institutional requirement of the population. This is necessary so that problems now being faced in Delhi may not resurface at Dwarka at a later time. (Action: DDA)

4. Regarding land available at Ghaziabad, Master Plan and Lay Out Plan to be examined and feasibility of having an integrated complex for the purpose be worked out. The proposal should ensure that least inconvenience is caused to the residential complex proposed. In planning for the area, care is to be taken to provide for a quite residential core. Office and Commercial activity be kept on the periphery taking advantage of broaden and busier main roads while isolating the residential heart from becoming a vehicular thoroughfare. While working out details, feasibility of density range within which plot of land will be available should also be taken into account. Secretary also emphasized that while proposing utilization of land for the purpose, development control norms must be kept in view for optimal utilizations. (Action: CPWD)
5. All the above options to be examined with merits/demerits pointed out when the matter is taken up to Cabinet Committee on Accommodation for appropriate orders.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

List of Participants

1. Shri Anil Baijal, Secretary (UD) - in chair
2. Shri S.M. Acharya, AS(UD)
3. Shri M.M. Kutty, JS(D&L)
4. Shri Subhash Kapoor, ADG(Arch.), CPWD
5. Shri Rakesh Kumar, Director (Works).
6. Shri R.K. Sinha, L&DO
7. Shri D. Suresh, Director of Estates
8. Shri V.M. Bansal, Principal Secretary & Commissioner, DDA
9. Shri R.K. Kakkar, Senior Architect (Headquarters -I), CPWD

No. K-13011/1/2004- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 6 February 2007

Subject: Extraordinary Gazette Notification - circulation of
Notification S.O. No. 29(E) dated 10.01.07 regarding change
of land use for Old Police Lines.

A copy of Notification dated 10 January, 2007 published in the
Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary
action.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

To

- ✓ 1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi
12. The Commissioner, Delhi Police, M.S.O Bldg. I.P. Estate, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)

PC & Secy

CIPig

DL

7/2

(Separate copies)

DDP

10/8/2007

AD(MC)

DL

9/2



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]
No. 28]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 2007/पौष 20, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 2007/PAUSA 20, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2007

का.आ. 29(अ).—यतः केन्द्र सरकार का दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2005 की सार्वजनिक सूचना सं. का.आ. 447(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और जिनके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अंदर आमन्त्रित किए गए थे।

2. यतः, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2001 में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

संशोधन

"पुरानी पुलिस लाइन्स, राजपुर रोड में, 7.99 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-उपयोग (मास्टर प्लान, 2001 में)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
पुरानी पुलिस लाइन्स, राजपुर रोड (जोन-सी)	7.99 हेक्टेयर	रिहायशी	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (पुलिस मुख्यालय और पुलिस लाइन्स)	उत्तर : कोर्ट रोड (24 मीटर मार्गाधिकार) दक्षिण : बुलवर्ड रोड (60 मीटर मार्गाधिकार) पूर्व : कोर्ट रोड (24 मीटर मार्गाधिकार) पश्चिम : राजपुर रोड (24 मीटर मार्गाधिकार)"

[सं. के-13011/1/2004-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2007

S.O. 29(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi, 2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 447(E), dated 30th March, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India:

Modification:

"The land use of an area measuring 7.99 ha. at Old Police Lines, Rajpur Road is changed as per description listed below:—

Location	Area (in Ha.)	Land Use (MPD-2001)	Land Use changed to	Boundaries
Old Police Lines, Rajpur Road (Zone C)	7.99 ha.	Residential	Public and semi-public facilities (Police Headquarters and Police Lines).	North : Court Road (24 mtr. R/W) South : Boulevard Road (60 mtr. R/W) East : Court Road (24 mtr. R/W) West : Rajpur Road (24 mtr. R/W)

[No. K-13011/1/2004-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K-13011/1/2004- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 6 February 2007

Subject: Extraordinary Gazette Notification - circulation of
Notification S.O. No. 29(E) dated 10.01.07 regarding change
of land use for Old Police Lines.

A copy of Notification dated 10 January, 2007 published in the
Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary
action.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi
12. The Commissioner, Delhi Police, M.S.O Bldg. I.P. Estate Old Delhi.

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)

57-G-800
7/2/07

36-AD/140
8/2/07

6
7/2
08/2/07
AD (M.C.)

DDA

6
8/2/07



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]
No. 28]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 2007/पौष 20, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 2007/PAUSA 20, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2007

का.आ. 29(अ).—यतः केन्द्र सरकार का दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2005 की सार्वजनिक सूचना सं. का.आ. 447(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और जिनके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अंदर आमन्त्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2001 में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

संशोधन

"पुराना पुलिस लाइन, राजपुर रोड में, 7.99 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :-

स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-उपयोग (मास्टर प्लान, 2001 में)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
पुरानी पुलिस लाइन, राजपुर रोड (जोन-सी)	7.99 हेक्टेयर	रिहायशी	सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (पुलिस मुख्यालय और पुलिस लाइन्स)	उत्तर : कोर्ट रोड (24 मीटर मार्गाधिकार) दक्षिण : बुलबुल रोड (60 मीटर मार्गाधिकार) पूर्व : कोर्ट रोड (24 मीटर मार्गाधिकार) पश्चिम : राजपुर रोड (24 मीटर मार्गाधिकार)"

[सं. के-13011/1/2004-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2007

S.O. 29(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi, 2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 447(E), dated 30th March, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and where the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2001:

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India:

Modification:

"The land use of an area measuring 7.99 ha. at Old Police Lines, Rajpur Road is changed as per description listed below:

Location	Area (in Ha.)	Land Use (MPD-2001)	Land Use changed to	Boundaries
Old Police Lines, Rajpur Road (Zone C)	7.99 ha.	Residential	Public and semi-public facilities (Police Headquarters and Police Lines)	North : Court Road (24 mtr. R/W) South : Boulevard Road (60 mtr. R/W) East : Court Road (24 mtr. R/W) West : Rajpur Road (24 mtr. R/W)

[No. K-13011/1/2001-DDIE]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

By speed post

Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi,
Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi-02

No. F. 10(12)/DG/Env. /2004-2005/ 335-352

Dated: 19/4/2007

To

Vice Chairman, DDA
Vikas Sadan,
Near INA Market,
New Delhi

Sub: Fly Ash Notification - Replacement of the existing one with a new notification - Draft

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the letter no. 9-8/2005-HSMD dated 11th April 2007 of MoEF, GOI regarding the above subject. A copy of the said draft notification is also enclosed.

It is requested to kindly send your comments regarding the draft, if any, to MoEF, GOI within the time stipulated in the draft notification with a copy of the same to this Department.

Yours faithfully,

(Nigam Agarwal)
Scientist (Env.)

Encl.: As above

RM

PC. D. S. Singh
C.I.D.

Mh

20/4

DD Rec 24/4

Secy
24/4/2007

24/4/07

AD (M.C.)

Assn

Please take immediate action at

A

Assn MC / Sh. Sanjiv Kumar

25/4/2007

BY SPEED POST

No.9-8/2005 -HSMD
Government of India
Ministry of Environment and Forests
HSM Division

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodi Road
New Delhi -110 003

Dated: 11th April, 2007

To

Secretary, *(on Election duty)*
Department of Environment,
Government of National Capital Territory, Delhi,
Delhi Secretariat, Indraprastha Estate,
New Delhi -110 002

Subject: Fly Ash Notification - Replacement of the existing one with a
new notification - Draft.

*Mrs N. Agarwal
Scientist*

Sir,

Enclosed please find 10 copies of the above draft notification. Since matter concerns a number of Departments such as Public Works Department, Road Construction Department, Building Construction Department, Local Bodies Department etc, You may like to bring to it to the attention to all concerned. This is only a draft notification and the comments, if any, should reach the Ministry of Environment and Forests, Government of India within the times stipulated in the draft notification.

Yours faithfully,

Encl. As above

R. Anandakumar

(R. Anandakumar)
Adviser

Telephone No.:011-24364592

*L-190/ Secy
76/4/07*



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 833]

No. 833]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2007/आषाढ़ 14, 1929

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2007/ASADHA 14, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2007

का.आ. 1103(अ).—यतः यहाँ नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26 अप्रैल, 2007 की सं.का.आ. 656(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त नहीं हुए तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन :

जोन "डी" में कस्तूरबा गांधी मार्ग (कर्जन रोड) पर 2.328 हेक्टे (5.75 एकड़) माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाए :—

स्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीडी 2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
कस्तूरबा गांधी मार्ग (कर्जन रोड)	2.328 हेक्टे (5.75 एकड़)	रिहायशी	सरकारी कार्यालय	उत्तर - सरकारी भूमि दक्षिण - जसवंत सिंह मार्ग (कॉनिंग लेन) पूर्व - कस्तूरबा गांधी मार्ग (45.72 मी. मार्गाधिकार) पश्चिम - लेडी इरविन स्कूल

[सं. के-13011/1/2007-डीडीबी]

पी. के. सांतारा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2007

S.O. 1103(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 656(E) dated 26th April, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice:

2. Whereas no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India :—

MODIFICATION:

The land use of the following area measuring 2.328 ha. (5.75 acres) at Kasturba Gandhi Marg (Curzon Road) in Zone "D" be changed as per description listed below :

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use Changed	Boundaries
Kasturba Gandhi Marg (Curzon Road)	2.328 ha. (5.75 acres)	Residential	Government Office	North - Government land. South - Jaswant Singh Marg (Canning Lane) East - Kasturba Gandhi Marg (45.72m R/W) West - Lady Irwin School

[No. K-1301 I/1/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

दि. वि. प्र. / संसद एवं समन्वय विभाग
D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
आवृत्ति नं. / DIARY No. 104-6
दिनांक / DATE 5/9/07

No. K-13011/16/2005-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 3rd September, 2007

Subject: **Extraordinary Gazette Notification for change of land use of measuring 4.4 acre at Plot No. 12, Rajpur Road (Zone 'C').**

A copy of Notification dated 2nd August, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

Encl. As above.

(F.K. Santra)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

To

1. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. The Director General of Works, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi
3. The Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
4. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
5. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
7. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
9. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
11. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
12. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi
13. Maj. Gen Nilendra Kumar, AVSM, VSM, Judge Advocate General, Army Headquarters, Sena Bhawan, New Delhi-110011.

डायरी संख्या 321
दिनांक 20.9.07
बैठक कक्षा, दि.वि.प्रा.

Read today
i.e. 20.9.07

② 21/9/07
AD(MC)

DDA 19/9

Please get it pasted in
the Gazette notification register
M. K. Santra
21/9/07

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 955]
No. 955]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2007/श्रावण 11, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 2, 2007/SRAVANA 11, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2007

का.आ. 1351(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 4 जनवरी, 2007 की सा.का.आ. 8(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खंड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

“प्लॉट सं. 12, राजपुरा रोड (जोन 'सी') में 4.4 एकड़ के क्षेत्रफल के निम्नलिखित भू-उपयोग में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है ”:—

क्षेत्रफल का ब्यौरा	क्षेत्रफल एकड़ में	से	में
उत्तर-पश्चिम में मनोरंजक क्षेत्रों, उत्तर-पूर्व में एमसीडी कर्मचारी आवास, दक्षिण-पूर्व में राजपुर रोड और दक्षिण-पश्चिम में एमसीडी कर्मचारी आवास से घिरा।	4.4	“रिहायशी”	‘अधिकतम एफएआर 75 वाली सार्वजनिक और अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं जिसमें (सेना विधि संस्थान) भूमि कवरेज 25 प्रतिशत और ऊंचाई 11 मीटर हो”

[सं. के-13011/16/2005-डी डी आई बी]

पी. के. सांतगा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2007

S.O. 1351(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 8(E), dated 4th January, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

"The land use of the following area measuring 4.4 acre of land at plot no. 12, Rajpur Road (Zone 'C') is changed as per description listed below :—

Description of Area	Area in Acre	From	To
Area bounded by Recreational in the North-West, MCD's Staff Housing in the North-East, Rajpur Road in the South-East and MCD staff housing in the South-West.	4.4	'Residential'	"Public & Semi-Public Facilities (Military Law Institute)" with a maximum FAR of 75, Ground Coverage 25% and Height 11 Mr."

[No. K-13011/16/2005-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION) PUBLIC NOTICE

The following modification which the Delhi Development Authority / Central Government proposes to make to the Master Plan / Zonal Development for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the Principal Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION:

"It is proposed to change the Landuse of an area measuring 2 acres (0.8 Ha) in Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi, in Zone-D bounded by Pocket 9 (Government Use) in the West, Road (20 m R/W) in the East, Deen Dayal Upadhaya Marg (36.58 m R/W) in the South and Kotla Road (30.48 m R/W) in the North from 'Government Office' to 'Public & Semi-Public Facilities'."

The Plan indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Joint Director (MP), 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, Delhi Development Authority, New Delhi, on all working days during the period referred above.

No. F.20(7)2007/MP

Sd/-
V. M. Bansal
Pr. Commr.-cum-Secy.

895568

Sunday Hindustan Times, New Delhi
OCTOBER 7, 2007

9

Website: www.dda.org.in



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION) PUBLIC NOTICE

The following modification which the Delhi Development Authority / Central Government proposes to make to the Master Plan / Zonal Development for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the Principal Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION:

"It is proposed to change the Landuse of an area measuring 2 acres (0.8 Ha) in Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi, in Zone-D bounded by Pocket 9 (Government Use) in the West, Road (20 m R/W) in the East, Deen Dayal Upadhaya Marg (36.58 m R/W) in the South and Kotla Road (30.48 m R/W) in the North from 'Government Office' to 'Public & Semi-Public Facilities'."

The Plan indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Joint Director (MP), 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, Delhi Development Authority, New Delhi, on all working days during the period referred above.

No. F.20(7)2007/MP

Sd/-
V. M. Bansal
Pr. Commr.-cum-Secy.

Visit DDA Website: www.dda.org.in or dial 42895568

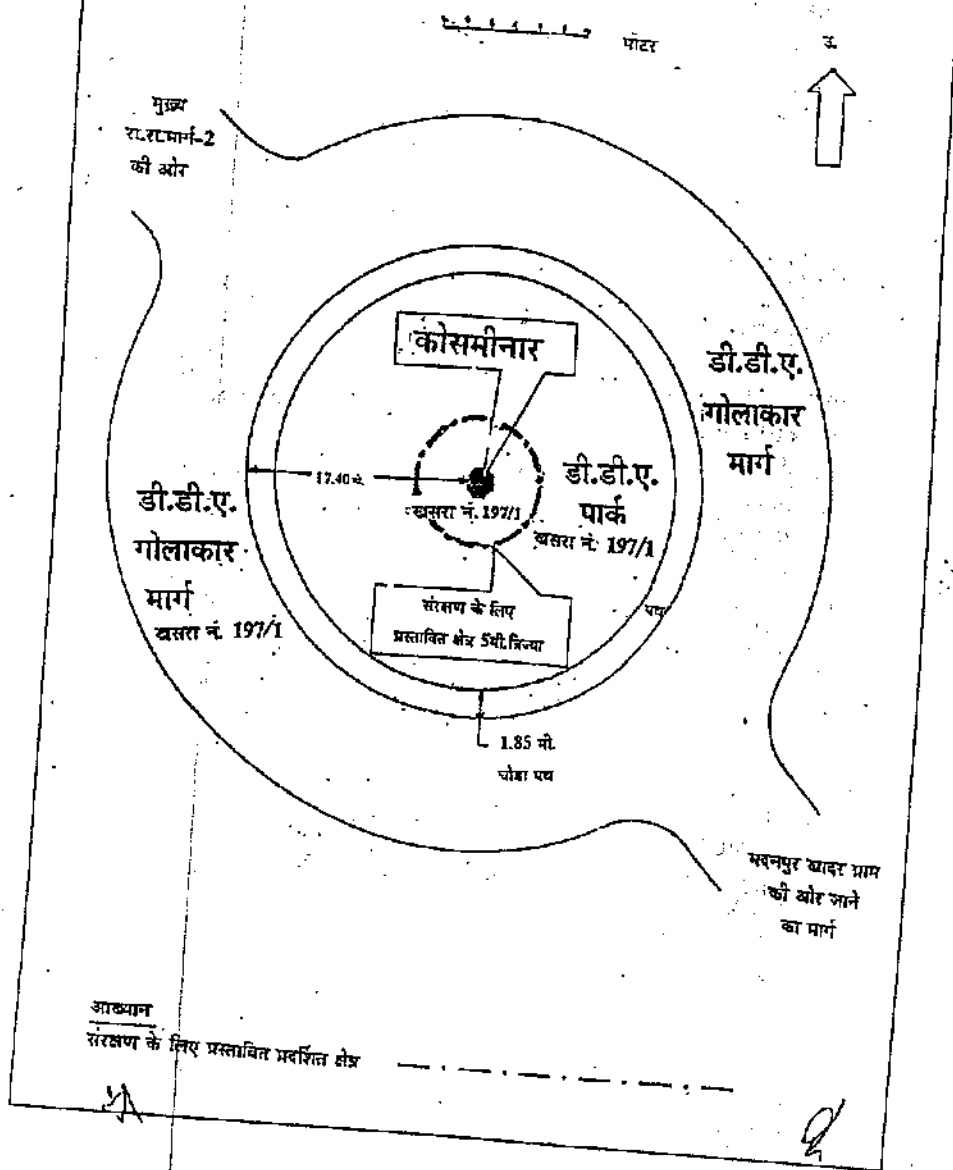
Please keep on record
10/10/07
As (MC) Mehta

shows that the modern Iraqi state is a product of arbitrary boundaries drawn by France and Britain in 1918. This has influenced the outcome of the war. If Indian batsmen feel the surplus in this...

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	इलाका	स्मारक का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	स्वामित्व	सीमाएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दिल्ली	दिल्ली	कोलकाजी	बदरपुर (ग्राम कोटला माहीगिरिम)	कोसमीनार	197/1	78.50 व.मी.	सरकार डी.डी.ए	उत्तर डी.डी.ए. पार्क पूर्व डी.डी.ए. पार्क दक्षिण डी.डी.ए. पार्क पश्चिम डी.डी.ए. पार्क

कोसमीनार, ग्राम कोटला माहीगिरिम (भदनपुर खादर) का स्थल मानचित्र

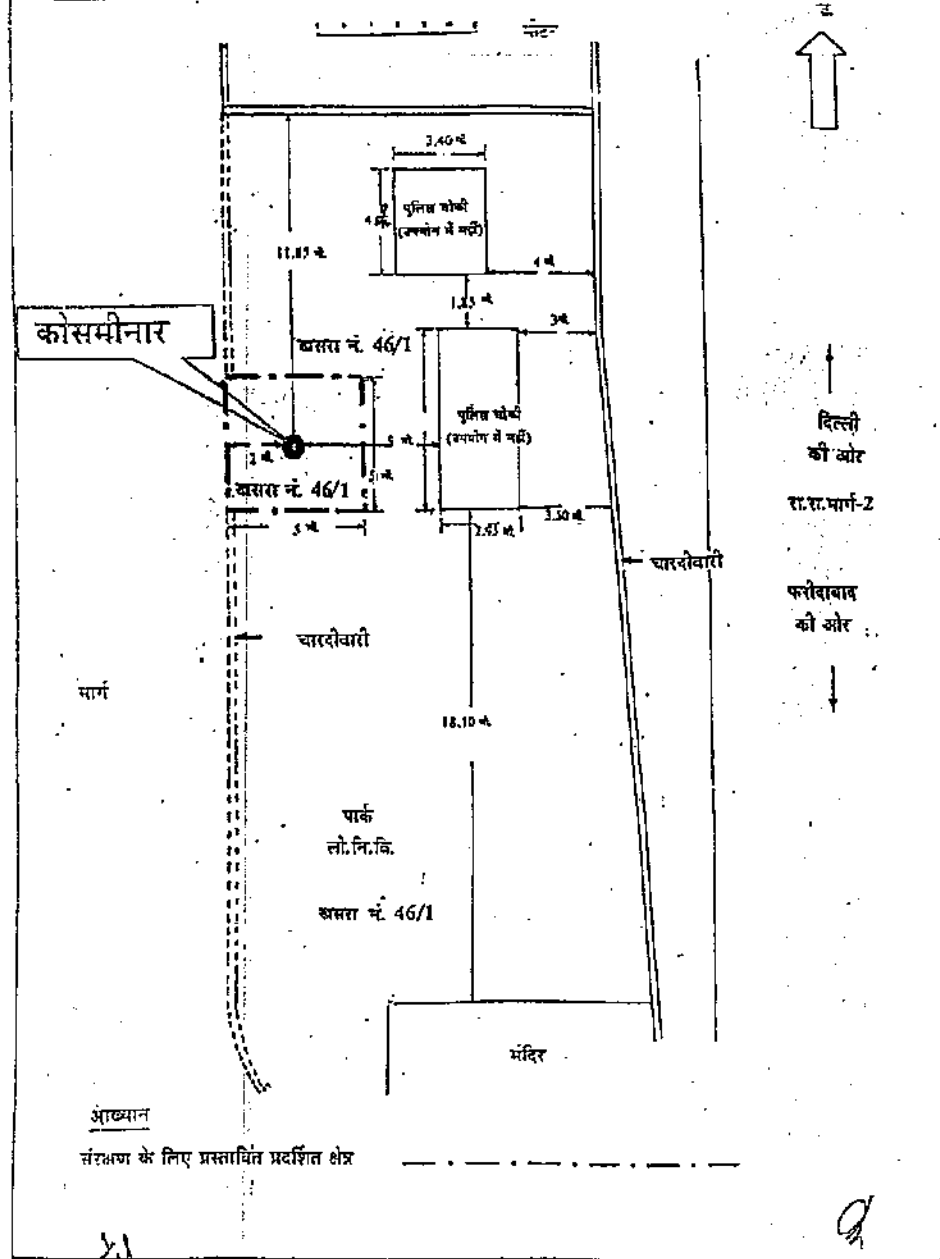


अनुसूची

राज्य	ज़िला	तहसील	इलाका	स्मारक का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	स्वामित्व	सीमाएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दिल्ली	दिल्ली	कालकाजी	बदरपुर (ग्राम ताजपुर)	कोसमीनार	46/1	25 व.मी.	सरकार पी.डी.डी.	उत्तर पार्क पूर्व पार्क दक्षिण पार्क पश्चिम मार्ग

u

कोसमीनार, ग्राम ताजपुल (बदरपुर बाडर) का स्थल मानचित्र



अनुसूची

राज्य	ज़िला	तहसील	इलाका	स्मारक का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	स्वामित्व	सीमाएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दिल्ली	दिल्ली	कासगंजी	बदरपुर	कोसमीनार	27// 12/1/1	55.08 व.मी.	सरकार भू. व. भ.	उत्तर डी.डी.ए. पार्क पूर्व डी.डी.ए. पार्क दक्षिण मार्ग, निर्मित संरचना पश्चिम खुला स्थल अस्थायी ढोचे

४८

कोसमीनार, बदरपुर का स्थल मानचित्र

मॉटर



डी.डी.ए. भूमि व पार्क
अ.अभि.खंड-4

खसरा नं. 27//
12/1/1

6.80 म.

कोसमीनार

8.10 म. खसरा नं. 27//
12/1/1

खुला स्थल
अस्थायी ढाँचों
का उपयोग के लिए

खसरा नं. 27//
12/1/1

खसरा नं. 27//
12/1/1

एम.एस.ग्रिल
चारदीवारी

मार्ग

खसरा नं. 27//
12/1/1

निर्मित संरचना

आख्यान
संरक्षण के लिए प्रस्तावित प्रदर्शित क्षेत्र

25

8

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(पुरातत्व विभाग)**

द्वारा शिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग, गु. गो. सि. इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय परिसर,
कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006

दिनांक 01-11-2007

अधिसूचना

सं.फा.3(25)/2006/मोन् (ii)/ 1231 - जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अधिसूचना सं.फा.3(25)/2006-मोन् (ii)/ 2367 दिनांक 5 सितम्बर, 2006 द्वारा दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्रों तथा अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट संस्मारकों को संरक्षित करने के अपने आशय की अधिसूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपियाँ उक्त संस्मारकों पर एवं इनके निकट सहज दृश्य स्थानों पर चिपका दी गई थी तथा उक्त संस्मारकों में रुचि लेने वाले सभी व्यक्तियों से इनको संरक्षित घोषित करने से संबंधित आपत्तियाँ एवं सुझाव, राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आमंत्रित की गई थी ;

और जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपियाँ 5 सितम्बर, 2006 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबकि इस सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव के लिये जनता से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये ;

अतः अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इसके साथ संलग्न उक्त स्थल मानचित्रों तथा अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट संस्मारकों को संरक्षित घोषित करती है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश तथा नाम पर,

अतिरिक्त सचिव
11/11/07

(आर. एम. पिल्लै)

अतिरिक्त सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

SCHEDULE

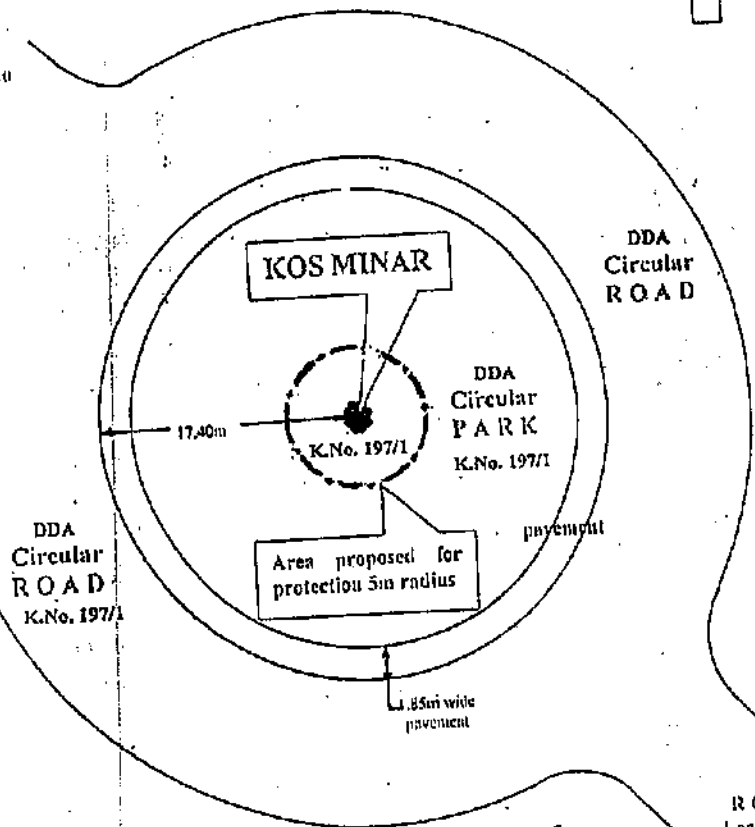
State	District	Tehsil	Locality	Name of the monument	Khasra No.	Area	Ownership	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Delhi	Delhi	Kalkaji	Village Kotla Mahigirim (near Apollo Hospital)	Kos Minar	197/1	78.50 Sq.mt.	Govt. DDA	North: DDA Park East: DDA Park South: DDA Park West: DDA Park

Site Plan for KOS MINAR at Madanpur Khadar (Village Kotla Mahigirim near Apollo Hospital)

Metres



ROAD
Leading to
main
N.H.2



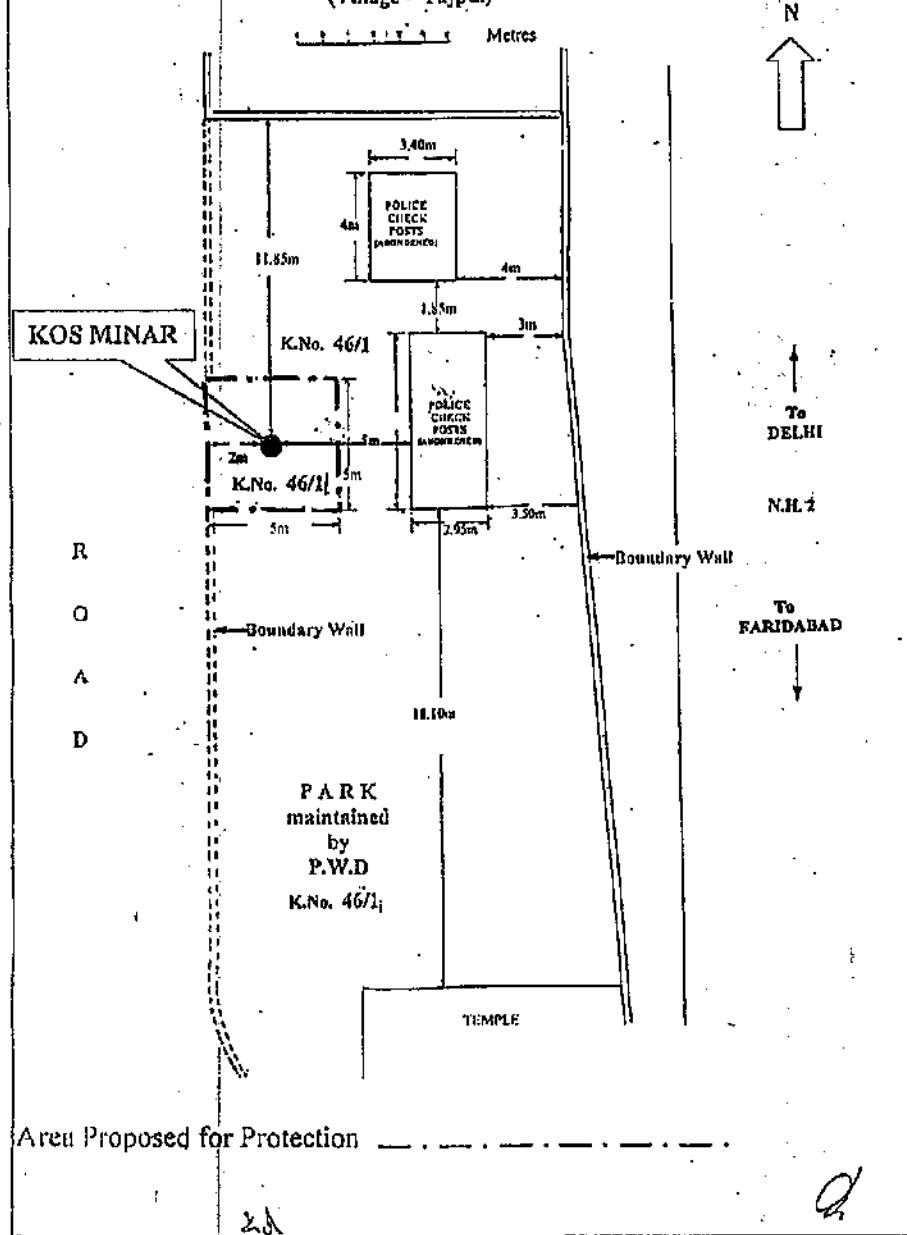
Area Proposed for Protection

Q

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the monument	Khasra No.	Area	Ownership	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Delhi	Delhi	Kalkaji	Badarpur Border (Village Tajpul)	Kos Minar	46/1	25 Sq.mt.	Govt. P.D.D.	North: Park East: Park South: Park West: Road

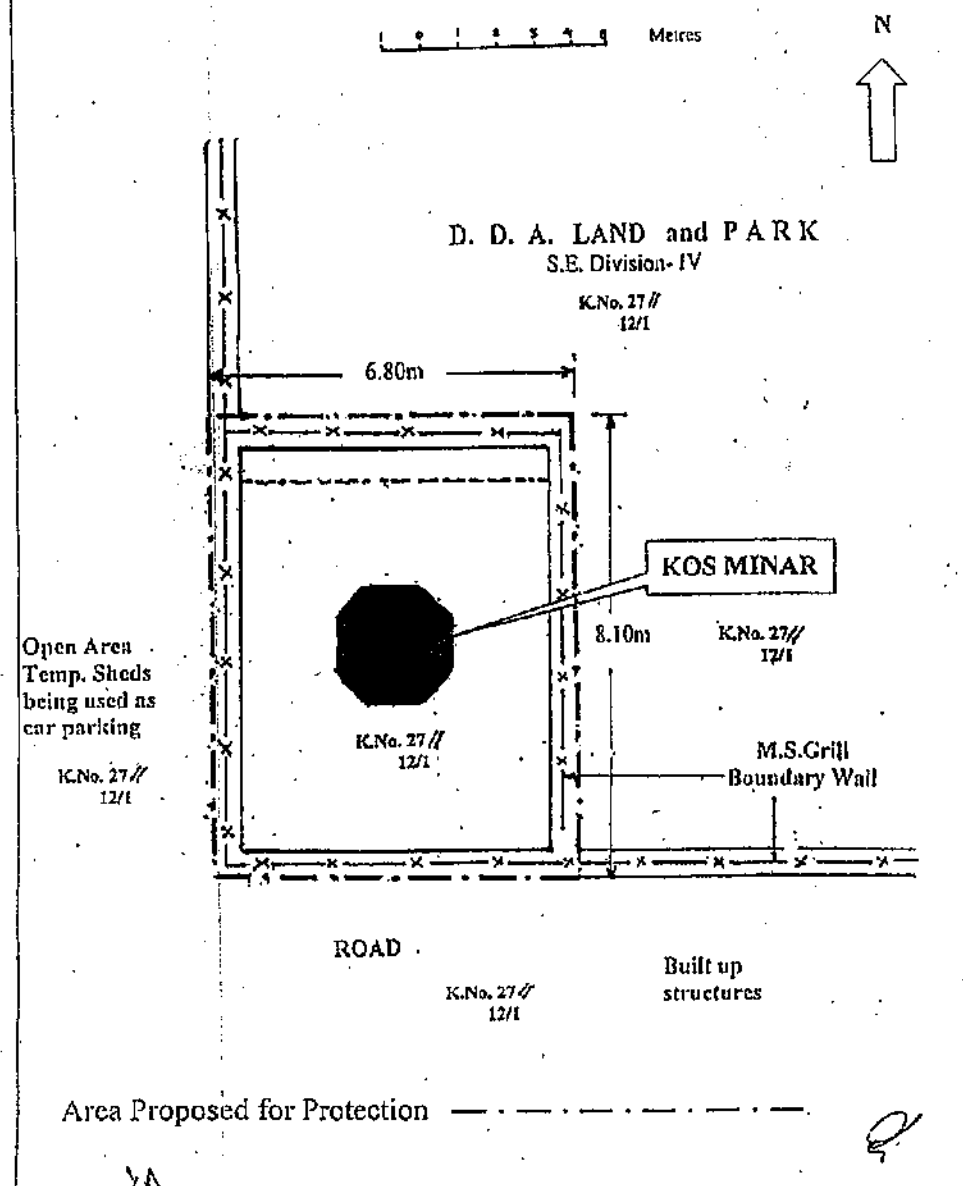
Site Plan for KOS MINAR near Badarpur Border (Village - Tajpul)



SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the Khasra monument No.	Area	Ownership	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Delhi	Delhi	Kalkaji	Badarpur	Kos Minar 27 // 12/1/1	55.08 Sq.mt.	Govt. L & B	North: DDA Park East: DDA Park South: Road, Built up structures West: Open area, Temp. Sheds

Site Plan for KOS MINAR at Badarpur



(TO BE PUBLISHED IN PART - IV OF THE DELHI GAZETTE - EXTRA ORDINARY)

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY)
DARA SHIKOH LIBRARY BUILDING, G.G.S. INDRAPRASTHA UNIVERSITY CAMPUS,
KASHMERE GATE, DELHI-110006.

Dated 01-11-2007

NOTIFICATION

No.F.3 (25)/2006/Monu.(ii)/1231 - Whereas the Government of the National Capital Territory of Delhi vide notification No. F.3(25)/2006/Monu.(ii)/2367 dated the 5th September 2006 issued under sub-section (1) of section 4 of the Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005) notified its intention to declare the monuments specified in the Schedules and the Site Plans annexed thereto, to be protected monuments and the copies of aforesaid notification were affixed in a conspicuous place on and near the said monuments, inviting objections and suggestions from all persons likely to be interested in any such monuments, within a period of two months from the date on which the copies of the Gazette pertaining to the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th September 2006;

And whereas no objection and suggestion has been received from the public to the said proposal by this Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005), the Government of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the monuments specified in the Schedules and Site Plans annexed hereto, to be the protected monuments for the purpose of said Act.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. M. Pillai
11/11/07
(R. M. Pillai)

Additional Secretary (Art, Culture & Language)

अनुसूची

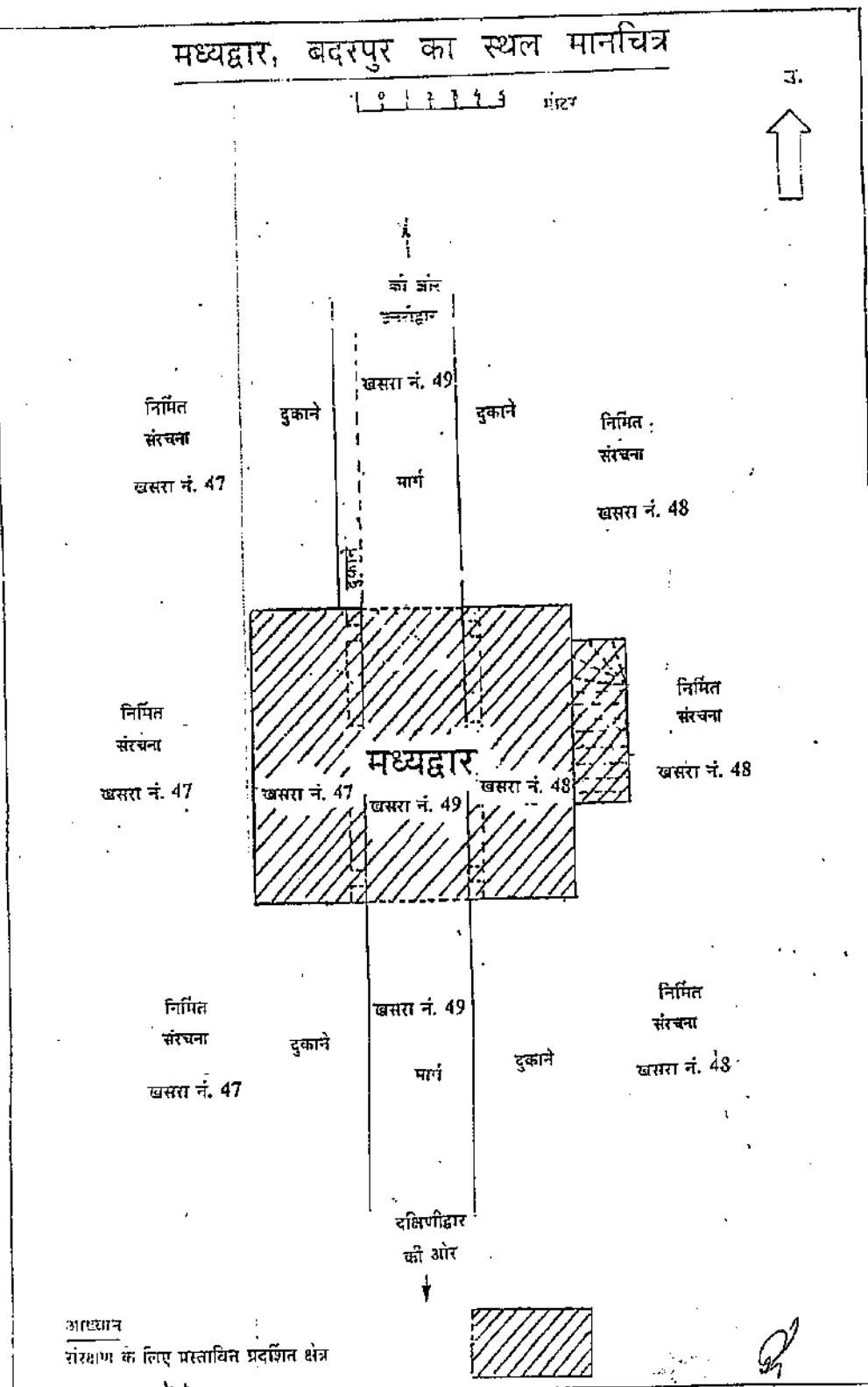
राज्य	ज़िला	तहसील	इलाका	स्मारक का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	स्वामित्व	सीमाएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दिल्ली	दिल्ली	कालकाजी	वदरपुर	दक्षिणीद्वार एवं चारदीवारी अवशेष	47(खण्ड) 48(खण्ड) 49(खण्ड)	328.50 ग्राम सभा व.मी. (गैर-मुपकिन आबादी)	दत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	मार्ग एवं खुला स्थल निर्मित संरचना मार्ग एवं व्यापारिक छोटे निर्मित संरचना
						सरकार दौलतगढ़दार		

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	इलाका	स्मारक का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	स्वामित्व	सोमार्ह	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
दिल्ली	दिल्ली	कातकाजी	बदरपुर	मध्यद्वार	47(खण्ड) 48(खण्ड) 49(खण्ड)	164 व.पी. (गैर-युयकिन जाबादी)	ग्राम सभा (गैर-युयकिन जाबादी)	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	मार्ग निर्मित संरचना मार्ग निर्मित संरचना

मध्यद्वार, बदरपुर का स्थल मानचित्र

1 0 1 2 3 4 5 1525

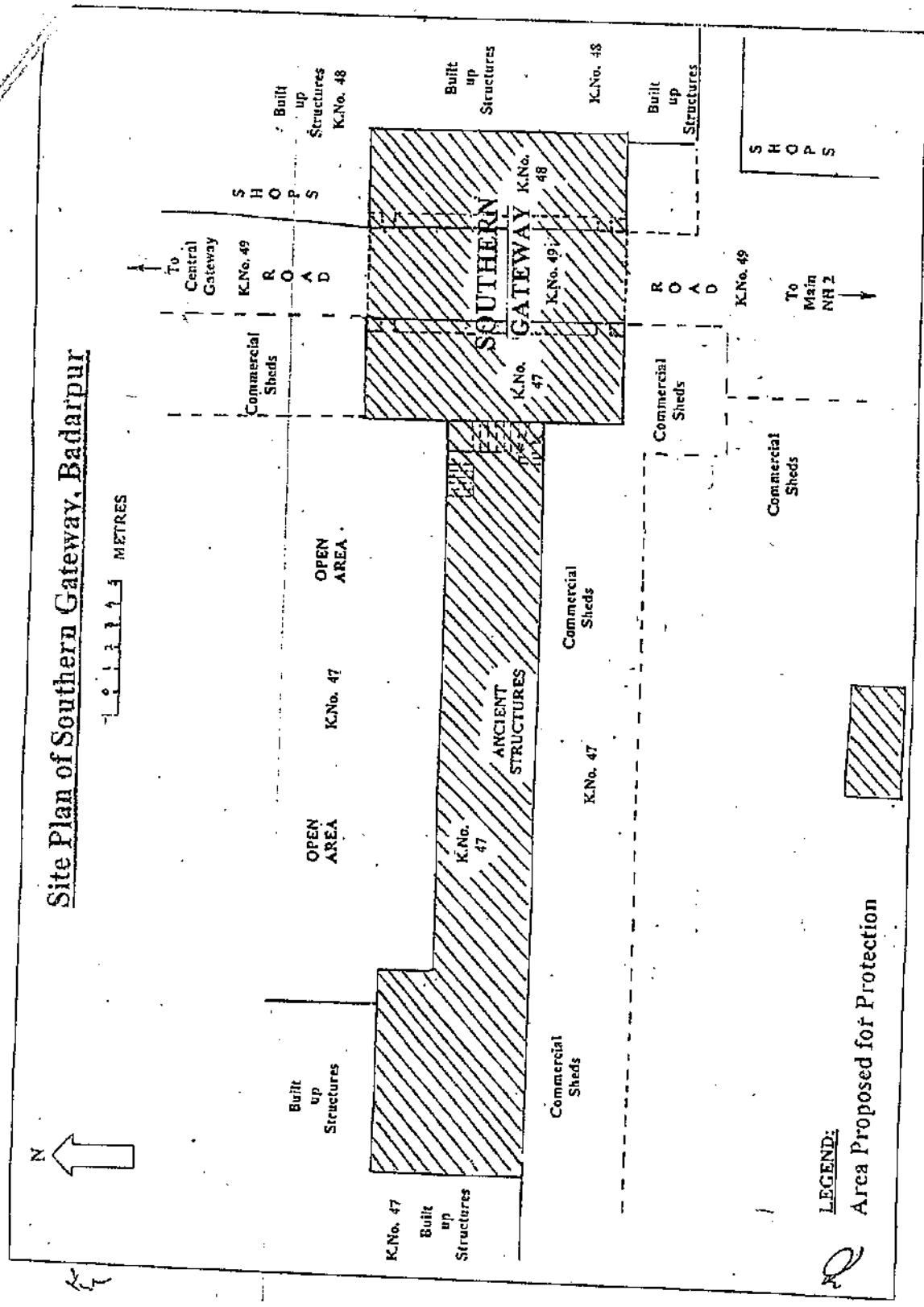


12/11/2014

अनुसूची

राज्य	ज़िला	तहसील	इलाका	स्मारक का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	स्वामित्व	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दिल्ली	दिल्ली	कालकाजी	बदरपुर	उत्तरीहारा	47(खण्ड) 48(खण्ड) 49(खण्ड)	164 व.मौ. (गैर-मुसकिन आबादी) सरकार दोस्तमदार	ग्राम सभा (गैर-मुसकिन आबादी) दक्षिण पश्चिम	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम निर्मित संरचना निर्मित संरचना

५१



15/11/2011

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the monument	Khasra No.	Area	Ownership	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Delhi	Delhi	Kalkaji	Badarpur	Southern Gateway and Enclosure Remains	47(part) 48(part) 49(part)	328.50 Sq.mt.	Gram Sabha (Qair-Mumkin Abadi) Sarkar Daulatmadar (Government)	North: Road & open area East: Built-up structures South: Road & commercial sheds West: Built-up structures

22

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(पुरातत्व विभाग)**

द्वारा शिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग, गु. गो. सि. इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय परिसर,
कश्मीरी गेट, दिल्ली -110006

दिनांक 01.11.2007

अधिसूचना

सं.फा.3(25)/2006-मोनू (i)/ 1230 - जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अधिसूचना सं.फा.3(25)/2006-मोनू (i)/ 2366 दिनांक 5 सितम्बर, 2006 द्वारा दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्रों तथा अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट संस्मारकों को संरक्षित करने के अपने आशय की अधिसूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपियाँ उक्त संस्मारकों पर एवं इनके निकट सहज दृश्य स्थानों पर चिपका दी गई थी तथा उक्त संस्मारकों में रूखि लेने वाले सभी व्यक्तियों से इनको संरक्षित घोषित करने से संबंधित आपत्तियाँ एवं सुझाव, राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आमंत्रित की गई थी ;

और जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपियाँ 5 सितम्बर, 2006 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबकि उक्त प्रस्ताव के लिये जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर इस सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अतः अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इसके साथ संलग्न उक्त स्थल मानचित्रों तथा अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट संस्मारकों को संरक्षित घोषित करती है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा नाम पर,

आर. एम. पिल्ले

(आर. एम. पिल्ले) 1/11/07

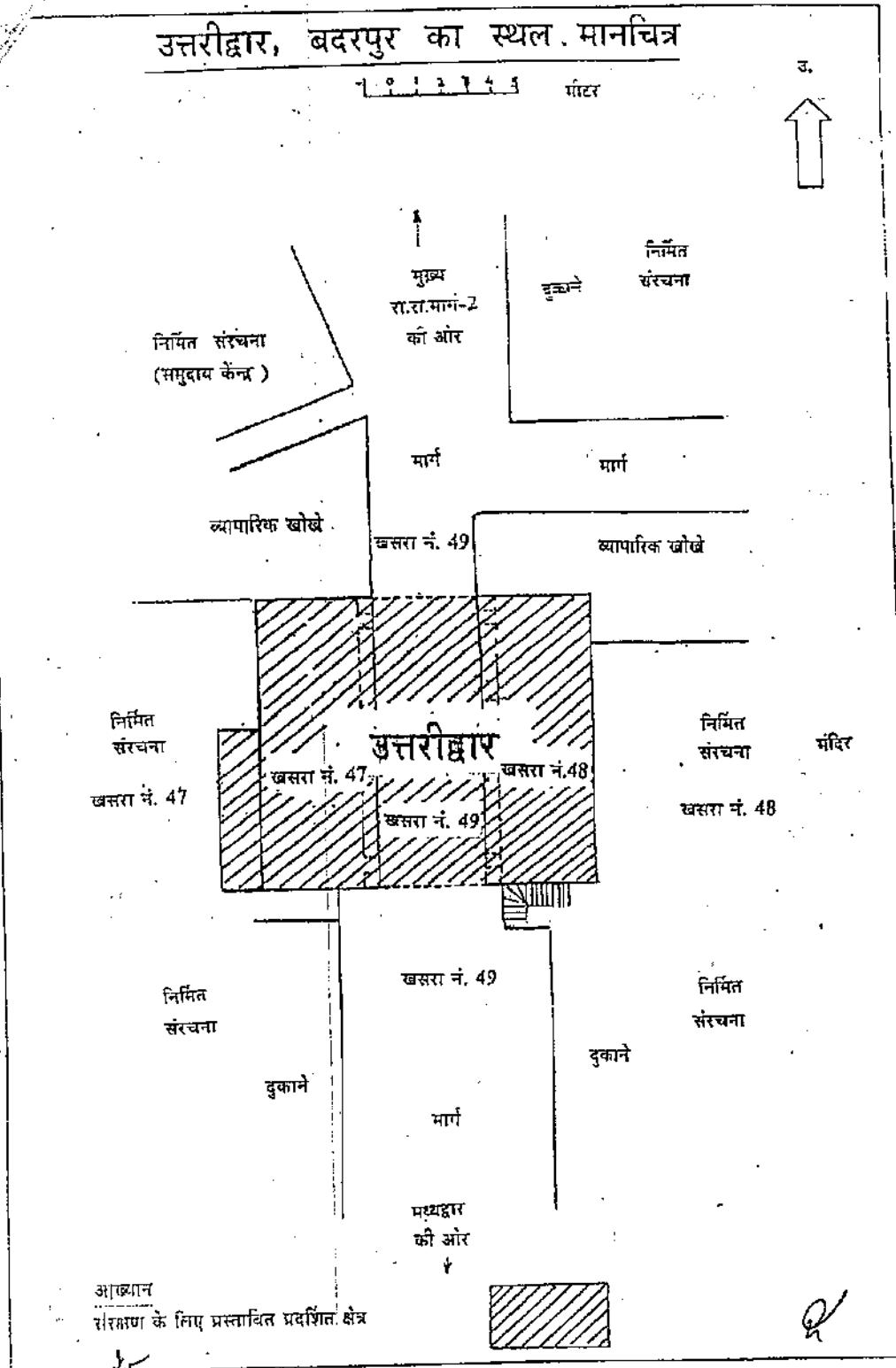
अतिरिक्त सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

12/11/07 12:11 96

उत्तरीद्वार, बदरपुर का स्थल मानचित्र

1 2 3 4 5 मीटर

उ.



दिनांक 24/11/2018

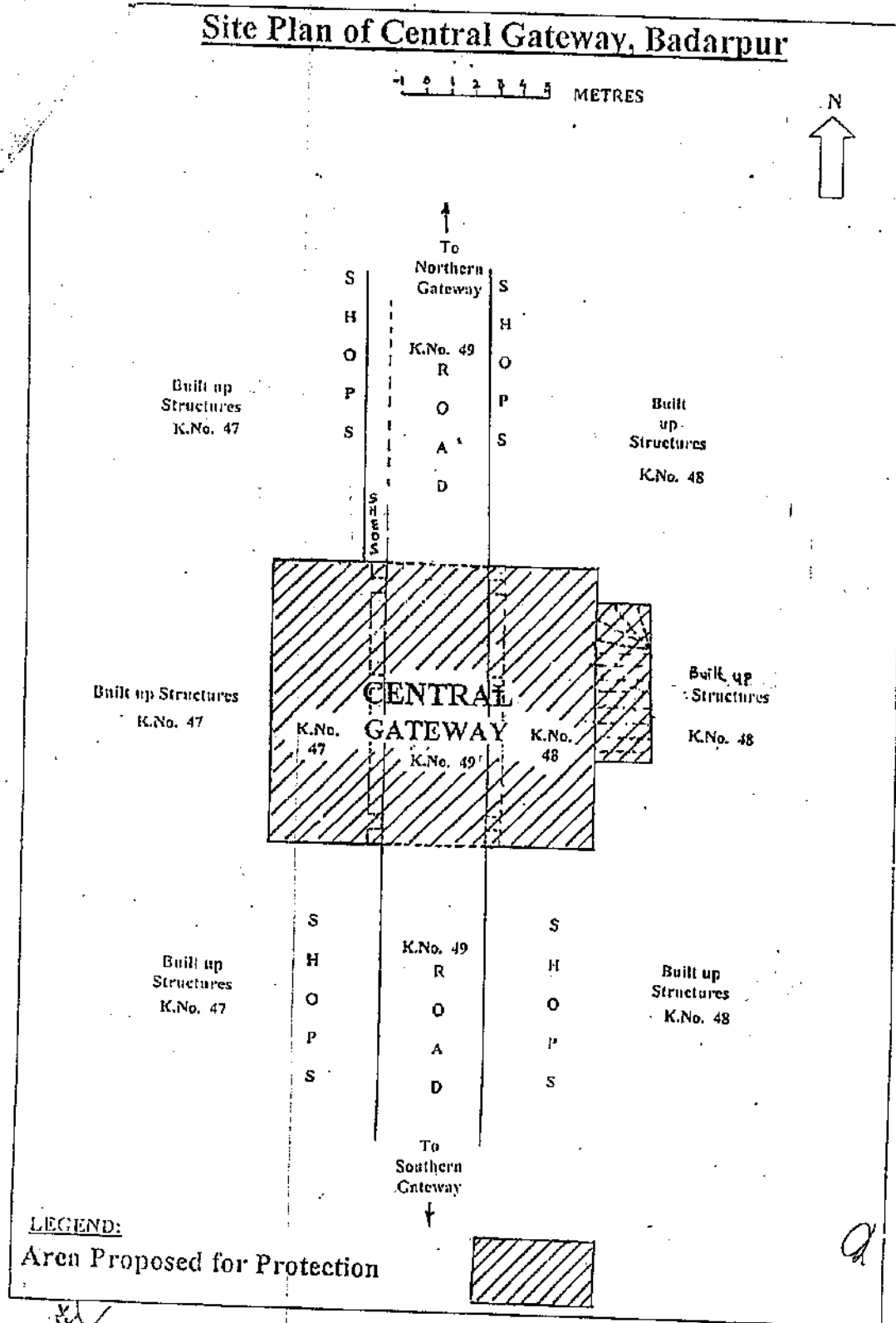
SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the monument	Khasra No.	Area	Ownership	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Delhi	Delhi	Kalkaji	Badarpur	Central Gateway	47(part) 48(part) 49(part)	164 Sq.mt.	Gram Sabha (Gair-Mumkin Abadi) Sarkar Daulatmadar (Government)	North: Road East: Built-up structures South: Road West: Built-up structures

Q

Site Plan of Central Gateway, Badarpur

1 2 3 4 5 METRES



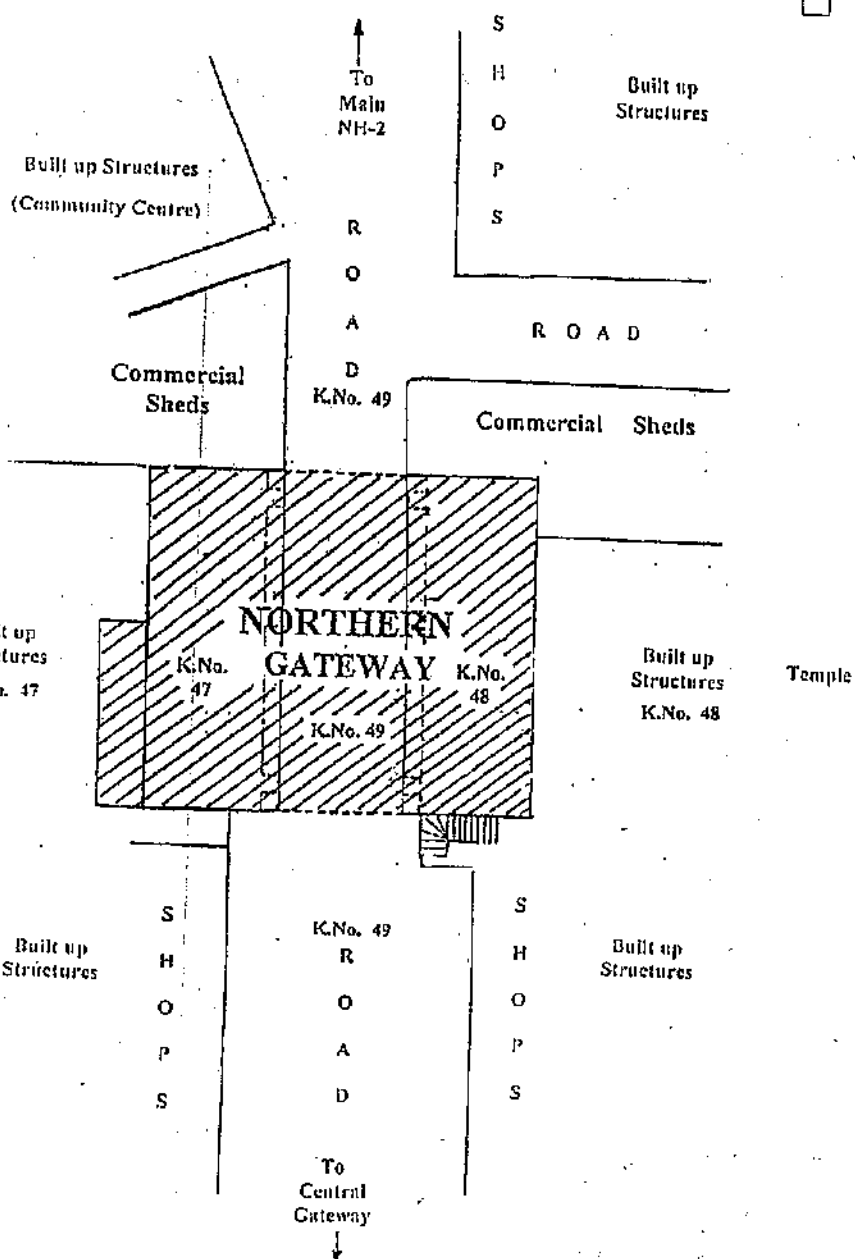
SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the monument	Khasra No.	Area	Ownership	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Delhi	Delhi	Kalkaji	Badarpur	Northern Gateway	47(part) 48(part) 49(part)	164 Sq.mt.	Gram Sabha (Gair-Mumkin Abadi) Sarkar Daulatmadar (Government)	North: Road East: Built-up structures South: Road West: Built-up structures

12

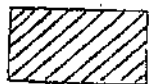
Site Plan of Northern Gateway, Badarpur

0 1 2 3 4 5 METRES



LEGEND:

Area Proposed for Protection



No. 1
Terr
200
and
to
pro
pla
like
on
the
An
the
An
be
No
De
C
de
pr

20

Q

(TO BE PUBLISHED IN PART -IV OF THE DELHI GAZETTE - EXTRA ORDINARY)

**GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY)**
DARA SHIKOH LIBRARY BUILDING, G.G.S. INDRAPRASTHA UNIVERSITY CAMPUS,
KASHMERE GATE, DELHI-110006.

Dated 01.11.2007

NOTIFICATION

No.F.3 (25)/2006/Monu.(i)/ 1230 - Whereas the Government of the National Capital Territory of Delhi vide notification No. F.3(25)/2006/Monu.(i)/2366 dated the 5th September 2006 issued under sub-section (1) of section 4 of the Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005) notified its intention to declare the monuments specified in the Schedules and the Site Plans annexed thereto, to be protected monuments' and the copies of aforesaid notification were affixed in a conspicuous place on and near the said monuments, inviting objections and suggestions from all persons likely to be interested in any such monuments, within a period of two months from the date on which the copies of the Gazette pertaining to the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th September 2006;

And whereas objections and suggestions received from the public to the said proposal have been considered by this Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005), the Government of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the monuments specified in the Schedules and Site Plans annexed hereto, to be the protected monuments for the purpose of said Act.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Rashmi Pillai
(R. M. Pillai)

Additional Secretary (Art, Culture & Language)

Addl. Secretary (Art, Culture & Language)

बैठक कम, दि. वि. प्र.
Meeting Cell, DDA,
डाइरी नं. 438
दिनांक 19.11.07
Date 19.11.07

No. K-13011/12/2007-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 13 November 2007

Subject: Extraordinary Gazette Notification - circulation of Notification S.O.
No. 1907(E) dated 12.11.2007 regarding Land Use Change.

A copy of Notification dated 12th November, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II-Section 3-Sub-section (ii) is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

To

1. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to N&S (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)

PC & Secy.

CPIg

(Separate copies)

Recd today

Copy to paste
in the Notification
register

Meeting Room

19/11/07

19/11/07

ADL

25/11



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1386]
No. 1386]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2007/कार्तिक 21, 1929
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2007/KARTIKA 21, 1929

राष्ट्रीय विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2007

का.आ. 1907(अ).—यतः, यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 को का.आ. 1721(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विचार किया गया तथा यतः, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन :

जोन "डी" में राजज एवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली पर 2 एकड़ (0.8 हेक्टे) माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाए :—

स्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एम पी डी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
राजज एवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	0.8 हेक्टे (2 एकड़)	सरकारी कार्यालय	सरकारी और अर्ध- सरकारी सुविधाएं	पूर्व : सड़क (20 मीटर मार्गाधिकार) पश्चिम : पॉकेट 9 (सरकारी उपयोग) उत्तर : कोटला रोड (30.48 मीटर मार्गाधिकार) दक्षिण : दीनदयाल उपाध्याय मार्ग (36.58 मीटर मार्गाधिकार)

[सं. के-13011/12/2007-डी डी आई बी]

4585 GI/2007

(1)

पी. के. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2007

S.O. 1907(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1721(E) dated 30th October, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modification were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India :—

Modification :

The land use of the following area measuring 2 acres (0.8 ha.) at Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi in Zone "D" be changed as per description listed below :

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use Changed	Boundaries
Rouse Avenue, DDU Marg	0.8 ha. (2 acres)	Government Office	Public and Semi-Public Facilities	East : Road (20 m R/W) West : Pocket 9 (Govt. Use) North : Kotla Road (30.48 m R/W) South : Deen Dayal Upadhaya Marg (36.58 m R/W)

[No. K-13011/12/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

No. K-13011/12/2007-IDDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 13 November 2007

Subject: Extraordinary Gazette Notification – circulation of Notification S.O.
No. 1907(E) dated 12.11.2007 regarding Land Use Change.

A copy of Notification dated 12th November, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II-Section 3-Sub-section (ii) is sent herewith for information and necessary action.

मेटक कक्ष, दि.वि.प्र.
Meeting Cell, D.D.A.

आवृत्ति नं. 136
Diary No. 136
दिनांक 16.11.07
Date 16.11.07

(P.K. Santra)
Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

- To
1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
 2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
 3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
 4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
 5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
 6. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
 7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
 8. The L&DO, Nirman Bhavan, New Delhi.
 9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
 10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
 11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&I)

le
16/11
16/11/07
16/11/07
Meelip Aest

भारत का राजपत्र

The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1386]

No. 1386]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2007/वार्तिक 21, 1929

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2007/KARTIKA 21, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2007

का.आ. 1907(अ).—यतः, यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 को न. का.आ. 1721(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विचार किया गया तथा यतः, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन :

जोन "डी" में राजज एवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली पर 2 एकड़ (0.8 हेक्टे) भाग वाले निम्नलिखित क्षेत्र को भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाए :—

स्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एम पी डी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
राजज एवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	0.8 हेक्टे (2 एकड़)	सरकारी कार्यालय	सरकारी और अर्ध- सरकारी सुविधाएं	पूर्व : सड़क (20 मीटर मार्गाधिकार) पश्चिम : पॉकेट 9 (सरकारी उपयोग) उत्तर : कोटला रोड (30.48 मीटर मार्गाधिकार) दक्षिण : दीनदयाल उपाध्याय मार्ग (36.58 मीटर मार्गाधिकार)

[सं. के-13011/12/2007-डी डी आई बी]

पी. के. सांतोरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2007

S.O. 1907(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1721(E) dated 31st October, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modification were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India :—

Modification :

The land use of the following area measuring 2 acres (0.8 ha.) at Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi in Zone "D" be changed as per description listed below :

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use Changed	Boundaries
Rouse Avenue, DDU Marg	0.8 ha. (2 acres)	Government Office	Public and Semi- Public Facilities	East : Road (20 m R/W) West : Pocket 9 (Govt. Use) North : Kotla Road (30.48 m R/W) South : Deen Dayal Upadhaya Marg (36.58 m R/W)

[No. K-13011/12/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

No. K-12016/6/2003- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the December 5, 2007

Subject: **Extraordinary Gazette Notification- circulation of Notification S.O. No. 1964(A) dated 20.11.2007 regarding Constitution of Heritage Conservation Committee (HCC).**

A copy of Notification dated 20th November, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681/
23061006 /23061478

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)

Copy to E.M., Dir (LS), DDA

11/12/2007

(MC)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1242]
No. 1242]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 12, 2007/आश्विन 20, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2007/ASVINA 20, 1929

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2007

का.आ. 1748(अ).—यतः, यहाँ नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विन्यास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खंड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2006 की सं. का.आ. 2151(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खंड 11-ए के उप-खंड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी ने आपत्तियों/सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खंड 11-ए के उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

"जोन 'ओ' बुलन्द मस्जिद क्षेत्र (शास्त्री पार्क एक्सटेंशन) के 1.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के निम्नलिखित भू-उपयोग में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी- 2021)	भू-उपयोग जिसमें परिवर्तित की गई	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
यमुना नदी तला जोन 'ओ' में बुलन्द मस्जिद क्षेत्र (शास्त्री पार्क एक्सटेंशन) में	1.70 हेक्टेयर	'कृषि एवं जलाशय'	सार्वजनिक व आर्थिक सार्वजनिक सुविधाएं	उत्तर : अ.रो.ब.अ. तथा जी.टी. रोड को जोड़ने वाली नई सड़क दक्षिण : अनाधिकृत निर्मित कालोनी पूर्व : अनाधिकृत निर्मित कालोनी/ 9 मी. चौड़ी प्रस्तावित सड़क पश्चिम : डीएमआरसी भूमि, एचटी लाइन/13.5 मी. चौड़ी प्रस्तावित सड़क

[सं. के-13011/3/2006-डीडीआई-बी]

पी. के. सांत्या, आवर सुचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th October, 2007

S.O. 1748(15).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 2151(15) dated 26th December, 2006 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of an area measuring 1.70 ha. of land in Buland Masjid area (Shastri Park Extension) in Zone 'O' is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buland Masjid area (Shastri Park Extension) in River Yamuna Bed Zone 'O'	1.70 ha.	'Agriculture and Water Body'	Public and semi-public facilities	North : New Road linking ISBT and G.T. Road South : Built-up unauthorised colony East : Built-up unauthorised colony/9M wide proposed Road West : DMRC land, HT Line/13.5M wide proposed Road

[No. K-13011/3/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

No. K-12016/2/2006- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the December 7, 2007

बैठक कम, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell DDA

ख. 471
दि. 11/12/07
Date 11/12/07

Subject: **The National Capital Territory of Delhi Laws
(Special Provisions) Act 2007 (43 of 2007) dated
5.12.2007-**

A copy of above Act published in the Gazette of India
Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)

Under Secretary

Telefax.: 23061681/
23061006 /23061478

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, DMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, UAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS
(D&L)/ Director (UD).

11/12/2007

AD (MC)

Meeting Resor

11/12/2007

DDP

10/12

14/12/07

Copy to BM, RM, PC
CLM & DRR.

DD(P&C)(MC)/Cons

OK



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52]

नई दिल्ली, गुरुवार, दिसम्बर 6, 2007 / अग्रहायण 15, 1929

No. 52] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2007 / AGRAHAYANA 15, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 6th December, 2007/Agrahayana 15, 1929 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 5th December, 2007, and is hereby published for general information:—

THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2007

No. 43 of 2007

[5th December, 2007]

An Act to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to 31st December, 2008 and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS there had been phenomenal increase in the population of the National Capital Territory of Delhi owing to migration and other factors resulting in tremendous pressure on land and infrastructure leading to encroachment or unauthorised developments which are not in consonance with the concept of planned development as provided in the Master Plan of Delhi, 2001 and the relevant Acts and building bye-laws made thereunder;

AND WHEREAS the Master Plan of Delhi, 2001 has been extensively modified and notified by the Central Government on 7th February, 2007 with the perspective for the year 2021 keeping in view the emerging new dimensions in urban development vis-a-vis the social,

financial and other ground realities;

AND WHEREAS the Master Plan of Delhi with the perspective for the year 2021 specifically provides for strategies for housing for urban poor as well as to deal with the informal sector;

AND WHEREAS a revised policy for relocation and rehabilitation of slum dwellers in the National Capital Territory of Delhi is also under consideration of the Central Government;

AND WHEREAS a strategy and a scheme has been prepared by the local authorities in the National Capital Territory of Delhi for regulation of urban street vendors in accordance with the National Policy for Urban Street Vendors and the Master Plan for Delhi, 2021;

AND WHEREAS some time is required for making orderly arrangements in accordance with the revised policy for relocation and rehabilitation of slum dwellers of Delhi as well as for putting in place the scheme for regulation of urban street vendors in terms of the Master Plan of Delhi, 2021 and also the national policy in this regard;

AND WHEREAS the Central Government has considered and finalised a policy regarding regularisation of unauthorised colonies, village *abadi* area and its extension, as existed on the 31st day of March, 2002 for which the guidelines are being framed;

AND WHEREAS the Central Government require time to take a considered view on the policy regarding existing farm houses involving construction beyond permissible building limits and regarding schools, dispensaries, religious institutions and cultural institutions, storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land, *inter alia*, in the light of recommendations of the Expert Committees constituted by the Central Government in the year 2006;

AND WHEREAS the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Ordinance, 2007 for making special provisions for the areas of the National Capital Territory of Delhi for a further period of one year promulgated on 4th July, 2007 will cease to operate from the 21st day of September, 2007; Ord. 6 of 2007.

AND WHEREAS the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2007 introduced in Parliament to replace the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Ordinance, 2007 could not be taken up for consideration and passing since Parliament adjourned *sine die*; Ord. 6 of 2007.

AND WHEREAS it is expedient to have a law in terms of the Master Plan of Delhi, 2021, in continuation of the said Act for a period up to 31st December, 2008 to provide temporary relief and to minimise avoidable hardships and irreparable loss to the people of the National Capital Territory of Delhi against any action by the concerned agency in respect of persons covered by the policies referred to above which are expected to be finalised within the period so extended;

Be it enacted by Parliament in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007.

(2) It extends to the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 19th day of May, 2007.

(4) It shall cease to have effect on the 31st day of December, 2008 except as respects things done or omitted to be done before such cesser, and upon such cesser section 6 of the General Clauses Act, 1897, shall apply as if this Act had then been repealed by a Central Act. 10 of 1897.

Short title,
extent,
commence-
ment and
duration.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "building bye-laws" means bye-laws made under section 481 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 or the bye-laws made under section 138, sub-section 61 of 1957.

Punjab Act 3 of
1911.

61 of 1957.

(3) of section 189 and sub-section (1) of section 190 of the Punjab Municipal Act, 1911, as in force in New Delhi or the regulations made under sub-section (1) of section 57 of the Delhi Development Act, 1957, relating to buildings;

66 of 1957.

(b) "Delhi" means the entire area of the National Capital Territory of Delhi except the Delhi Cantonment as defined in clause (11) of section 2 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957;

(c) "encroachment" means unauthorised occupation of Government land or public land by way of putting temporary, semi-permanent or permanent structure for residential use or commercial use or any other use;

66 of 1957.

44 of 1994.

61 of 1957.

(d) "local authority" means the Delhi Municipal Corporation established under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, or the New Delhi Municipal Council established under the New Delhi Municipal Council Act, 1994, or the Delhi Development Authority established under the Delhi Development Act, 1957, legally entitled to exercise control in respect of the areas under their respective jurisdiction;

61 of 1957.

(e) "Master Plan" means the Master Plan for Delhi with the perspective for the year 2021 notified, *vide* the notification number S.O.141(E), dated 7th February, 2007 under the Delhi Development Act, 1957;

(f) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(g) "punitive action" means action taken by a local authority under the relevant law against unauthorised development and shall include demolition, sealing of premises and displacement of persons or their business establishment from their existing location, whether in pursuance of court orders or otherwise;

61 of 1957.

(h) "relevant law" means in case of—

66 of 1957.

44 of 1994.

(i) the Delhi Development Authority, the Delhi Development Act, 1957;

(ii) the Municipal Corporation of Delhi, the Delhi Municipal Corporation Act, 1957; and

(iii) the New Delhi Municipal Council, the New Delhi Municipal Council Act, 1994;

(i) "unauthorised development" means use of land or use of building or construction of building or development of colonies, village *abadi* area and its extension, carried out in contravention of the sanctioned plans or without obtaining the sanction of plans, or in contravention of the land use as permitted under the Master Plan or Zonal Plan or layout plan, as the case may be, and includes any encroachment.

61 of 1957.

66 of 1957.

44 of 1994.

(2) The words and expressions used but not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and the New Delhi Municipal Council Act, 1994.

3. (1) Notwithstanding anything contained in any relevant law or any rules, regulations or bye-laws made thereunder, the Central Government shall before the expiry of this Act, take all possible measures to finalise norms, policy guidelines and feasible strategies to deal with the problem of encroachment or unauthorised development in the form of encroachment by slum dwellers and *Jhuggi-Jhopri* clusters, hawkers and urban street vendors, unauthorised colonies, village *abadi* area and its extension, existing farm houses involving construction beyond permissible building limits and schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions, storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land, as mentioned below;

Enforcement
to be kept in
abeyance.

(a) policy for relocation and rehabilitation of slum dwellers and *Jhuggi-Jhopri* clusters in accordance with provisions of the Master Plan of Delhi, 2021 to ensure development of Delhi in a sustainable, planned and humane manner;

(b) strategy for regulation of urban street vendors in consonance with the national policy for urban street vendors and hawkers as provided in the Master Plan of Delhi, 2021;

(c) scheme containing guidelines for regularisation of unauthorised colonies, village *abadi* area and its extension, as existed on the 31st day of March, 2002, and where construction took place even beyond that date and up to the 8th day of February, 2007;

(d) policy regarding existing farm houses involving construction beyond permissible building limits; and

(e) policy regarding schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions, storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land.

(2) Subject to the provisions contained in sub-section (1) and notwithstanding any judgment, decree or order of any court, *status quo* —

(i) as on the 1st day of January, 2006 in respect of encroachment or unauthorised development; and

(ii) in respect of unauthorised colonies, village *abadi* area and its extension, which existed on the 31st day of March, 2002 and where construction took place even beyond that date and up to the 8th day of February, 2007, mentioned in sub-section (1),

shall be maintained.

(3) All notices issued by any local authority for initiating action against encroachment or unauthorised development referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been suspended and no punitive action shall be taken till the 31st day of December, 2008.

(4) Notwithstanding any other provision contained in this Act, the Central Government may, at any time before the 31st day of December, 2008, withdraw the exemption by notification in respect of encroachment or unauthorised development mentioned in sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be.

Provisions of this Act not to apply in certain cases.

4. During the period of operation of this Act, no relief shall be available under the provisions of section 3 in respect of the following encroachment or unauthorised development, namely:—

(a) encroachment on public land except in those cases which are covered under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of section 3;

(b) removal of slums and *Jhuggi-Jhopri* dwellers, hawkers and urban street vendors, unauthorised colonies or part thereof, village *abadi* area and its extension, in accordance with the relevant policies approved by the Central Government for clearance of land required for specific public projects.

Power of Central Government to give directions.

5. The Central Government may, from time to time, issue such directions to the local authorities as it may deem fit, for giving effect to the provisions of this Act and it shall be the duty of the local authorities to comply with such directions.

Repeal and savings.

6. (1) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Ordinance, 2007 is hereby repealed.

Ord. 7 of 2007.

Ord. 7 of
2007.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Ordinance, 2007, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

K.N. CHATURVEDI,
Secy. to the Govt. of India

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI—2007.

MGIPMRND—5268UD(GI)(S-1)—06-12-2007.

11/12/2007

DD(P&C)(MO)/G.S. 25/12/07



No. K-20014/2/2007-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 09th January, 2008

To

The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023

[Attention: Shri Prahlad Singh, Director (LC)]F

Sub: Cost Benefit Analysis (CBA) of Narela and determination of pre-determined rates for various land uses in Narela project for the year 2007-2008.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F.4(23)06/AO(P)/DDA/47 dated 11.7.2007, on the subject noted above, and to enclose a copy of the Notification regarding pre-determined rates for various land uses in Narela for information and further necessary action.

Encl.: As above

Yours faithfully,

(S.N. GUPTA)
Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Copy along with a copy of Notification to the DDA [Member (Finance)/Principal Commissioner-cum-Secretary/Commissioner (LD)], Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt. of India

RECEIVED
D.D.A. / PABLI. & CO-ORDIN. BRANCH
10-1-08

27-6-08
97/108

RECEIVED
Cell, D.D.A.
41

10.1.108

DDA 10/1
10/1/08
AD (M.S.)

M. celip Asst
10/1/2008

(भारत के राजपत्र के भाग-1। खण्ड 3 उपखण्ड(I)में प्रकाशनार्थ)

सं० 20014/2/2007-डीडी।ए

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
00000

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: ०९.०१.२००८

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं..... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

भूमि की श्रेणी	2007-2008 के लिए नरेला के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी०)
1. सीजीएस के लिए भूमि	7602.00
2. वैकल्पिक भूखंड	6108.00 रु० (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल हैं)
3. डीडीए आवासीय स्कीम	
(क) एसएफएस	7602.00 रु०
(ख) एमआईजी	6335.00 रु०
(ग) एलआईजी	3801.00 रु०
(घ) ईडब्ल्यूएस	2534.00 रु० (फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाय)
4. जे०जे० स्क्वेटर्स (पुनर्वास)	22.90 लाख रु० प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी हैं।

ए। म. नाथ
(एस०एन० गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली।



[To be published in Gazette of India,
Part II-Section 3-sub-Section (i)]

No.K-20014/2/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 09th January, 2008

Notification

G.S.R. No. _____ In exercise of powers conferred by Rule 2(i) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under :-

Category of Land	Approved pre-determined rates for Narela for 2007-2008 (per sq. mtr.)
1. Land for CGHS	Rs. 7602.00
2. Alternative Plots	Rs. 6108.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
3. DDA Housing Schemes	
(a) SFS	Rs. 7602.00
(b) MIG	Rs. 6335.00
(c) LIG	Rs. 3801.00
(d) EWS	Rs. 2534.00
	(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
4. J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 22.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.

(S.N. Gupta)

Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064



[To be published in Gazette of India -
Part II-Section 3-Sub-section (i)]

No.K-20014/3/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 09th January, 2008

NOTIFICATION

G.S.R. No. _____ In exercise of powers conferred by Rule 2(i) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under: -

Category of Land	Approved pre-determined rates for Rohini Phase IV & V for 2007-2008 (per sq. mtr.)
1. Rohini Plots	
(a) EWS 26 sqm.	Rs. 4905.00
(b) LIG 32 sqm.	Rs. 6193.00
(c) MIG 60 sqm.	Rs. 10058.00
	(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
2. Housing Scheme	
(a) EWS	Rs. 2577.00
(b) LIG	Rs. 3865.00
(c) MIG	Rs. 6441.00
(d) SFS	Rs. 7730.00
	(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
3. Alternative Plots	Rs. 6193.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
4. Land for CGHS	Rs. 7730.00
5. J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 22.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.


(S.N. Gupta)

Under Secretary to the Govt. of India

To
The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064



No. K-20014/3/2007-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 09th January, 2008

To

The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023

[Attention: Shri Prahlad Singh, Director(LC)]

Sub: Cost Benefit Analysis of Rohini Phase IV & V and determination of pre-determined rates for various land uses in Rohini Phase IV & V project for the year 2006-2007.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F.4(25)06/AO(P)/DDA/49, dated the 11.7.2007, on the subject noted above, and to enclose a copy of the Notification regarding pre-determined rates for various land uses in Rohini Phase IV & V for information and further necessary action.

Encl.: As above

Yours faithfully,

(S.N. GUPTA)

Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Copy along with a copy of Notification to the DDA [Member (Finance)/Principal Commissioner-cum-Secretary/Commissioner (LD)], Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt. of India

DDA 9/1
10/1/08
AD(MC)
M Asst
10/1/2008

(भारत के राजपत्र के भाग-III खण्ड 3 उपखण्ड(i) में प्रकाशनाथ)

सं० 20014/3/2007-डीडी।।ए

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
00000

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं..... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

भूमि की श्रेणी

2007-2008 के लिए रोहिणी फेज-IV एवं V के लिए
अनुमोदित पूर्व निर्धारित दर
(प्रति वर्ग मी०)

1. रोहिणी प्लॉट

- (क) ईडब्ल्यूएस 26 वर्गमी०
(ख) एलआईजी 32 वर्गमी०
(ग) एमआईजी 60 वर्गमी०

4905.00 रु०
6193.00 रु०
10058.00 रु०
(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)

3. आवासीय स्कीम

- (क) ईडब्ल्यूएस
(ख) एलआईजी
(ग) एमआईजी
(घ) एसएफएस

2577.00 रु०
3865.00 रु०
6441.00 रु०
7730.00 रु०
(प्लॉटों के बिक्री लागत पूरा करने के दौरान आंतरिक विकास के लागत को जोड़ा जाय)

3. वैकल्पिक प्लॉट

6193.00 रु०
(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)

4. सीजीएचएस के लिए भूमि

7730.00 रु०

5. जे0जे0 स्क्वेटर्स
(पुनर्वास)

22.90 लाख रु0 प्रति एकड़
(आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के
स्लम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी हैं।

जोष बाबू गुप्ता

(एस0एन0 गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुख्यालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली।

No. N-11013/19/2006-DDIB
No. K-13011/3/2004-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division 1B)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 7th January, 2008

Subject: **Extraordinary Gazette Notification** -
circulation of Notification (i) S.O. No.
2178(E) dated 28.12.2007 and (ii) S.O. No.
141(E) dated 1.1.2008.

मैटिंग सेल, डी.डी.आ.
Meeting Cell, D.D.A.
रजिस्ट्रार 38
दिनांक 10.1.08
Date 10.1.08

A copy each of Notification/Corrigendum dated 27.12.2007 and 1.1.2008 referred to above and published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

P.C. Secy
(C.P. Secy)

(Separate Copies)

54B
81408

24-6-04
9/1/08

To

- ✓ 1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-
PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS
(D&L)

(P.K. Santra)

Under Secretary
Telefax.: 23061681

10/1/08

AD (me)

D) 9/1

Meeting Assst

10/1/08



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1595]
No. 1595]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2007/पौष 6, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2007/PAUSA 6, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2187(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 को का.आ.सं.1690(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विचार किया गया तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन: जोन "डी" में रेस कोर्स रोड(45 मीटर मार्गाधिकार) के 19868 वर्ग मीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाए :-

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
जोन "डी" में 45 मीटर मार्गाधिकार वाले रेस कोर्स रोड	19868 वर्ग मीटर	सर्कुलेशन/रोड	आवासीय (प्रधान मंत्री के सरकारी आवास)	पूर्व- मनोरंजनात्मक(जिम. खाना क्लब) पश्चिम- आवासीय (7 रेस कोर्स रोड कॉम्प्लैक्स) उत्तर/पश्चिम- अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग का चौराहा दक्षिण- क्लब रोड(36.57 मीटर मार्गाधिकार)

[फा.सं. के-13011/3/2004-डी डी I बी]
जी. के. सांत्या, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2007

S.O. 2187(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1690 (E) dated 1st October 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of an area measuring 19668 sqm of Race Course Road (45 m R/W) in Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Race Course Road 45m R/W in Zone-D	19668 sqm	Circulation/Road	Residential (Official Residence of the Prime Minister)	East - Recreational (Gymkhana Club) West - Residential (7 Race Course Road Complex) North/West - Junction of Akbar Road and Teen Murti Marg South - Club Road 36.57m R/W

[F. No. K-13011/3/2004-DDIB]

P.K. SANTRA, Under Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2008/पौष 11, 1929

No. 6]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2008/PAUSA 11, 1929

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st January, 2008

S.O. 6(E).—Reference is invited to Ministry of Urban Development's Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 141(E) dated 7-2-2007 (issued from F. No. K-12011/1/2005-DDIB). In the English version of the said Notification, in note (i), under the column 'other controls' against Sl. Nos. (c) Hotel, below table 5.4:—Development Controls—Commercial Centres, for the numerics "5 10%", read "10%".

[No. N-11013/19/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

8 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110054
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. N-11013/19/2006-DDIB
No. K-13011/3/2004-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division 1B)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 7th January, 2008

Subject: **Extraordinary Gazette Notification -**
circulation of Notification (i) S.O. No.
2178(E) dated 28.12.2007 and (ii) S.O. No.
141(E) dated 1.1.2008.

A copy each of Notification/Corrigendum dated
27.12.2007 and 1.1.2008 referred to above and published in
the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for
information and necessary action.

26-6-08
9/1/08
मैट्रिक कक्ष, दि. वि. प्र.
Meeting Cell, D.D.A.
डा. वि. प्र. 36
Diary No.
दिनांक 10.1.08
Date

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
- ✓ 2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :
PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS
(D&L)

4/1/08
ADMC/DJ/29/11
M Asst
10/1/08



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1595]
No. 1595]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2007/पौष 6, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2007/PAUSA 6, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2187(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 की का.आ.सं.1690(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विचार किया गया तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन "डी" में रेस कोर्स रोड(45 मीटर मार्गाधिकार) के 19668 वर्ग मीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाए :-

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
जोन "डी" में 45 मीटर मार्गाधिकार वाले रेस कोर्स रोड	19668 वर्ग मीटर	सर्कुलेशन/रोड	आवासीय (प्रधान मंत्री के सरकारी आवास)	पूर्व- मनोरजनात्मक(जिम खाना क्लब) पश्चिम- आवासीय (7 रेस कोर्स रोड कॉम्प्लैक्स) उत्तर/पश्चिम- अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग का चौराहा दक्षिण- क्लब रोड(36.57 मीटर मार्गाधिकार)

[फा.सं. के-13011/3/2004-डी डी I बी]

पी. के. सांतोरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2007

S.O. 2187(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1690 (E) dated 1st October 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of an area measuring 19668 sqm of Race Course Road (45 m R/W) in Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Race Course Road 45m R/W in Zone-D	19668 sqm	Circulation/Road	Residential (Official Residence of the Prime Minister)	East - Recreational (Gymkhana Club) West - Residential (7 Race Course Road Complex) North/West - Junction of Akbar Road and Teen Murti Marg South- Club Road 36.57m R/W

[F. No. K-13011/3/2004-DDIB]

P.K. SANTRA, Under Secy.

Modification:

The land use of an area measuring 19668 sqm of Race Course Road (45 m R/W) in Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Race Course Road 45m R/W in Zone-D	19668 sqm	Circulation/Road	Residential (Official Residence of the Prime Minister)	East - Recreational (Gymkhana Club) West - Residential (7 Race Course Road Complex) North/West - Junction of Akbar Road and Teen Murti Marg South - Club Road 36.57m R/W

[F. No. K-13011/3/2004-DDIB]

P.K. SANTRA, Under Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

No. 6]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2008/पौष 11, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2008/PAUSA 11, 1929

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st January, 2008

S.O. 6(E).—Reference is invited to Ministry of Urban Development's Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 141(E) dated 7-2-2007 (issued from P. No. K-12011/1/2005-DDIB). In the English version of the said Notification, in note (i), under the column 'other controls' against Sl. Nos. (c) Hotel, below table S.4:—Development Controls—Commercial Centres, for the numerics "5 10%", read "10%".

[No. N-11013/19/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

8 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



No. K-20014/2/2007-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 09th January, 2008

To

✓ The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023

[Attention: Shri Prahlad Singh, Director (LC)]

✓ Sub: Cost Benefit Analysis (CBA) of Narola and determination of pre-determined rates for various land uses in Narola project for the year 2007-2008.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F.4(23)06/AO(P)/DDA/47 dated 11.7.2007, on the subject noted above, and to enclose a copy of the Notification regarding pre-determined rates for various land uses in Narola for information and further necessary action.

Yours faithfully,

(S.N. GUPTA)

Under Secretary to the Govt. of India
2306 1478

Copy along with a copy of Notification to the DDA (Member (Finance)/Principal Commissioner-cum-Secretary/Commissioner (LD)), Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt. of India

Sub: 2007, R.D.M.
Meeting Call, D.D.A.
2007/11
Dy. No. 47
Date 11/1/08

AD (M.C.)
11/1/08
14/1/2008

(भारत के राजपत्र के भाग-11 खण्ड 3 उपखण्ड (1) में प्रकाशनाधी)

सं० 20014/2/2007-डी.डी.11ए

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

110001

नियंत्रण भवन, नई दिल्ली-110011,

दिनांक: 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सी..... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नजूल भूमि विकास का निगटान) नियम, 1981, के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूरे निर्धारित प्रकार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

भूमि की श्रेणी	2007-2008 के लिए नयेला के लिए अनुमोदित पूर्ण निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी०)
1. सी.जी.एच.एस. के लिए भूमि	7602.00
2. नैकलिक भूखंड	6100.00 रु० (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिगोण प्रकार शामिल हैं)
3. सीटीए आवासीय स्कीम	7602.00 रु०
(क) एसएचएस	6335.00 रु०
(ख) एसआईसी	3801.00 रु०
(ग) एसआईसी	2534.00 रु०
(घ) ईडब्ल्यूएस	(कूलेटों की किसी लागत निकालने समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाय)
4. ओओओ स्कवेटर्स (पुनर्वास)	22.80 लाख रु० प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एससीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी हैं।

ए.एस.आर.सी.

(एसओएन गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुख्यालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली।



[To be published in Gazette of India,
Part II-Section 3-sub-Section (ii)]

No.K-20014/2/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

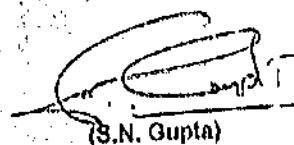
Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 00th January, 2008

Notification

G.S.R. No. _____ In exercise of powers conferred by Rule 2(i) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under :-

Category of Land	Approved pre-determined rates for Narela for 2007-2008 (per sq. mtr.)
1. Land for CGHS	Rs. 7002.00
2. Alternative Plots	Rs. 8108.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
3. DDA Housing Schemes	
(a) SFS	Rs. 7802.00
(b) MIG	Rs. 6335.00
(c) LIG	Rs. 3801.00
(d) EWS	Rs. 2634.00 (cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
4. J.J. Squallors (Resettlement)	Rs. 22.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.


(S.N. Gupta)

Under Secretary to the Govt. of India

To
The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110004



No. K-20014/3/2007-DDIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 09th January, 2008

To

The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023

(Attention: Shri Prahlad Singh, Director(LC))

Sub: Cost Benefit Analysis of Rohini Phase IV & V and determination
of pre-determined rates for various land uses in Rohini Phase IV
& V project for the year 2006-2007.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F.4(25)06/AO(P)/DDA/49,
dated the 11.7.2007, on the subject noted above, and to enclose a copy of the
Notification regarding pre-determined rates for various land uses in Rohini
Phase IV & V for information and further necessary action.

Yours faithfully,

Encl.: As above

(S.N. GUPTA)

Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Recd. Secy. to Govt.
Ministry of Urban Development,
New Delhi

Copy along with a copy of Notification to the DDA [Member
(Finance)/Principal Commissioner-cum-Secretary/Commissioner (LD)], Vikas
Sadan, INA Colony, New Delhi for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt. of India

Handwritten notes:
12/1/08
DDA
10/1/08

Handwritten notes:
M. S. Gupta
12/1/08

(भारत के राजपत्र के भाग-1। खण्ड 3 उपखण्ड (1) में प्रकाशनाधी)

र/0 20014/3/2007-सी.सी.11ए

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
(अ.स.स.)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं. दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास तथा निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार को (य दश) को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

भूमि की श्रेणी

2007-2008 के लिए रोहिणी फेज-IV एवं V के लिए
अनुमोदित पूर्व निर्धारित दर
(प्रति वर्ग मी०)

1. रोहिणी प्लॉट

- (क) ईटल्यूएस 20 वर्गमी०
(ख) एलआईजी 32 वर्गमी०
(ग) एमआईजी 60 वर्गमी०

4005.00 रु०

6193.00 रु०

10050.00 रु०

(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग
प्रकार शामिल)

2. आवारीय रकम

- (क) ईटल्यूएस
(ख) एलआईजी
(ग) एमआईजी
(घ) एसाएएस

2577.00 रु०

3065.00 रु०

6441.00 रु०

7730.00 रु०

(प्लॉटों के बिक्री लागत पूरा करने के दौरान आंतरिक
विकास के लागत को जोड़ा जाये)

3. वैकल्पिक प्लॉट

6193.00 रु०

(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग
प्रकार शामिल)

4. सीआईएसएस के लिए भूमि

7730.00 रु०

b. ओ.ओ.एस. (एन.एस.)

22.90 लाख रु० प्रति एकड़
(आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के
स्लम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी हैं।

लोमबाध गुप्ता

(एस.ओ.एस. गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुख्यालय,
रिंग रोड, गांधीपुरी,
नई दिल्ली।



[To be published in Gazette of India -
Part II-Section 3-Sub-section (1)]

No.K-20014/3/2007-DD HA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 09th January, 2008

NOTIFICATION

G.S.R. No. _____ In exercise of powers conferred by Rule 2(i) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under: -

Category of Land	Approved pre-determined rates for Rohini Phases IV & V for 2007-2008 (per sq. mtr.)
1. Rohini Plots	
(a) EWS 28 sqm.	Rs. 4005.00
(b) LIG 32 sqm.	Rs. 6193.00
(c) MIG 60 sqm.	Rs. 10058.00
	(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
2. Housing Scheme	
(a) EWS	Rs. 2577.00
(b) LIG	Rs. 3065.00
(c) MIG	Rs. 6441.00
(d) SFS	Rs. 7730.00
	(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
3. Alternative Plots	Rs. 6193.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
4. Land for CGHS	Rs. 7730.00
5. J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 22.00 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.

(S.N. Gupta)

Under Secretary to the Govt. of India

To
The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110004



No. K-20014/3/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 09th January, 2008

To
The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Sub :- Publication of Pre-determined rates for Rohini Phase IV & V for
2007-08 in Part II Section - 3 Sub-section (I) in the Gazette of
India.

Sir,

I am directed to send herewith a copy each of the notifications
(Hindi & English versions) (duly signed in ink) in respect of pre-
determined rates of Rohini Phase IV & V for the year 2007-08 for being
published in the Gazette of India.

4. It is requested that the same may be published immediately and
one set each of the Gazette Notifications may be sent to this office for
official use.

5. This may be treated as **MOST IMMEDIATE**. This issues with the
approval of Hon'ble Urban Development Minister.

Yours faithfully,

(S.N. Gupta)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel.: 2306 1478

Encl. :- As above.

Copy to:

1. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
2. The Secretary to E.G., Delhi.
3. Secretary (L & B), GNCTD, Delhi.
4. Finance Member, DDA, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
5. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.

Under Secretary to the Govt. of India

(भारत के राजपत्र के भाग-11 प्रपत्र 3 उपखण्ड(1))में प्रकाशनाधी)

सी 20014/3/2007-डी.सी.112

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
नई दिल्ली

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सी..... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नजूल भूमि विकास का विपणन) नियम, 1981, के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्ण निर्धारित प्रकार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

भूमि की श्रेणी

2007-2008 के लिए रोहिणी फेज-IV एवं V के लिए अनुमोदित पूर्ण निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)

1. रोहिणी प्लॉट

(क)	ईटल्यूएस 20 वर्गमी०	4005.00 रु०
(ख)	एलआईजी 32 वर्गमी०	0193.00 रु०
(ग)	एलआईजी 60 वर्गमी०	10080.00 रु०

(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रकार शामिल)

2. आवासीय स्कीम

(क)	ईटल्यूएस	2677.00 रु०
(ख)	एलआईजी	3005.00 रु०
(ग)	एलआईजी	6441.00 रु०
(घ)	एसएफएस	7730.00 रु०

(प्लॉटों के विक्री लागत पूरा करने के दौरान आंतरिक विकास के लागत को उभेरा जाय)

3. वैकल्पिक प्लॉट

0193.00 रु०

(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रकार शामिल)

4. सीजीएसएस के लिए भूमि

7730.00 रु०

5. ओओओ सचिवदर
(पुनर्गता)

22.90 लाख रुप प्रति एकड़
(आंतरिक विकास के तर्ष को ओकुकर ओ एगरीडी के
रलग सिमाग द्वारा निर्धारित किया जाना है)

ये दरें वित्तीय तर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी हैं ।

ओमकाथ गुप्ता

(एसओएसओ गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार गुप्तालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।



[To be published in Gazette of India -
Part II-Section 3-Sub-section (ii)]

No K-20014/3/2007-DD HA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 09th January, 2008

NOTIFICATION

G.S.R. No. _____ In exercise of powers conferred by Rule 2(i) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under:-

Category of Land	Approved pre-determined rates for Rohini Phase IV & V for 2007-2008 (per sq. mtr.)
1. Rohini Plots	
(a) EWS 26 sqm.	Rs. 4905.00
(b) LIG 32 sqm.	Rs. 6193.00
(c) MIG 60 sqm.	Rs. 10058.00
	(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
2. Housing Scheme	
(a) EWS	Rs. 2577.00
(b) LIG	Rs. 3885.00
(c) MIG	Rs. 6441.00
(d) SFS	Rs. 7730.00
	(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
3. Alternative Plots	Rs. 6193.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
4. Land for CGHS	Rs. 7730.00
5. J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 22.00 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.

(S.N. Gupta)

Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064



No. K-20014/2/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 09th January, 2008

To
The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Subj:- Publication of Pre-determined rates for Narela for 2007-08 in Part II Section - 3 Sub-section (1) in the Gazette of India.

I am directed to send herewith a copy each of the notifications (Hindi & English versions) (duly signed in ink) in respect of pre-determined rates of Narela for the year 2007-08 for being published in the Gazette of India.

2. It is requested that the same may be published immediately and one set each of the Gazette Notifications may be sent to this office for official use.

3. This may be treated as **MOST IMMEDIATE**. This issues with the approval of Hon'ble Urban Development Minister.

Yours faithfully,

(S.N. Gupta)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel.: 2306 1478

Encl. :- As above.

Copy to:

1. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, I.N.A, New Delhi.
2. The Secretary to L.G, Delhi.
3. Secretary (I. & B), GNCTD, Delhi.
4. Finance Member, DDA, Vikas Sadan, I.N.A, New Delhi.
5. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, I.N.A, New Delhi.

Under Secretary to the Govt. of India

RECEIVED
SECRETARY
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
GOVT. OF INDIA
NEW DELHI
09/01/2008

P.D.

P.C.

P.C. 5006

M
M

69B

09/01/2008

Secretary, R.D.M.

Meeting Cell, D.D.A.

46

11/01/08

File No. DD/2
Avt (me.)

107

M. 11/01/08

19/1

(भारत के राजपत्र के भाग-1 | खण्ड 3 उपखण्ड (1) में प्रकाशनाधीन)

सं० 20014/2/2007-डी.डी.11ए

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
100001

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: ०१.०१.२००८

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं. दिल्ली विकास प्राधिकरण (नग्न भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

भूमि की श्रेणी	2007-२००८ के लिए नरला के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी०)
1. सी.सी.एफ.ए. के लिए भूमि	7002.00
2. वैकल्पिक भूखंड	6108.00 रु० (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल हैं)
3. सी.सी.ए. आवश्यक स्कीम	
(क) एराफफरा	7002.00 रु०
(ख) एमआईडी	6335.00 रु०
(ग) एलआईडी	3801.00 रु०
(घ) ईटव्यूएस	2634.00 रु०
	(फ्लैटों की वित्ती लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाय)
4. ओओओ रकबेटर्स (पुनर्वास)	22.00 लाख रु० प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर ओ एमसीडी के स्वामित्व द्वारा निर्धारित किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी हैं।

सचिव
(एसओएनओ गुप्ता)

भारत सरकार, भारत सरकार

रोवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुख्यालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली।



[To be published in Gazette of India,
Part II: Section 3-sub-Section (ii)]

No K-20014/2/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 09th January, 2008

Notification

G.S.R. No. _____ In exercise of powers conferred by Rule 2(i) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under:-

Category of Land	Approved pre-determined rates for Naraia for 2007-2008 (per sq. mtr.)
1. Land for CGHS	Rs. 7602.00
2. Alternative Plots	Rs. 8100.00 (Inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
3. DDA Housing Schemes	
(a) SFS	Rs. 7602.00
(b) MIG	Rs. 8335.00
(c) LIG	Rs. 3801.00
(d) EWS	Rs. 2534.00 (cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
4. J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 22.00 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India

To
The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110004

No. K-12016/2/2006- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 31st January, 2008

Subject: Notification dated 30.1.2008 regarding issue of directions to the local authorities in the Extraordinary Gazette of India.

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)

Under Secretary

Telefax.: 23061681/
23061006 /23061478

- Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)/ Director (DD)

वैयक्तिक कार्य, वि. वि. वि.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी नं. 95
दिनांक 31/01/08
Date 31/01/08

5.2.08
PS to UDM
dy. sec. PPS/UD

31/01/08
AD/Secy

Meeting Room

6/2/2008

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]
No. 127]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2008/माघ 10, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2008/MAGHA 10, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2008

का.आ. 213(अ).—यतः दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) (यहाँ इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 के निबन्धनों के अनुसार अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी नोटिस, दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित माने जाएंगे;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के उपबंधों के निबन्धनों के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में उल्लिखित अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास के खिलाफ दण्डिक कार्रवाई दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित रखी जाएगी;

अतः, अब, दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को एतद्वारा निम्नलिखित निर्देश देती है :

निर्देश

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अनधिकृत विकास के संबंध में अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र को छोड़कर, न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सीलिंग कार्य बंद करने सहित जनवरी, 2006 के पहले दिन की यथास्थिति बनाए

312 G/2008

रखने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

(ii) न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सीलिंग कार्य बंद करने सहित अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र जो 31 मार्च, 2002 को 8 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार मौजूद थे, की स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथास्थिति बनाई रखी जाएगी।

2. अधिनियम के खण्ड 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध प्रारंभिक कार्रवाई के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी सभी सूचनाएं निलंबित होंगी और 31 दिसम्बर, 2008 तक कोई भी दण्डिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

3. दिसम्बर, 2007 के 5वें दिन से 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 4 में यथानिर्दिष्ट अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संगत विधियों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

[फा. सं. के-12016/2/2006-डीडीआईबी]

पी. के. सांतारा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2008

S.O. 213(E).—Whereas in terms of Section 3 of The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007) (hereafter referred to as

(1)

the said Act), all notices issued by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development mentioned therein shall be deemed to have been suspended till the 31st day of December, 2008;

And whereas in terms of the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the said Act, punitive action against encroachment or unauthorized development referred to in sub-section (1) of Section 3 of the Act shall be suspended till the 31st day of December, 2008;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 5 of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007), the Central Government hereby issues the following directions to the local authorities to give effect to the provisions of the said Act, namely :

DIRECTIONS

- (1) (i) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including descaling, to maintain status quo as on 1st day of January, 2006 in respect of encroachment or unauthorized development referred to in Section 3 of the said Act except in respect of unauthorized colonies, village abadi area and its extension.

(ii) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including descaling, to maintain status quo, in the unauthorized colonies, village abadi area and its extension, which existed on the 31st day of March, 2002 as on the 8th day of February, 2007.

(2) All notices issued by any local authority for initiating action against encroachment or unauthorized development referred to in Section 3 of the Act shall be suspended and no punitive action shall be taken till the 31st day of December, 2008.

(3) During the period up to 31st December, 2008 w.e.f. 5th day of December, 2007, action as per relevant laws shall continue to be taken by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development, as specified in Section 4 of the said Act and a monthly report of the action taken shall be sent to the Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi by the end of the first week of the succeeding month.

[F. No. K-12016/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 12th February, 2008

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi.
12. Dy. Registrar (AG), Supreme Court of India.

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display the above Notification on the website of the Ministry.

DD 8/2 12/2
K 1372108
AD (p.c.)
Meeting Assn
13/12/2008



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. - 176]
No. 176]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 272(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 16 मई, 2007 को सं. का.आ. 767(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विचार किया गया तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

जोन "डी" में 12.19 एकड़ माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया गया है :-

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सोमाएं
1	2	3	4	5
जोन "डी" में आईटीपीओ, प्रगति मैदान	12.19 एकड़	मनोरंजनात्मक	सरकारी कार्यालय	उत्तर-रेलवे लाईन/मेट्रो लाईन पूर्व और दक्षिण-प्रगति मैदान काम्पलेक्स पश्चिम-मथुरा रोड

[का.सं. के-20013/17/2006-डी डी V ए/बी]

पी. के. सांतारा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2008

S.O. 272(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 767(E) dated 16th May, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas a number of objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 12.19 acres of land in Zone D is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
ITPO, Pragati Maidan in Zone-D	12.19 acre	'Recreational'	Government office	North : Railway line/Metro station East and South : Pragati Maidan Complex West : Mathura Road

[F.No. K-20013/17/2006-DDVA/IB]

P.K. SANTRA, Under Secy.

(To be published in Part I, Section 2 of the Gazette of India)

No. K-11011/42/2006-DDIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 108
Dated: April 2, 2008

NOTIFICATION

वैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.

डायरी नं. 205

दिनांक 4.4.2008

The President is pleased to appoint Ms. Veena Ish, IAS (AP:85) as Principal Commissioner (Commonwealth Games) in the Delhi Development Authority at the level of Joint Secretary in the pay scale of Rs. 18400-22400 for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or till the term of the Commonwealth Games or until further orders, whichever is the earliest.

Don

(N.T. Joseph)

Under Secretary (DD 1A)

Tel: 23061478

To

The Manager,
Govt. of India Press, (with Hindi version)
FARIDABAD (Haryana)

Copy forwarded to:

1. The Secretary to the Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
2. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
3. Department of Personnel & Training (Shri A.K. Singhal, Director) w.r.t O.M. No. 26/1/2007-EO (SM.I) dated 20.3.2008.
4. Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Secretariat, Hyderabad.
5. Ms. Veena Ish, IAS (AP:85) through Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Secretariat, Hyderabad.
6. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
7. Commissioner (Personnel), DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Copy also forwarded for information to:-

PS to UDM / Sr. PPS to Secretary (UD) / PS to SS (UD) / PS to JS(DL)/PS to JS & FA/PS to JS(UD).

Don

(N.T. Joseph)

Under Secretary (DD 1A)

Tel: 23061478

DD(MC) 4/4

4/4/08

ADMC

4/4/08

M.S. ASH

No. K- 12016/6/2003-DDIB

Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi

Dated the 21st April, 2008

21/4/08
25/4/08

Subject: Modification of Composition of Heritage Conservation Committee-- forwarding of copy of Extraordinary Gazette Notification issued on 4.4.2008.

PC-Secy
Com (P.S.)

A copy of Notification No.817 (E) dated 4th April, 2008 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K.Santra)

Under Secretary

Tel.No.23061681

Copy to:

1. **Special Secretary**, MoUD and Chairman of the Heritage Conservation Committee, Nirman Bhavan, New Delhi
2. **Member Secretary**, DUAC,
3. **Director General**, Archeological Survey of India, Janpath, New Delhi
4. **Vice Chairman**, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
5. **Chairperson**, NDMC, Palika Kendra, New Delhi
6. **Commissioner** (MCD), Town Hall, Delhi
7. **Director General (Works)**, CPWD, Nirman Bhavan, New Delhi

उपस्थित का
आवृत्ति सं. 264-B
दिनांक 22/4/08

25/4/08
AD (Secy)
25/4/08
25/4/08
12/5/08



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2008/चैत्र 15, 1930
No. 452] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2008/CHAITRA 15, 1930

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2008

का.आ. 817(अ).—केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली भवन निर्माण उप-नियमों में एतद्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन :

1. धारा 23.16 में हेरिटेज संरक्षण समिति के गठन में क्र.सं.

(i) को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाए :-

"1. विशेष सचिव/अपर सचिव

अध्यक्ष"

शहरी विकास मंत्रालय

2. दिनांक 20 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1964(अ) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाए :-

संशोधन

1. हेरिटेज संरक्षण समिति के गठन में क्र.सं. 1 को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाए :-

"1. विशेष सचिव/अपर सचिव

अध्यक्ष"

शहरी विकास मंत्रालय

2. पैरा 2 को इस प्रकार संशोधित किया जाए :-

"2. समिति का कार्यकाल दिनांक 9-2-2007 से लेकर 3 वर्ष तक का होगा।"

[सं. के-12016/6/2003-डीडीआईबी]
पी. के. सान्त्रा, अवर सचिव

1270 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2008

S.O. 817(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1957, the Central Government hereby makes the following modifications in the Delhi Building Bye Laws with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Sl.No. (i) in the composition of the Heritage Conservation Committee in Clause 23.16 shall be modified to read as under :-

"(i) Special Secretary/Additional Secretary, Ministry of Urban Development

Chairman"

2. Attention is also invited to Notification No. S.O.1964(E) dated 20th November, 2007. The following modifications shall be made in the said Notification :-

Modifications

1. In the composition of the Heritage Conservation Committee, Sl.No.1 shall be modified to read as under :-

"1. Special Secretary/Additional Secretary, Ministry of Urban Development

Chairman"

2. Para 2 shall be modified as under :-

"2. The tenure of the Committee shall be 3 years with effect from 9-2-2007".

[No. K-12016/6/2003-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674]
No. 674]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2008/वैशाख 26, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2008/VAISAKHA 26, 1930

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.

जायरी सं.

Diary No.

दिनांक

Date

280

28.5.08

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2008

का.आ. 1169(अ).—यह, नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 14 नवम्बर, 2007 को सं. का.आ. 1933(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत का राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः, केन्द्र सरकार ने, मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निश्चय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, वशते कि मौजूदा अनधिकृत बस्तानों के साथ-साथ डिफेंस अपनी भूमि पर उचित सड़क मुहैया कराए।

संशोधन :

जोन-जे (दक्षिण दिल्ली-II) में 12.15 हेक्टे (29.968 एकड़) के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन-जे (दक्षिण दिल्ली-II) रंगपुरी (वस्तुबुज)	12.15 हेक्टे (29.968 एकड़)	कृषि और जलाशय "ग्रामीण"	डिफेंस उद्देश्य हेतु "सरकारी भूमि (अनिश्चित उपयोग)"	पूर्व — एयरपोर्ट प्राधिकरण की भूमि पश्चिम — कृषि और जलाशय (ग्रामीण) और क्षेत्रीय पार्क उत्तर — महारौली-महिपालपुर रोड और मुल्तानगढ़ी मकबरा दक्षिण — नांगल देवात बेदखल स्कीम

[फा. सं. के-13011/4/2007-डी डी आई बी]

पी. के. सातवा, अवर सचिव

1821 GI/2008

(1)

Copy sent to A2/ Meeting Cell, 201
for m/s freedom.

A2/ Meeting Cell 26/5/08

Praveen
A2/PR 28/5/08

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2008

S.O. 1169(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1933(E) dated the 14th November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India. Subject to the condition that proper road would be provided by Defence on their land along the existing unauthorized colony.

Modification:

The land use of the following area measuring 12.15 Ha. (29.968 acres) of land falling in Zone-J (South Delhi-II) is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rangpuri (Vasant Kunj) in Zone-J (South Delhi-II)	12.15 Ha. (29.968 Acres)	Agricultural and Water Body 'Rural'	'Government Land (use undetermined)' for defence purpose.	East — Air-port Authority land West — Agricultural and Water Body (Rural) and Regional Park North — Mehrauli Mahipalpur Road and Sultan Garhi Tomb South — Nangal Dewat Evictees Scheme

[F.No.K-13011/4/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]
No. 389]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2008/चैत्र 4, 1930
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2008/CHAITRA 4, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2008

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन के विनियम
(दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के
अंतर्गत)

का.आ. 683(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957
का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली
विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा
निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. प्रस्तावना
2. परिभाषाएं
3. अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन के मानदण्ड
 - 3.1 निर्धारक तिथि
 - 3.2 नियमन के लिए पात्र वस्ती
 - 3.3 नियमन के लिए विचार नहीं की जाने वाली
कॉलोनियों की प्रकृति
 - 3.4 गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए
जाने वाले आवासीय भवन
 - 3.5 अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई
 - 3.6 विनियम जो संश्रुत कॉलोनियों से संबद्ध नहीं हैं
4. नियमन की पद्धति
 - 4.1 रेजीडेंट सोसायटी का पंजीकरण

- 4.2 रेजीडेंट सोसायटी के कार्य
- 4.3 ले-आउट प्लान तैयार करना
- 4.4 ले-आउट प्लान में संशोधन करना
- 4.5 ले-आउट प्लान प्रस्तुत करने की अपेक्षाएं
 - 4.5.1 प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
 - 4.5.2 वर्तमान/प्रस्तावित ले-आउट प्लान के संबंध में
सूचना
 - 4.5.3 वचनबंध-पत्र
5. नियमन के लिए स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्ष. दिल्ली
सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई/पद्धति
 - 5.1 एक पृथक कक्ष (सेल) का सृजन
 - 5.2 ले-आउट प्लान की जांच
 - 5.3 सीमाओं को अंतिम रूप देना
 - 5.4 स्थानीय निकायों को ले-आउट प्लान अंग्रेषित
करना
 - 5.5 ले-आउट प्लान का अनुमोदन
 - 5.6 भूमि उपयोग परिवर्तन
 - 5.7 आदेश जारी करना
 - 5.8 भूमि को लागत
 - 5.9 जुर्माना
 - 5.10 विकास कार्य प्रारंभ करना

- 5.11 समय अनुसूची
6. नियमन के मानदण्ड/आधार
 - 6.1 भूमि का इक
 - 6.2 योजना मानदण्ड
 - 6.3 मिश्रित उपयोग
 - 6.4 लागत/विकास प्रभार की वसूली
7. विविध
 - 7.1 संस्वीकृति देना या ठुकराना
 - 7.2 दिशानिर्देशों के साथ पठित विनियम
 - 7.3 समन्वय आदि रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा

1. प्रस्तावना

शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 05-10-2007 के पत्र द्वारा दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन हेतु संशोधित मार्गनिर्देश 2007 की सूचना दी है, जिसे 1994 की रिट याचिका सं. 725 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14-02-2006 के आदेशों और 1993 की सिविल रिट याचिका सं. 4771 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 27-2-2001 के आदेशों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के आदेशों में मार्गनिर्देशों के अनुसार नियमित की जाने वाली कॉलोनियों को अधिसूचना और नियमों को तैयार करने की भाग की गई है।

2. परिभाषाएँ

- (क) "वास्तुकार/नगर योजनाकार" ऐसा वास्तुकार जो वास्तुकला परिपक्व में मंजीकृत हो और जिसके पास नगर योजना में ऐसी योग्यता हो जो नगर योजनाकार संस्थान, भारत की सदस्यता के लिए मान्य हो;
- (ख) "संबंधित एजेंसी" से अभिप्राय ऐसे स्थानीय निकाय/दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.)/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार) अथवा किसी अन्य एजेंसी से है, जो योजनाओं के नियमन/तैयार करने, क्रियान्वयन की प्रक्रिया और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन के कार्य में सम्मिलित हो।
- (ग) "बरती" शब्द से अभिप्राय संशोधित मार्गनिर्देश 2007/विनियमों में यथा निर्दिष्ट नियमन के उद्देश्य के लिए उन बस्तियों से है जो 31-3-2002 को विद्यमान थी तथा जो गाँव की आवादी के विस्तार के रूप में बनी हैं और जो गाँव की आवादी के लाल डोरा विस्तार के रूप में अधिसूचित नहीं हैं;
- (घ) "आधारिक संरचना" से अभिप्राय उस आधारिक संरचना से है, जो 'सामाजिक आधारिक संरचना' जैसे जल आपूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, बिजली और कूड़ा निपटान, जिसका उल्लेख दिल्ली मुख्य योजना (एम.पी.डी.)-2021 के अध्याय-14 (भौतिक आधारिक संरचना) में हुआ है, से भिन्न है;
- (ङ) "ले-आउट प्लान" से अभिप्राय: उस नक्शे से है जिसमें सभी विद्यमान (प्रस्तावित भी, यदि कोई हो) सड़कों की उनकी चौड़ाई सहित अवस्थिति, बिल्डिंग लाइन्स सहित प्लॉटों की

दिशाओं, नालों और सार्वजनिक सुविधाओं, यदि क हो, की अवस्थिति, सड़कों के स्थल के कुल क्षेत्रफल को दर्शाने वाला विवरण और यदि उपलब्ध हो, तो पार्कों के लिए खुले स्थलों, खेल-मैदानों, मनोरंजनात्मक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों को दर्शाया गया हो;

- (च) "रेजीडेंट्स सोसायटी" से अभिप्राय एक मंजीकृत रेजीडेंट सोसायटी से है, जिसमें अनधिकृत कॉलोनी/आवास के सदस्य शामिल हैं, जो समन्वय, ले-आउट प्लान तैयार करने और नियमन की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में संबंधित एजेंसी से सम्पर्क करने के लिए उत्तरदायी होगी।
 - (छ) "सर्विस रोड"—ऐसी रोड/लेन जिसकी व्यवस्था सर्विस उद्देश्यों के लिए प्लॉट के पीछे या एक तरफ की गई है;
 - (ज) "साइट या प्लॉट"—ऐसा भूखण्ड जिसकी सीमाएँ निर्धारित हैं;
 - (झ) "सामाजिक आधारिक संरचना" से अभिप्राय उन सामाजिक आधारिक संरचना संबंधी सुविधाओं से है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल सुविधाओं एवं सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक कार्यक्रमों से संबंधित हैं;
 - (ञ) "स्ट्रीट" में कोई भी मार्ग, रोड, लेन, स्कवेयर, कोर्ट, गली, नाली, रास्ता चाहे वह आम रास्ता हो या न हो और चाहे वह बना हुआ हो या न हो, जिसके ऊपर आम जनता को चलने का अधिकार हो और चाहे वह किसी पुल या पक्के नदी पथ पर बना रोड वे या पैदल रास्ता हो, शामिल है;
 - (ट) "अनधिकृत कॉलोनी" से अभिप्राय ऐसी कॉलोनी/समीपस्थ विकास क्षेत्र से है, जहाँ ले-आउट प्लान, और/अथवा बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के लिए संबंधित एजेंसी से कोई अनुमति प्राप्त न की गई हो;
- ## 3. अनधिकृत कॉलोनियों और बस्तियों के नियमन हेतु मानदण्ड
- 3.1 नियमन की निर्धारक (कट ऑफ) तिथि 31-3-2002 है।
 - 3.2 ऐसे आवास जो गाँव की आवादी के विस्तार के रूप में बने हैं और जो गाँव के लाल डोरे से बाहर स्थित हैं, वे नियमन के लिए अनधिकृत कॉलोनियों की पद्धति के समान आधार पर नियमन के लिए पात्र होंगे।
 - 3.3 निम्नलिखित प्रकार की कॉलोनियाँ अथवा उनके भाग पर नियमन हेतु विचार नहीं किया जाएगा :
 - (क) ऐसी अनधिकृत कॉलोनियाँ/कॉलोनियों के भाग/बस्तियाँ, जो अधिसूचित या आरक्षित वन क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं।
 - (ख) अनधिकृत/कॉलोनियाँ/कॉलोनियों के भाग/बस्तियाँ जो आधारिक-संरचना सुविधाओं की व्यवस्था में बाधा

- उत्पन्न करती हैं, अथवा नियमावली/प्रस्तावित केने माइनों, मुख्य योजना राइकों और बड़ी/मुख्य जलमय और सीवरज लाइनों के मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) के क्षेत्र में आती हैं।
- (ग) अनधिकृत कॉलोनियाँ/वस्तियाँ, जिनमें निर्माण योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि को 50 प्रतिशत से अधिक प्लॉटों पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तथापि, उपर्युक्त कॉलोनिनों में 31-3-2002 के बाद और नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि तक बने प्लॉटों को कॉलोनी की नियमन की पात्रता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- (घ) अनधिकृत कॉलोनियाँ/कॉलोनिनों के भाग/वस्तियाँ-जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1956 की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करती हैं।
- 3.4 समय-समय पर यथा संशोधित, दि.मु.यो.-2021 में निहित मिश्रित भूमि उपयोग विनियमों के अंतर्गत शामिल होने वाले आवासीय भवनों को छोड़कर, गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जा रहे आवासीय भवनों के संबंध में कोई नियमन नहीं किया जाएगा। इन कॉलोनिनों के संबंध में दि.मु.यो.-2021 के खण्ड 15.3.4 में यथा-निर्धारित मिश्रित उपयोग सड़कों की अधिसूचना के लिए सर्वेक्षण करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कॉलोनी को नियमित कॉलोनी माने जाने की अधिसूचना की तिथि से अथवा उस तिथि-जिससे कॉलोनी नियमन के लिए योग्य मानी जाएगी, से आरंभ होगी।
- 3.5 अनधिकृत कॉलोनियाँ/कॉलोनिनों के भाग/वस्तियाँ जो नियमन की शर्तें पूरी नहीं करती हैं, में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा पैरा 16.2.3 में दी गई व्यवस्थाओं सहित दिल्ली मुख्य योजना में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार की जाएगी।
- 3.6 ये विनियम सार्वजनिक और निजी भूमि पर संभ्रांत वर्गों द्वारा बसायी गयी वस्तियों/अनधिकृत कॉलोनिनों पर लागू नहीं होंगे।
4. नियमन के लिए प्रक्रिया
- नियमन के लिए निम्नलिखित कदमों को अपनाया जाएगा:-
- 4.1 रेजीडेंट्स सोसायटी का पंजीकरण
- प्रत्येक अनधिकृत कॉलोनी/वस्ती के निवासी एक पंजीकृत रेजीडेंट्स सोसायटी (जिसे आगे रेजीडेंट सोसायटी कहा जाएगा) का गठन करेंगे। नियमन के मामले में विचार के लिए यह एक पूर्व-शर्त होगी। एक कॉलोनी में कई एसोसिएशनों के होने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु इन एसोसिएशनों को संयुक्त रूप से एक पंजीकृत रेजीडेंट्स सोसायटी बनानी होगी। स्थानीय निकाय केवल ऐसी रेजीडेंट्स सोसायटियों को मान्यता देगा और उनसे बातचीत करेगा, जिसमें उस कॉलोनी के कम-से-कम 75 प्रतिशत निवासी उसके सदस्य हों।
- 4.2 रेजीडेंट्स सोसायटी निम्नलिखित कार्य करेगी:-
- 4.2.1.1 नियमन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मामलों में संबंधित अभिकरण के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
- 4.2.1.2 वास्तुकार/नगर योजनाकार के माध्यम से कॉलोनी का विद्यमान ले-आउट प्लान तैयार करना। तथापि, रेजीडेंट सोसायटी अपनी कॉलोनी के संबंध में संशोधित ले-आउट प्लान स्वीच्छक रूप से भी जमा करा सकती है।
- 4.2.1.3 इस प्रकार तैयार किया गया ले-आउट प्लान रेजीडेंट सोसायटी द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी साथ ही साथ रेजीडेंट सोसायटी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को भी ले-आउट प्लान की एक प्रति जमा कराएगी।
- 4.2.2 रेजीडेंट सोसायटी द्वारा ले-आउट प्लान के साथ पूर्ण विवरण जैसे प्लॉट नं. और कॉलोनी के क्षेत्रफल सहित सदस्यों की पूर्ण सूची स्थानीय निकाय को जमा कराना होगा। रेजीडेंट्स सोसायटी का यह दायित्व होगा कि वह सामाजिक आधारिक संरचना की व्यवस्था करने हेतु कार्य करने के लिए संबंधित अभिकरण को जहां संभव हो, भूमि उपलब्ध कराए। जिन कॉलोनिनों में सोसायटी द्वारा सामाजिक आधारिक संरचना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकती, उन कॉलोनिनों को ऐसी आधारिक-संरचना की व्यवस्था के बिना अपना काम चलाना होगा।
- 4.2.3 स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार/भारत संघ के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी कि वे उन निवासियों को वैकल्पिक स्थलों/प्लैटों का आवंटन करें, जिन्हें खण्ड 3.3 में यथावर्णित नियमित नहीं हुई कॉलोनिनों में नागरिक सुविधाओं/आधारिक-संरचना की व्यवस्था के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए विस्थापित किया गया हो।
- 4.2.4 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार रेजिडेंट सोसायटियों/व्यक्तियों से वसूल किए जाने वाले विकास प्रभारों/कार्यवाही शुल्क, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगी।
- 4.3 रेजिडेंट सोसायटी को ले-आउट प्लान और संशोधित ले-आउट प्लान का प्रस्ताव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना होगा। यह उस विधि से और उतनी संख्या में प्रस्तुत करना होगा जिस रूप में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा उचित समझा जाए।
- 4.4 ले-आउट प्लान एक बार संस्वीकृत हो जाने पर रेजिडेंट सोसायटी उसकी मुद्रित प्रमाणित प्रति सोसायटी के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराएगी। संस्वीकृत ले-आउट प्लान में कोई भी अंतर एवं संशोधन संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. के अनुमोदन के अधीन होगा।
- 4.5 ले-आउट प्लान को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज
- 4.5.1 प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :
- अनधिकृत कॉलोनिनों के नियमन हेतु आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

(i) खसरा संख्या सहित भूमि का ब्योरा निचले माप स्थल नक्शा लगा हो जिसमें स्थल का वास्तविक विवरण दिया गया हो।

(ii) प्रमाण-पत्रों पर रेजिडेंट सोसायटी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/स्वामी और वास्तुकार/नगर योजनाकार के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए।

(iii) विनियमन हेतु आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया ले-आउट प्लान 1:1000 या बड़े पैमाने पर तैयार किया हुआ होना चाहिए और उसमें आगे के पैराग्राफ में दिया गया विवरण दर्शाया हुआ होना चाहिए।

4.5.2 विद्यमान/प्रस्तावित ले-आउट प्लान पर प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित जानकारी :

(i) स्वामित्व संबंधी स्थिति सहित स्थल की चारदीवारी और उससे सटी हुई भूमि;

(ii) समीपवर्ती क्षेत्र/सड़कों के संबंध में इस स्थल की स्थिति;

(iii) उन मार्गों के नाम जिनमें प्लॉट प्रस्तावित/विद्यमान है;

(iv) भूमि के उप विभाजन (सब डिवीजन) सहित उस पर प्लॉटों का उपयोग एवं स्थिति ;

(v) पट्टाच मार्ग/रोड स्ट्रीट और उनकी चौड़ाई ;

(vi) नॉर्थ प्वाइंट ;

(vii) अन्य विद्यमान भौतिक विशेषताएं जैसे कुएं, नाले, वृक्ष आदि;

(viii) प्लान रेजिडेंट सोसायटी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और वास्तुकार/नगर योजनाकार द्वारा अधिप्रमाणित होना चाहिए।

4.5.3 वचनबंध-पत्र

रेजिडेंट सोसायटी को ले-आउट प्लान प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित वचनबंध-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

(i) वे शर्तों सहित अथवा शर्तों के बिना यथा अनुमति ले-आउट प्लानों का पालन करेंगे।

(ii) वे सामाजिक-आधारिक संरचना के लिए उपलब्ध भूमि, यदि कोई हो, का हस्तांतरण दि.वि.प्रा. या दि.न.नि./नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के नाम में, निःशुल्क रूप से, ऐसी सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराने के लिए करेंगे।

5. नियमन के लिए स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय/कार्य-पद्धति :

5.1 स्थानीय निकायों/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार में, उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कॉलोनिजों के नियमन से संबंधित कार्य को करने के लिए एक पृथक

वाक्य बनाया जाएगा। रेजिडेंट सोसायटी द्वारा तैयार किया गया ले-आउट प्लान इस कक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

5.2 रेजिडेंट सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किए गए ले-आउट प्लान को प्राप्त होने पर स्थानीय निकाय अथवा दि.वि.प्रा. जैसी भी स्थिति हो, दो माह के अन्दर ले-आउट प्लान की जांच पूरी करेगा।

5.3 इसके साथ-साथ, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सैटेलाइट/एरियल सर्वेक्षण चित्रों का प्रयोग करते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से तीन माह के अन्दर प्रत्येक निर्धारित कॉलोनी की सीमाओं को अंतिम रूप देगी।

5.4 संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा जांच किए गए ले-आउट प्लान पर सीमाएं निर्धारित किए जाने के बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, औपचारिक रूप से ले-आउट प्लान को अनुमोदन के लिए स्थानीय निकाय की भेजेगी।

5.5 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा चारदीवारियों के निर्धारण के पश्चात् ले-आउट प्लान की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संबंधित स्थानीय निकाय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदित किया जाएगा।

5.6 साथ ही साथ, स्थानीय निकाय मामले को नियमन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को और भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए दि.वि.प्रा. को भेजेगा।

5.7 भूमि उपयोग परिवर्तन और सभी अपेक्षित प्रभावों के भुगतान सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा औपचारिक आदेश अथवा नियमन जारी किया जाएगा।

5.8 सरकारी भूमि पर कॉलोनिजों के संबंध में भूमि की लागत भूमि स्वामी एजेंसी की ओर से स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा एकत्रित की जाएगी। प्राप्त की गई राशि को संबंधित भूमि स्वामी एजेंसी के खाते में जमा किया जाएगा।

5.9 इसी तरह, स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा एकत्रित की जाने वाली जुर्माना राशि एक अलग फंड में जमा की जाएगी।

5.10 यदि यह संतुष्टि होती है कि कॉलोनिजों अथवा उनके भाग-संशोधित दिशानिर्देश 2007 में निहित सामान्य सिद्धान्तों की पूर्ति करते हैं तो ले-आउट प्लान की प्राप्ति के तुरन्त बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सार्वजनिक हित में कॉलोनिजों में विकास कार्य और आधारिक सुविधाओं के संबंधन को प्रारम्भ कर सकती है।

5.11 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगी कि भूमि उपयोग में परिवर्तन के अतिरिक्त नियमन की संपूर्ण-प्रक्रिया 6 माह के अन्दर पूरी होगी और रेजिडेंट सोसायटी द्वारा ले-आउट प्लान प्रस्तुत करने के 9 माह के अन्दर भूमि उपयोग में प्रभावी परिवर्तन के बाद औपचारिक नियमन हो जाएगा। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर उपरान्तपाल, दिल्ली पृथक कॉलोनिजों के संबंध में समय-सीमा में छूट दे सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2008

Regulations for Regularisation of Unauthorised Colonies in Delhi

(under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 683(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations:—

9. अनधिकृत कॉलोनी काय से अस्तित्व में है :
 10. अवस्थिति/आस-पास के स्थान (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर) :
 11. विस्तार क्षेत्र में—
दि.न.वि./न.दि.न.पा./कॉट बोर्ड क्षेत्र/
क्या यह अधिसूचित स्लम क्षेत्र में पड़ता है?
 12. अनधिकृत कॉलोनी का कुल क्षेत्र :
 13. भूमि की स्थिति (स्टेड्स) :
 14. न्यायालय मूल्यांकन, यदि कोई हो
(कृपया, विवरण संलग्न करें)
 15. क्या भूमि अभिगृहण हेतु अधिसूचित है?
 16. रेजिडेंट्स सोसायटी के सदस्य के रूप में निवासियों/गृह-स्वामियों का प्रतिशत :
 17. निर्मित प्लॉटों की संख्या :
(i) 100 वर्ग मीटर तक
(ii) 100 वर्ग मीटर से अधिक एवं 250 वर्ग मीटर तक
(iii) 250 वर्ग मीटर से अधिक
 18. खाली प्लॉटों की संख्या :
(i) 100 वर्ग मीटर तक
(ii) 100 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर
(iii) 250 वर्ग मीटर से बड़े
 19. सुविधाओं की स्थिति संख्या/क्षेत्र/ विकास-चरण
चौड़ाई/लंबाई
 - पार्क/परिवहन लॉट्स/ सामान्य खुला स्थल
 - स्कूल
 - समाज सदन
 - सामान्य पार्किंग क्षेत्र
 - डिस्पेंसरी/स्वास्थ्य केन्द्र
 - धार्मिक संरचना
 - पुलिस पोस्ट/फायर पोस्ट
- संलग्नक :
- (क) सदस्यों/स्वामियों/अधिभागियों की सूची
 - (ख) रेजिडेंट्स सोसायटी का पंजीकरण/संकल्प
 - (ग) नियमितकरण प्लान्स/ले-आउट प्लान
 - (घ) वचन बंधपत्र
 - (ङ) प्रमाणित भूमि स्वामित्व दस्तावेज/खसरा गिरदावरी
 - (च) भुगतानों की रसीद
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर रेजिडेंट्स सोसायटी

1. Introduction
2. Definitions
3. Criteria for Regularization of Unauthorized Colonies
 - 3.1 Cut off date
 - 3.2 Habitation eligible for regularization
 - 3.3 Types of colonies NOT to be considered for regularization
 - 3.4 Residential buildings used for non-residential purposes
 - 3.5 Action against unauthorized construction
 - 3.6 Regulations not relate to affluent colonies
4. Procedure for Regularization
 - 4.1 Registration of Resident Society
 - 4.2 Functions of Resident Society
 - 4.3 Submission of Layout Plan
 - 4.4 Modification in the Layout Plan
 - 4.5 Requisites for submission of Layout Plan
 - 4.5.1 Documents to be submitted
 - 4.5.2 Information regarding existing/proposed Layout Plan
 - 4.5.3 Undertakings
5. Steps/procedure to be followed by Local Body/DDA/GNCTD for regularization
 - 5.1 Creation of a separate Cell
 - 5.2 Scrutiny of Layout Plan
 - 5.3 Finalization of boundaries
 - 5.4 Forwarding of Layout Plan to Local Body
 - 5.5 Approval of Layout Plan
 - 5.6 Change of Land Use
 - 5.7 Issue of Orders
 - 5.8 Cost of land
 - 5.9 Penalties
 - 5.10 Commencement of developmental works
 - 5.11 Time schedule

6. नियमन के लिए मानदण्ड/आधार

6.1 भूमि का हक

भूमि का हक देने के लिए, समुचित संशोधित दिशा-निर्देश, 2007 तैयार करने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार दि.वि.प्र. के प्रतिनिधियों के साथ वरीयतः 2 माह की समय-सीमा के अन्दर एक कमेटी का गठन करेगी।

6.2 योजना मानदण्ड

दि. मु.यो.—2021 के पैरा 4.2.2.2 (बी) में यथा निहित संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

6.3 मिश्रित उपयोग

दि. मु. यो.—2021 के संगत प्रावधान संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा मिश्रित उपयोग सड़कों (स्ट्रीट्स)/स्थानीय व्यावसायिक स्ट्रीट की घोषणा के आधार पर लागू होंगे।

6.4 भूमि की लागत और विकास प्रभारों की वसूली

यूनिट एरिया विधि के आधार पर सम्पत्ति कर की वसूली हेतु कॉलोनियों के वर्गीकरण के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा अपनाए गए मानदण्ड के आधार पर नियमितोकरण उद्देश्य हेतु, कॉलोनियों को मुख्यतः तीन समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जो कि निकटवर्ती नियोजित कॉलोनी की अपेक्षा दो स्तर कम से मानक पर आधारित है।

समूह I : श्रेणी सी एवं डी में अनधिकृत कॉलोनियां।

समूह II : श्रेणी ई एवं एफ में अनधिकृत कॉलोनियां।

समूह III : श्रेणी जी में अनधिकृत कॉलोनियां।

सरकारी भूमि की लागत निम्नानुसार वसूल की जाएगी :-

(क) अविकसित सार्वजनिक/सरकारी भूमि हेतु :

समूह-I की कॉलोनियों में :

कृषि भूमि की प्रचलित अधिग्रहण लागत (575 रुपये प्रति वर्ग मी.) + 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट आकार हेतु 10 प्रतिशत जुर्माना राशि और 100 से 250 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज के लिए 25 प्रतिशत जुर्माना राशि, और 250 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट साइज के लिए 50 प्रतिशत जुर्माना राशि।

समूह II की कॉलोनियों में :

कृषि भूमि की प्रचलित अधिग्रहण लागत में से 15 प्रतिशत घटाकर + 100 से 250 वर्गमीटर तक के प्लॉट साइज के लिए 10 प्रतिशत जुर्माना राशि और 250 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट साइज के लिए 25 प्रतिशत जुर्माना राशि। 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज के लिए कोई जुर्माना राशि वसूल नहीं की जाएगी।

समूह III की कॉलोनियों में :

कृषि भूमि की प्रचलित अधिग्रहण लागत में से 30 प्रतिशत घटाकर + 100 से 250 वर्ग मी. तक के प्लॉट साइज के लिए 5 प्रतिशत जुर्माना राशि और 250 वर्ग मी. से बड़े प्लॉट साइज के लिए 10 प्रतिशत जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए कोई जुर्माना राशि वसूल नहीं की जाएगी।

(ख) विकसित सार्वजनिक भूमि/सरकारी भूमि हेतु :

अधिसूचित भूमि-दर और जुर्माना राशि (100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए 10 प्रतिशत तथा 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट के लिए 50 प्रतिशत)।

(ग) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निजी भूमि के रूप में निर्धारित की गई भूमि पर बसी हुई अधनाद्वय (नॉन-एम्प्लूएंट) कॉलोनियों से कोई भी परिवर्तन प्रभार अथवा संपटन-शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त दरें समय-समय पर परिवर्तनीय रहेंगी।

7. विधि

7.1 संस्वीकृति प्रदान करना अथवा मना करना :-

स्थानीय निकाय योजनाओं को अनुमोदित अथवा संशोधित कर सकता है अथवा जैसा वह आवश्यक समझे उन्हें संशोधनों/निर्देशों सहित मंजूर कर सकता है तथा विनिर्धारित रूप में नोटिस देकर संबंधित व्यक्ति को अपना निर्णय प्रेषित करेगा। जिन मामलों में प्लॉट में दिशा-निर्देश, 2007 अथवा विनियमों का पर्याप्त उल्लंघन पाया जाएगा, उन मामलों में स्थानीय निकाय प्लान को रद्द कर सकता है अथवा 'रेजिडेंट सोसाइटी' द्वारा उन्हें संशोधित कराने का आदेश दे सकता है।

7.2 इन विनियमों को, संशोधित दिशा-निर्देश, 2007 के साथ पढ़ा जाए और एक तालमेल के साथ इनका प्रतिपादन किया जाए ताकि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितोकरण की प्रक्रिया सुविधाजनक हो सके।

7.3 नियमितोकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा समन्वित और पर्यवेक्षित किया जाना है, जो संशोधित दिशा-निर्देश, 2007 और इन विनियमों को और भी अधिक प्रचार-प्रसार देगी।

[सं. फा. 3(11)2004/एम.पी./पार्ट-I]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

अनुबंध

अनधिकृत कॉलोनी के नियमन हेतु जांच-सूची

1. कॉलोनी का नाम और पता
2. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की सूची
3. रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन/आवेदक की सोसायटी का नाम
4. रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सोसायटी की पंजीकरण संख्या
5. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम
6. कॉलोनी की श्रेणी (दि.न.नि. सम्पत्तिकर के अनुसार)
7. राजस्व गांव/खसरा सं.
8. जोन (दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार)

1075 GI/08-2

4.5.2 Information required to be furnished on Existing/ Proposed Layout Plan:

- (i) The boundaries of the site and of contiguous land with ownership status;
- (ii) The position of the site in relation to neighbouring area/roads;
- (iii) The name of the streets in which the plots are proposed/existing;
- (iv) The use and position of the plots on the land including sub division;
- (v) The means of access/roads streets and their widths;
- (vi) The North point;
- (vii) Any existing physical features, such as wells, drains, trees etc;
- (viii) The plan shall be authenticated by the authorized signatory of Resident Society and Architect/Town Planner.

4.5.3 Undertakings

The Residents' Society shall furnish the following undertakings at the time of submission of the layout plan:

- (i) That they shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions.
- (ii) That they shall transfer the land available if any for social infrastructure in the name of the DDA or the MCD/NDMC, free of cost, in order to provide such social infrastructure.

5. Steps/Procedure to be followed by Local Body/ DDA/GNCTD for regularization:

- 5.1 A separate Cell is to be created in the local bodies/ DDA/GNCTD to carry out the work relating to regularization of unauthorized colonies within their jurisdiction. The layout plan prepared by Resident Societies would be submitted to this Cell.
- 5.2 On receipt of the layout plan submitted by the Resident Society, the Local Body or DDA, as the case may be, within two months will complete the scrutiny of the layout plan.
- 5.3 Simultaneously, GNCTD will finalize the boundaries of each identified colony within three months from the last date of submission of layout plan by using satellite/aerial survey images.
- 5.4 After fixing the boundaries on the scrutinized layout plan by the Local Body concerned, GNCTD to formally forward the layout plan to Local Body for approval.

5.5 Lay-out plan to be approved by the competent authority in the Local Body concerned within one month of receipt of LOP after fixation of boundaries by GNCTD.

5.6 Simultaneously, the Local Body to refer the case to GNCTD for regularization and to DDA for land use change.

5.7 Formal orders or regularization to be issued by GNCTD only after completing all formalities including land use change and payment of all requisite charges.

5.8 The cost of land shall be collected by Local Body/ DDA on behalf of land owning agency in respect of colonies on public land. Amounts so recovered to be credited to the account of respective land owning agency.

5.9 Similarly, penalties to be collected by Local Body/ DDA and to be credited into a separate fund.

5.10 GNCTD may commence the development works and augmentation of infrastructure facilities in public interest in colonies soon after the receipt of layout plan if it is satisfied that the colonies or part thereof fulfil the general principles contained in the Revised Guidelines 2007.

5.11 GNCTD shall take all required steps to ensure that the entire process of regularization except change in land use is completed within six months and formal regularization after effecting change in land use is done within nine months of submission of LOP by Resident Society. Lt. Governor, Delhi may relax the time limit in respect of individual colonies on specific request of GNCTD.

6. Parameters/basis for regularization

- 6.1 Title of land
GNCTD shall constitute a Committee with representatives of DDA to evolve suitable Revised Guidelines-2007 to confer title of land preferably within a time frame of two months.
- 6.2 Planning norms
Relevant provisions as contained in para 4.2.2.2(B) of MPD 2021 to apply.
- 6.3 Mixed Use
The relevant provisions of MPD-2021 shall be applicable subject to declaration of mixed use street / local Commercial Street by the concerned Local Body.
- 6.4 Recovery of cost of land and development charges
Based on criteria adopted by the Municipal Corporation of Delhi for categorization of colonies for recovery of property tax based on Unit Area Method, the colonies are broadly clubbed under three groups for regularization purpose based on the criteria of two stage lower than adjacent planned colony:

Group-I: Unauthorized Colonies in Category C and D

Group-II: Unauthorized Colonies in Category E & F

Group-III: Unauthorized Colonies in Category G

The cost of Government land shall be recovered as under:

(a) For undeveloped public/Govt. land

In Group-I colonies:

Prevailing Cost of acquisition of agricultural land (Rs. 575 per sqm) + 10% penalty for plot size up to 100 sqm and 25% penalty for plot size from 100 to 250 sq. m, and 50% penalty for plot size beyond 250 sqm.

In Group-II colonies:

Prevailing Cost of acquisition of agricultural land minus 15% + 10% penalty for plot size from 100 to 250 sqm and 25% penalty for plot size beyond 250 sqm. No penalty is to be levied for plot size up to 100 sqm.

In Group-III colonies:

Prevailing Cost of acquisition of agricultural land minus 30% + 5 % penalty for plot size from 100 to 250 sqm and 10% penalty for plot size beyond 250 sqm. No penalty is to be levied for plot size up to 100 sqm.

(b) For developed public land/Govt. land

Notified land rate and penalty (10% up to 100 sqm plot and 50% beyond 100 sqm plot).

(c) No conversion charges or compounding fee for non-affluent colonies on lands identified as private land by the GNCTD shall be levied.

Above rates are subject to changes from time to time.

7. Miscellaneous

7.1 Grant of Sanction or Refusal - The Local Body may either approve or modify the plans, or may sanction them with modifications or directions as it may deem necessary and thereupon shall communicate its decision to the person giving the notice in the prescribed form. In cases where the plans are substantially violative of the guidelines-2007 or the Regulations, the Local Body may reject or cause the plans to be modified by the Resident Society.

7.2 These Regulations may be read together with the Revised Guidelines 2007 and may be interpreted harmoniously so as to facilitate the process of regularization of the unauthorized colonies.

7.3 The entire process of regularization is to be coordinated and supervised by GNCTD, which

may also give wide publicity to the Revised Guidelines 2007 and these Regulations.

[F. No. 3(11)2004-MP-pt. I]

V.M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

Annexure

Check list for Regularization of Unauthorized Colony

1. Name and address of the Colony
2. Serial No. in the GNCTD List, if any
3. Name of RWA/Applicant Society
4. Registration no. of the RWA/Society
5. Name of Authorized Signatories
6. Category of colony (as per MCD Property Tax)
7. Revenue Village/khasra no.
8. Zone (As per Master Plan of Delhi)
9. Date from which unauthorized colony exists
10. Location/surroundings (Towards North, South, East West)
11. Development Area No :
MCD/NDMC/Canti. Board Area/Whether falls in Notified Slum Area?
12. Total area of Unauthorized Colony
13. Land Status
14. Court Case, if any (Please attach details)
15. Land whether notified for acquisition
16. Percentage of Residents/house owners as members of the Residents Society
17. No. of Built up Plots:
(i) Up to 100 sq.m. _____
(ii) Above 100 sqm & upto 250 sqm. _____
(iii) Above 250 sqm. _____
18. No. of Vacant Plots:
(i) Up to 100 sq.m. _____
(ii) Up to 100 - 250 sqm. _____
(iii) Above 250 sqm. _____
19. Status of Facilities Nos./ Area/ Stage of
Width/ Length Development.
 - Parks / Transport lots/ Common open space;
 - Schools
 - Community Hall
 - Common Parking Areas
 - Dispensary / Health Centre
 - Religious structures
 - Police Post / Fire Post

—Enclosures:

- (a) Lists of members/owners/occupants.
- (b) Registration/ resolution of the Residents Society.
- (c) Regularization Plans / Layout Plan.
- (d) Undertakings
- (e) Certified Land Ownership documents/ Khasra Gildawari (f) Receipt of payments.

Signature of Authorized Signatory
Resident Society

6. Parameters/basis for regularization

- 6.1 Title of land
- 6.2 Planning norms
- 6.3 Mixed use
- 6.4 Recovery of cost/development charges

7. Miscellaneous

- 7.1 Grant of sanction or refusal
- 7.2 Regulations to be read together with Guidelines
- 7.3 GNCTD to Coordinate, etc.

1. Introduction

Ministry of Urban Development *vide* letter dated 05-10-2007 conveyed the Revised Guidelines 2007 for regularization of unauthorized colonies in Delhi which also referred to orders of Supreme Court dated 14-02-2006 in WP@No. 725 of 1994 and orders of Delhi High Court dated 27-2-2001 in CW(P) No. 4771 of 1993. The High Court order stipulates notification of the colonies to be regularized as per the guidelines and framing of modalities.

2. Definitions

- (a) "Architect/Town Planner": An architect registered with the Council of Architecture and having qualification in Town Planning, recognized for the membership of Institute of Town Planners, India;
- (b) "Concerned agency" means Local Body/Delhi Development Authority (DDA)/ Government of NCT of Delhi (GNCTD) or any other agency involved in the process of regularization/preparation, implementation of the plans and work of regularization of unauthorized colonies falling within their respective jurisdictions;
- (c) "Habitations" for the purpose of regularization as envisaged in the Revised Guidelines 2007/ Regulations means those habitations existing as on 31-3-2002 that have come up as extension to village abadi and have not been notified as Lal Dora extension to village abadi;
- (d) "Infrastructure" means infrastructure other than 'social infrastructure' such as water supply, drainage, sewerage, electricity and solid waste management, as mentioned in the Chapter 14 (Physical Infrastructure) of the Master Plan for Delhi (MPD)-2021.
- (e) "Layout Plan" means a plan that will indicate the location of all existing (also proposed, if any) roads with their widths, dimensions of plots along with building lines, location of drains and public facilities, if any, a statement indicating the total area of the site under roads, and if available, then open spaces for parks, playgrounds, recreational spaces and other public spaces;

(f) "Residents' Society" means a registered Resident Society and comprising the members of the unauthorized colony/habitation which will be responsible for coordination, preparation of layout plans, and for liaison with the concerned agency in respect of various issues pertaining to the regularization process;

(g) "Service Road" - A road/lane provided at the rear or side of a plot for service purposes;

(h) "Site or Plot" - A parcel/piece of land enclosed by definite boundaries;

(i) "Social infrastructure" means social infrastructure facilities pertaining to health, education, sports facilities and socio-cultural activities and religious activities.

(j) "Street" includes any way, road, lane, square, court, alley, gully, passage, whether a thoroughfare or not and whether built upon or not, over which the public have a right of way and also the roadway or footway over any bridge or causeway;

(k) "Unauthorized colony" means a colony/development comprising of contiguous area, where no permission of concerned agency has been obtained for approval of Layout Plan, and/or building plan;

3. Criteria for Regularization of Unauthorized Colonies and Habitations

3.1 Cut off date for regularization is 31-3-2002.

3.2 Habitations that have come up as extension to village abadi and are outside the Lal Dora of village, would be eligible for regularization on the same lines as those of unauthorized colonies.

3.3 The following types of colonies or parts thereof would not be considered for regularization:

- (a) Unauthorized colonies/part of colonies/habitations falling in notified or reserved forest areas.
- (b) Unauthorized colonies/part of colonies/habitations which pose hindrances in the provision of infrastructure facilities or fall in the area of right of way (ROW) of existing/proposed railway lines; Master Plan roads and major/trunk water supply and sewerage lines.
- (c) Unauthorized colonies/habitations where more than 50% plots are un-built on the date of formal announcement of regularization scheme. However, plots, which have been built up in the above mentioned colonies, even after 31-3-2002

1075 GI/08-3

and till the date of formal announcement of regularization scheme will be taken into consideration for deciding the eligibility of the colony for regularization.

(d) Unauthorized colonies/part of colonies/habitations which violates the provisions of Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1958.

3.4 No regularization will be done in respect of residential buildings used for non-residential purposes except those covered under the mixed land use regulations contained in the MPD-2021 as may be amended from time to time. The time limit of 90 days for conducting survey for notification of mixed use streets as prescribed in clause 15.3.4 of the MPD-2021 in respect of these colonies will commence with effect from the date of notification of the colony as deemed regularized colony by the GNCTD or the date with effect from which the colony shall qualify for regularization.

3.5 Action against unauthorized constructions in unauthorized colonies/parts of colonies/habitations which do not fulfill the conditions for regularization, will be taken by concerned Local Body/DDA subject to provisions contained in Master Plan of Delhi including those in para 16.2.3.

3.6 These Regulations do not relate to unauthorized colonies/habitations inhabited by affluent sections on public and private land.

4. Procedure for regularization

The following steps are to be followed for regularization :

4.1 Registration of Residents' Society

The residents of each unauthorized colony/habitation shall establish a registered Residents Society (henceforth called as Resident Society). This shall be a pre-condition for considering the case for regularization. There would be no objection to several associations in a colony; but they would have to be federated into one recognized Residents Society. The Local Body shall only recognize and interact with such Residents Societies which have at least 75% of residents of that colony as its members.

4.2 The Resident Society shall perform/carry out the following functions :

4.2.1.1 Liaise with the concerned agency in various matters pertaining to the regularization process.

4.2.1.2 Prepare through an Architect/Town Planner, the existing layout plan of the colony. The Resident Society may, however, voluntarily also submit proposal for improved Layout Plan in respect of their colony.

4.2.1.3 The Layout Plan thus prepared shall be submitted by the Resident Society to the concerned Local Body/DDA, and simultaneously, a copy of the Layout Plan shall also be submitted to GNCTD by the Resident Society.

4.2.2 Along with the layout plan, the Resident Society shall be required to submit the complete list of members with details such as plot nos. and area of the colony to the Local Body. It shall be the duty of the Resident Society to make available, wherever possible, land to the concerned agency for taking up the works for provision of social infrastructure. In such colonies where land cannot be made available by the society for social infrastructure, the colony shall have to manage without the provision of such infrastructure.

4.2.3 There shall be no obligation on part of the Local Body/DDA/GNCTD/Union of India to allot alternate sites/plots to residents who may be displaced on account of provision of land for civic amenities/infrastructure which are not regularized as in clause 3.3.

4.2.4 The GNCTD shall determine the development charges/processing fee, if any, to be charged from the Residents Societies/individuals.

4.3 The Resident Society shall be required to submit the layout plan and proposal for improved layout plan if any. It shall be submitted in such manner and numbers as the GNCTD may deem fit.

4.4 Once sanctioned, a printed authenticated copy of the layout plan shall be made available by the Resident Society to all its members. Any deviation and modification in the sanctioned layout plan shall be subject to approval by the concerned Local Body/DDA.

4.5 Requisites for submission of Layout Plan:

4.5.1 Documents to be submitted

Application for regularization of unauthorized colonies shall be accompanied by the following documents:

(i) Land details with Khasra No. accompanied by a site plan giving the physical description of the site.

(ii) The certificates duly signed by the authorized signatory of Resident Society/owner and the Architect/Town Planner.

(iii) The layout plan submitted with the application for regularization shall be drawn to a scale of 1 : 1000 or larger and shall show details as given in the following paragraphs.

(TO BE PUBLISHED IN THE PART IV- OF THE DELHI GAZETTE)
EXTRAORDINARY
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT)
9TH Level, A-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002

No. F.24/Misc/NH/DHS/94/PF /A-2 / ^{25/8-202} Dated, the 16th May, 2008

NOTIFICATION

No. F.24/Misc/NH/DHS/94/PF /A-2 – The following draft of Rules further to amend the Delhi Nursing Homes Registration Rules, 1953, which the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make in exercise of the powers conferred by section 16 of the Delhi Nursing Homes Registration Act, 1953 (Delhi Act 6 of 1953), is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby, and notice is, hereby, given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing this notification are made available to the public, together with any objections or suggestions, that may be received in respect thereof by the stipulated period.

The objections and suggestions in this behalf should be addressed to the Director of Health Services, Government of NCT of Delhi, F-17, Karkardooma, Shahdara Delhi-110032: -

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Delhi Nursing Homes Registration (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force with immediate effect:
Provided that the nursing homes already registered on the date on which these rules come into force shall comply with these rules within a period of ninety days from the said date.
2. Amendment of rule 6. – In the Delhi Nursing Homes Registration Rules, 1953 (hereinafter referred to as "the principal Rules"), in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
“(1) An application for the renewal of registration shall be made every third year, in Form 'B' in advance in the month of January and shall be accompanied by the fee prescribed in rule 7.”
3. Substitution of new rule for rule 7. – In the principal Rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely: -
“ 7. Fees for registration and for renewal of registration for a period of three years. - (1) The fees to be paid for registration and for renewal of registration shall be charged as under: -

Bed Strength

Upto ten beds
Eleven beds to thirty beds
Thirty-one beds to one hundred beds
One hundred beds onwards

Registration /Renewal Fees

Two thousand rupees
Three thousand rupees
Eight thousand rupees
Eight thousand rupees plus one hundred twenty five rupees per bed for number of beds above one hundred beds.

- (2) Where the fee for renewal is not deposited in time as required under rule 6, a late fee amounting to ten percent of the renewal fee shall be charged per month or part thereof.
- (3) Failure to deposit the fee for renewal of registration within six months of the last date prescribed under sub-rule (1) of rule 6 shall result in refusal of the application for renewal and removal of name from the register."
4. Substitution of new rule for rule 11. – In the principal Rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely :-
- "11. Issue of duplicate certificates. – In the event of a certificate of registration being lost, mutilated or destroyed, the holder may apply to the supervising authority for a fresh certificate and the supervising authority, if it thinks fit, may issue such certificate upon payment of a fee of five hundred rupees. A certificate issued under this rule shall be marked 'DUPLICATE'."
5. Amendment of rule 12. – In the principal Rules, in rule 12, –
- (i) for the shoulder heading, the following shoulder heading shall be substituted, namely: –
- "12. Records of patients admitted or children born in the nursing home. –";
- (ii) for sub-rule (1), the following sub rule shall be substituted, namely: –
- "(1) The keeper of a nursing home shall keep --
- (a) in the Form "D" appended to these rules, a register of patients admitted into the nursing home as per the guidelines framed by the supervising authority from time to time;
- (b) a correct alphabetical index of the names of the patients admitted in the nursing home in accordance with the admission register as per Form "D";

(c) record of health of every patient admitted in the nursing home containing the following information in addition to any other information, that may be required by the supervising authority and as per guidelines framed by the supervising authority from time to time:-

- (1) Admission number
- (2) Name -----son/daughter/wife of Shri-----
- (3) Age
- (4) Sex
- (5) Occupation
- (6) Religion
- (7) Doctor in charge of the case
- (8) Date and time of admission
- (9) Date of discharge
- (10) Admitting diagnosis
- (11) Final diagnosis
- (12) Result/out come of the case
- (13) Case summary
- (14) Record of investigations
- (15) Consent
- (16) Details of operative procedure and anesthesia, if given
- (17) Records of treatment
- (18) Records of nursing care
- (19) Special record and progress notes for patient admitted in ICU/CCU
- (20) Diet
- (21) If medico legal case, date and time of information to police
- (22) Summary of Medico Legal case given to police;

(d) in the Form "E" appended to these rules, a record of every maternity case admitted into the nursing home and of every child delivered;

(e) in the Form "F 1 & F 2" appended to these rules, a record of all the miscarriages, medical termination of pregnancies and stillbirths occurring in the nursing home as per the provisions under MTP Act (F 1) and PNDT Act (F 2)."

6. Substitution of new rule for rule 13. – In the principal Rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely: -

"13. Intimation of death occurring in nursing home. – If any death occurs in the nursing home, the keeper of the nursing home shall, within twenty four hours from the occurrence of death, furnish the information in respect of such death to the supervising authorities in Form "G", together with any other information that may be required by it and to the Medical Officer of Health MCD/NDMC/Cantonment Board having jurisdiction over the area in which the nursing home is situated."

7. Substitution of new Schedule for the Schedule. – In the principal Rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :-

" SCHEDULE

(See rule 14)

Requirements to be complied with by a nursing home:

1. Location and surroundings. – The nursing home shall be situated in a place having clean surroundings and shall not be adjacent to an open sewer, drain or public lavatory or to a factory emitting smoke or obnoxious odour. The nursing home shall have sufficient facilities for parking area for the visitors, as per the municipal byelaws in force from time to time/as per norms of MPD 2021.
2. Buildings. –
 - 2.1 The building used for the nursing home shall comply with the municipal byelaws as in force and such guidelines as may be framed by the Government from time to time and the use of the premises shall conform to the land use prescribed under the relevant law(s).

2.2 The rooms in the nursing home shall be well ventilated and lighted and shall be kept in clean and hygienic conditions. Arrangements shall be made for cooling the rooms in summer and heating them in winter.

2.3 The walls of the labour room and operation theatre up to a height of 1.22 metre (4 feet) from the floor shall be of such construction as to render it waterproof. The flooring shall be such as not to permit retention or accumulation of dust. There shall be no chinks or crevices in the walls or floors.

2.4 Aseptic conditions shall be maintained in labour room and the operation room.

2.5 Adequate arrangements shall be made for isolating septic and infectious cases.

3. Space accommodation for the patients, etc. -

3.1 A nursing home providing facility for a single specialty or additional specialty shall have sufficient waiting area for the patients and attendants with proper sitting arrangements and other facilities near the reception/registration counter and shall have appropriate infrastructure according to the specialty or specialties. The floor space in the general nursing home shall not be less than 7.43 square metre (80 square feet) for one bed and additional minimum 5.57 square metre (60 square feet) for every additional bed in the room and the area shall not include the area for toilet for the patient.

3.2 A nursing home having facility for intensive care shall, in the main areas, have a space of 18.59 square meter (200 square feet) per bed. There shall be sufficient storage space for medicines and equipments (for ventilators, special beds, suction machine, transport equipment, wheel chair carts, monitors, etc.). The intensive care units shall have sturdy large shelves, wide room access with touch less door openers and outlets for battery charging. The space for doctors/staff on duty shall be in addition to the intensive care unit bed space. The supportive service rooms (changing rooms, duty rooms, attendant room) shall be near the intensive care unit. There shall be space for readily accessible storage (one for 2/4 bedded pod:

3-4 for 10 bedded ICU), crash cart alcoves (with electrical outlets), medication station, refrigerator, lockable cabinet (narcotics), countertop work area, storage cabinet/ drawers, X-ray view box:

- 3.3 Besides the main areas in the intensive care units, the ancillary areas shall include space for communication (house telephones, intercommunication system and emergency code alarm system), clerical space (filing cabinets and drawers) and public space adjacent to unit and prayer area.
- 3.4 A nursing home which intends to provide facilities for a newborn nursing or neonatal care unit shall have 4.65 square meter (50 square feet) per neonatal bed with provision of separate area for hand wash and gowning, formula preparation, stores and duty room for doctors. The floor area and walls upto 1.22 metre (4 feet) shall be washable.
4. Operation theatre and labour room. - The operation theatre shall be provided with a minimum floor space of not less than 13.94 square metre (150 square feet), and the labour room with an area of not less than 9.29 square metre (100 square feet) per table. The labour room shall have the facilities and equipments for neonatal resuscitation unit.
5. Provision of duty room. - A duty room shall be provided for the nursing staff on duty.
6. Storage space. - Adequate space for storage of medicines, food articles, equipments, etc. shall be provided.
7. Water supply. - The water used in the nursing home shall be pure and of drinkable quality.
8. Health clothing and sanitary requirements of staff. -
 - 8.1 The staff employed shall be free from contagious disease, and shall be provided with clear uniforms suitable to the nature of their duties.

- 8.2 The workers shall be medically examined at the time of employment and periodically so examined thereafter. The worker shall be vaccinated against all contagious diseases to which they are exposed or have a high risk of being exposed.
9. The equipments and Linens, etc. - The nursing home shall -
- 9.1 provide and maintain adequate number of commodes, bedpans and slop sinks, with flushing arrangements;
 - 9.2 have high pressure sterilizer and instrument sterilizer;
 - 9.3 have an uninterrupted supply of oxygen through adequate number of oxygen cylinders fitted with all necessary attachments and flow meter, for safe and hygienic delivery of oxygen to the patients;
 - 9.4 have apparatus for transfusions, necessary equipments, instruments, apparatus and medicines of such quality and numbers, as are required in accordance with to the services offered by the nursing home;
 - 9.5 have the equipments and drugs required in the neonatal resuscitation unit in the labour room and in the neonatal care unit as per guidelines framed by the supervising authority from time to time;
 - 9.6 in case providing facilities for intensive care, have monitoring, diagnostic, radiological, therapeutic/supportive and bedside facilities and availability of drugs as per the guidelines framed by the supervising authority from time to time;
 - 9.7 have adequate quantity of bed sheets, mattresses, pillows, blankets, draw sheets and other linens;
 - 9.8 have a separate almirah under lock and key for poisons.

10. Food. — If the nursing home provides diet to the patients, it shall be prepared and served in hygienic conditions.

11 Nursing Staff. —

11.1 There shall be one qualified nurse on duty at all times having minimum qualification as general nursing and midwifery course, registered with the Delhi Nursing Council, for every ten beds or a fraction thereof in the nursing home: Provided that a part of nursing staff may be substituted with the prior approval of the supervising authority by other trained staff like midwife, pharmacist, dressers, etc. according to the specific needs of the nursing home.

11.2 The nursing home providing facilities of intensive care shall have the qualified staff nurses with experience of working in a 10 bedded ICU/CCU for one year. At one point of time there shall not be more than 40% inexperienced staff nurses, who have not had experience of working in intensive care unit for one year, thus ensuring that there would be availability of minimum 60% experienced staff nurses in one shift. The staff nurses shall be available in the ratio of 1:1 round the clock and for every 10 nurses there shall be one qualified supervisor in the intensive care unit round the clock. The paramedical staff posted in the intensive care unit shall have the previous experience of working in the intensive care unit.

11.3 The nursing home providing newborn nursing or neonatal care unit, shall also have 1:1 nurses patient ratio.

12. Records. — Separate stock registers shall be maintained by the nursing home for

- (a) equipment,
- (b) instruments, and
- (c) linens.

13. Doctor. -

13.1 There shall be one qualified doctor of modern scientific system of medicine having registration with the Delhi Medical Council, round the clock for every 20 beds or fraction thereof, and the consultant of the concerned speciality shall be on call, in the nursing home.

13.2 In the nursing homes providing intensive care, there shall be a postgraduate doctor (MD) in the relevant speciality ICU. In case of nursing home providing facilities of super speciality, the consultant of relevant speciality shall be available on call. The consultant concerned shall possess requisite post-doctoral qualification:

Provided that in case of non availability of a postgraduate doctor, a doctor after graduation, having experience of working for one year in a 10 bedded general ICU/CCU under the supervision of a consultant, may be considered for working as resident doctor in the ICU/CCU. The ratio of the doctors shall be in the ratio of 1:4 beds round the clock and the consultants shall be on call.

14 Co-operation at the time of natural calamity or disaster. -

14.1 In the event of any natural calamity or disaster, the owner or the keeper of every nursing home shall, on being requested by the supervising authority in writing co-operate and provide such reasonable assistance and medical aid as may be considered essential by the supervising authority at the time of natural calamity or disastrous situation.

14.2 The nursing home shall not refuse treatment to the injured/serious persons brought to them due to any reason, whatsoever.

15. Display of charges. - The keeper of the nursing home shall ensure that the charges levied by the nursing home for the various services available in the nursing home are prominently displayed.

16. **Provision of stand by generator.** - The keeper of the nursing home shall ensure the provision of stand by generator in case of the power failure in the nursing home.
17. **Handling of biomedical waste.** - The nursing home shall abide by the Biomedical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, as amended from time to time and shall also get authorization from Delhi Pollution Control Committee under these rules.
18. **Disruption of services at a nursing home.** - Where the services of a nursing home are likely to be disrupted due to any reasons, the keeper shall give information about the same to the supervising authority, at least, four weeks in advance:

Provided that in the event of any exigency leading to disruption of services, the information shall be given to the supervising authority within twenty four hours of such disruption. "

By order and in the name of the Lt.
Governor of the National Capital Territory
of Delhi,


(VIVEK RAE)

PRINCIPAL SECRETARY (HEALTH & FAMILY WELFARE)

**GUIDELINES REGARDING BASIC REQUIREMENTS, ESSENTIAL
EQUIPMENTS AND DRUGS ETC. FOR ICU/ ICCU OPERATING IN THE
PRIVATE HOSPITALS/ NURSING HOMES**

Critical Care Units or Intensive care units are, such patients' units, which are responsible for a specifically defined and limited number of acutely ill, unstable, or potentially unstable patients who require constant instrument monitoring and a core of full time nurses and staff with specialized training. The critical care units would broadly include cardiac care units and intensive care units. The most common intensive care units are Medical Intensive Care Units (MICU), Surgical Intensive Care Units (SICU), Pediatric Intensive Care Units (PICU), Neurological Intensive Care Units (Neuro ICU), Neonatal Intensive Care Units (NICU), and Burn Units.

The intensive care units should have the following facilities

GENERAL ICUs

(A). Space Requirement

(1) Main

There should be a space of 200 square feet /bed for maintaining ICU bed. There should be sufficient storage space for medicine and equipment (for ventilators, special beds, suction machine, transport equipment, wheel chair carts, monitors etc.). It should have sturdy, large shelves, wide room access with touch less door openers and outlets for battery charging. The space for doctors, Nurses and staff on duty should be in addition to ICU bed space.

The supportive service rooms e.g. changing rooms, Duty rooms, attendant room should be near the ICU. Stand by electric supply system in case of failure of electricity must be available

Bedside (Readily accessible Storage) (one for 2/4 bedded pod; 3-4 for 10 bedded ICU)

Crash cart alcoves (with electrical outlets)

Medication station

Refrigerator

Lockable cabinet (narcotics)

h
13

Countertop work area
Storage cabinet/ Drawers
X-ray view box

(ii) Ancillary areas

a) Communication

House telephones
Intercommunication system
Emergency code alarm system

b) Clerical space (preferably separate)

Filing Cabinets, Drawers etc.

c) Public space (Adjacent to unit)

Telephone (House and public)
Prayer area

B. Equipments (Essential)

(i) **Monitoring equipments with recording data storing and analyzing facilities**

ECG machine /monitor
SpO2
Defibrillator facility
Temperature- Multiparameter
ETCo2
• NIBP
Infusion Pumps Syringe
Difficult intubation/ extubation carts
Nebulisers (Ultrasonics)

Optional

Cardiac output

(ii) **Diagnostic**

Facilities of ABG machine, Electrolyte machine,
Haematocrit, K.F.T, Glucose Measurement facilities should be available round the clock
within the ICU/Hospital

(iii) Radiological

Imaging X-rays, bedside ultrasonography facilities.

All basic imaging facilities and all investigative radiological procedure should be
available. There should be assured arrangement for CT Scan and bedside
Echocardiography facility.

(iv) Therapeutic/ Supportive

Ventilator/s

(v) Bedside Facilities

Central pipeline system for oxygen supply, vacuum suction, Blood Pressure monitoring
System, Nitrous oxide, Air for ventilators. Sufficient electrical sockets to avoid electrical
wires to crisscross, Air mattresses, Wheel Chairs, Shifting Trolleys. Adjustable bed with
overhead trolley, Detachable bed.

SPECIALISED ICUs

All other ICUs such as Neurological ICU, Neonatal ICU, Medical ICU, Surgical ICU,
should have equipments as per their requirements besides the requirements in a general
ICU.

The Neurology/ Neurosurgery ICU must have CT Scan Facility.

The Coronary Care Units (CCU) must have cardiac monitor and temporary pacing and
facilities for fluoroscopy and invasive arterial/venous pressure monitoring and Intra-
aortic balloon counter pulsation facilities.

The facilities of Coronary Angiographies as optional,

(C) Essential Drugs and Consumables

I Drugs: - There should be availability of required drugs / fluids in the ICU at all times and at no point of time there should be any shortage of drugs in the ICU.

A list of essential drugs is given below:

(i) Induction/ Sedation agents

Thiopentone
Ketamine
Propofol
Midazolam
Diazepam
Morphine
Pethidine
Pentazocine
Promethazine
Chlorpromazine

(ii) Relaxants

Suxamethonium
Vecuronium
Pancuronium
Rocuronium
Atracurium

(iii) Inotrops

Adrenaline
Noradrenaline
Dopamine
Dobutamine

(iv) Antibiotics

(v) Bronchodilators

Deriphyllin
Aminophylline

Terbutaline

Nebulisation solution (Asthline, Ipravent, Budicort, Mucolytic)

(vi) Infusions

Esmolol

Nitroglycerine

Sodium Nitroprusside

Insulin

TPN Solution

Manitol

(vii) Other drugs

Metoprolol

Furosemide

Ranitidine

Metoclopramide

Onadansetrone

Local anaesthetics (Lidocaine, Bupivacaine)

Antiarrhythmic (Adenosine, Xylocard, Cordarone, Bretyllium)

Vitamine K

Low Molecular Weight Heparin

Diltiazem

Diclofenac

Tramadol

Atropine

PAM

Inj. Avil

Inj. Decadron

Inj. Hydrocortisone

Inj. Stemetil

Inj. Emeset

Inj. Digoxin

Glycopyrrolate

Neostigmine

Calcium Gluconate
Sodabcarb
Inj Potassium Chloride and Syrup Potassium Chloride
Magnesium
Multivitamins
Local anaesthetic jelly
Eye ointment
Antiseptic solutions and ointments
Cleaning / disinfecting solutions
Antisnake venome
Colloids (Polygeline, Starches, Dextrans, Albumin)
Mexiletine

II. Consumables

Endotracheal tubes (all sizes)
Tracheostomy tubes all sizes)
LMAs (including ILMA) (all sizes)
Face masks (all sizes)
Oropharyngeal airways (all sizes)
Nasopharyngeal airways (all sizes)
Non touch suction apparatus
Suction catheters (all sizes)
Heat and Moisture exchangers (For use with ETT, Tracheostomy tube)
Incentive spirometers
I/V Cannulae
Three ways
CVP lines (all sizes)
Intra-arterial Cannulae
Foley's Catheters
Nasogastric tubes
CPAP Masks
Venturi Mask
Binasal Cannulae

Nasal Spectacle
Percutaneous dilatation tracheostomy set
Sterile dressings
Disposable Gloves, Masks, Syringes and needles, Shoe Covers.
Temporary pacing leads 6F, 7F
Temporary pulse generator
Check Flow (5-7F) and Swan Ganz Catheter
Arterial Puncture Needle.
Sterile drape Sheets

(D). Staff requirement

(i) Doctors

There should be a post graduate doctor (MD) in the relevant specialty ICU and the consultant of relevant specialty should be available on call, in case of super-specialty. The consultant concerned must possess requisite post-doctoral qualification. In case of non availability of a post graduate doctor, a doctor after graduation, having experience of working for one year in a 10 bedded general ICU/CCU under the supervision of a consultant may be considered for working as Resident doctor in ICU/CCU. The doctors should be registered with Delhi Medical Council and the ratio of the doctors should be in the ratio 1:4 beds round the clock and the consultants should be on call.

(ii) Nursing Staff

There should be staff nurses with minimum qualification as General Nursing and Midwifery Course; having registration with Delhi Nursing council with an experience of working in a 10 bedded ICU/CCU for one year. At one point of time there should not be more than 40 % inexperienced staff nurses, who have not had experience of working in ICU for a period of one year, thus ensuring that there would be availability of minimum 60% experienced staff nurses in one shift. The staff nurses should be available in the ratio of 1:1 round the clock and for every 10 nurses there should be one Qualified Supervisor in the ICU round the clock.

(iii) **Paramedical Staff**

The paramedical staff posted in the ICU should have the previous experience of working in the ICU.

(E) General services

- Fire safety features
- Air conditioning / Heating
- Grounded electric points
- Emergency Power source
- Circuit Breaker access
- Proper Lighting

The facilities for transport of the patients to other Hospitals or High Centres should be available with each of the ICU/ICCU.

These recommendations have been made to be the guidelines for an ICU/ICCU and are not exhaustive, and they may need revision from time to time.

**BASIC REQUIREMENT OF ESSENTIAL EQUIPMENTS AND DRUGS IN
THE NEWBORN CARE UNIT/NEONATAL CARE UNIT AND NEONATAL
RESUSCITATION UNIT IN NURSING HOMES**

Newborn care unit:

1. A nursing home intending to provide a newborn care unit shall have the following essential equipments and facilities:-

- a) A stethoscope with neonatal chest-piece for each Neo-natal bed
- b) Baby weighing machine
- c) Oxygen hood box and other oxygen delivery apparatus like humidifier and regulator
- d) Phototherapy unit
- e) Uninterrupted availability of oxygen and compressed air
- f) Oxygen analyzer (oximeter)
- g) Non-invasive blood pressure monitor
- h) Heart rate and/or apnea monitor
- i) Newborn resuscitation kit.
- j) Transport incubator
- k) Suction machine
- l) Air thermometer
- m) Radiant heat source

There shall be facilities to get requisite biochemical and hematological test done round the clock, as may be required for management of a sick baby, facilities for infection control such as uninterrupted water supply and isolation of infected babies, safe and adequate method for handling of soiled and dirty linen or other infected waste.

Neonatal resuscitation unit in labour room :

- a) A functioning wall clock with seconds arm or a stop clock.
- b) Radiant heat source.
- c) Pressure controlled suction machine and requisite number of mucus extractors.
- d) Two working infant laryngoscopes with neonatal sized blades.
- e) Requisite facilities for IPPR with self-inflating bag, well fitting neonatal facemask, endotracheal tubes and appropriate adapters.
- f) Umbilical vein cannulations set.
- g) Baby weighing machine.
- h) Essential drugs needed during resuscitation.

**GUIDELINES FOR MAINTAINING RECORDS OF THE PATIENTS IN THE
NURSING HOMES**

The nursing homes shall maintain the records as per the format given below in the Forms

FORM "D" Register of patients admitted

FORM "E" Records of every maternity cases admitted in the nursing home.

FORM "F" Records of miscarriages, MTP cases and still births occurring in the
F₁ & F₂ nursinghomes & PNDT Act

FORM "G" Records of deaths occurring in the nursing homes

h

(22)

4

7-11-68

1.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Outcome or/
and remarks

10

FORM "D"

(See rule 12)

Register of patients admitted to _____ Nursing home, _____

Adm n. No.	Name S/o, D/o, W/o & Addre ss	Age/Sex	Date & time of Admn	Admitting diagnosis	Final diagnosis	Doctor I/C of case	Date & time of discharge/ Death/ LAMA	Whether MLC (Y/N)	Outcome or / and remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....(Name and qualification of the Registered Medical practitioner in block letters)

..... (Full address of the Registered Medical practitioner)

..... (Name and qualification of the Registered Medical practitioner in block letters)

..... (Full address of the Registered Medical practitioner)

hereby certify that *I/ We am/are of opinion, formed in good faith, that it is necessary to terminate the pregnancy of.....(Full name of pregnant women in block letters) resident of(Full name of pregnant women in block letters)

for the reasons given below**

*I/we hereby give intimation that *I/We terminated the pregnancy of the woman referred to above who bears the serial no.....in the Admission Register of the hospital/approved place.

Signature of the registered Medical Practitioner/Practitioners

Place:

Date:

- Strike out whichever is not applicable.
- Of the reasons specified items (i) to (v) write the one which is appropriate.
 - (i) in order to save the life of the pregnant women,
 - (ii) in order to prevent grave injury to the physical and mental health of the pregnant women,
 - (iii) in view of the substantial risk that if the child was born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped,
 - (iv) as the pregnancy is alleged by pregnant women to have been caused by rape,
 - (v) as the pregnancy has occurred as result of failure of any contraceptive device or methods used by married woman or her husband for the purpose of limiting the number of children.

Note—Account may be taken of the pregnant women's actual or reasonably foreseeable environment in determining whether the continuance of her pregnancy would involve a grave injury to her physical or mental health.

Place:

Date:

Signature of the registered Medical Practitioner/Practitioners

h

[See Regulation 4(5)]
Medical Termination of Pregnancy Act Report for the Month of _____

East District, Delhi

1. (i) No. of Institution approved _____

(ii) No. of Institution reporting _____

For the Month _____

2. Total no. of M.T.P case done _____

3. Break up of the total no. of cases

(i). Duration of pregnancy (give total No. only)

(a)	Up to 12 weeks.	
(b)	Up to 12-20 weeks.	

(ii). Age group

(a)	Less than 15	
(b)	15--19	
(c)	20--24	
(d)	25--29	
(e)	30--34	
(f)	35--39	
(g)	40--44	
(h)	45 & above	
(i)	not available	

Total = _____

(iii). Religion of women

(a)	Hindu	
(b)	Muslim	
(c)	Christian	
(d)	Others	
	Total	

(iv). Reasons for termination:

(give total number under each sub-head)

(a)	Danger to life of the pregnant woman.	
(b)	Grave injury to the physical health of the pregnant woman.	
(c)	Grave injury to the mental health of the pregnant woman.	
(d)	Pregnancy cause by rape.	
(e)	Substantial risk that if the child was born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped.	
(f)	Failure of any contraceptive device or method.	
(g)	Not available	

4. Termination with acceptance of contraception.

(a)	Sterilisation	
(b)	I.U.D.	

5. No. of Death Reported _____

Signature of the Officer In charge with Date

h



16 F-1
22
FORM III
(See Regulation 5)

Admission Register

S. No.	Date of Admission	Name of the patient	Wife / Daughter of	Age	Religion	Address
1	2	3	4	5	6	7

Duration Of Pregnancy	Reasons on Which Pregnancy Is Terminated	Date of termination Of Pregnancy	Date of Discharge Of patient	Result and Remarks	Name of Registered Medical Practitioner (s) by who the opinion is formed	Name of Registered medical practitioner (s) by whom pregnancy is terminated
8	9	10	11	12	13	14

h

F-2 13
"FORM A"

[See rules 4(1) and 8(1)]

(To be submitted in Duplicate with supporting documents as enclosures)

APPLICATION FOR REGISTRATION OR RENEWAL OF REGISTRATION OF A GENETIC COUNSELLING CENTRE/GENETIC LABORATORY/GENETIC CLINIC/ULTRASOUND CLINIC/IMAGING CENTRE

1. Name of the applicant
(Name of the organisation sought to be registered)
2. Address of the applicant
3. Type of facility to be registered
(Please specify whether the application is for registration of a Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre or any combination of these)
4. Full name and address/addresses of Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ Ultrasound Clinic/Imaging Centre with Telephone/Fax number(s)/Telegraphic/Telex/E-mail address (s).
5. Type of ownership of Organisation (individual ownership/partnership/company/co-operative/any other to be specified). In case type of organization is other than individual ownership, furnish copy of articles of association and names and addresses of other persons responsible for management, as enclosure.
6. Type of Institution (Govt. Hospital/Municipal Hospital/Public Hospital/Private Hospital/Private Nursing Home/Private Clinic/Private Laboratory/any other to be stated.)
7. Specific pre-natal diagnostic procedures/tests for which approval is sought
(a) Invasive (i) amniocentesis/ chorionic villi aspiration
/chromosomal/biochemical/molecular studies
(b) Non-Invasive Ultrasonography
Leave blank if registration is sought for Genetic Counselling Centre only.
8. Equipment available with the make and model of each equipment (List to be attached on a separate sheet).
9. (a) Facilities available in the Counselling Centre.
(b) Whether facilities are or would be available in the Laboratory/Clinic for the following tests:
- | | |
|-------|----------------------------|
| (i) | Ultrasound |
| (ii) | Amniocentesis |
| (iii) | Chorionic villi aspiration |
| (iv) | Foetoscopy |
| (v) | Foetal biopsy |
| (vi) | Cordocentesis |
- Whether facilities are available in the Laboratory/ Clinic for the following:
- | | |
|-------|-----------------------------------|
| (i) | Chromosomal studies |
| (ii) | Biochemical studies |
| (iii) | Molecular studies |
| (iv) | Preimplantation genetic diagnosis |
10. Names, qualifications, experience and registration number of employees (may be furnished as an enclosure).
11. State whether the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ultrasound clinic/imaging centre ^(b) qualifies for registration in terms of requirements laid down in Rule 3]
- h

INFORMATION

I, Sh./Smt./Kum./Dr. son/daughter/wife of aged years, working as in (indicate name of the organisation to be registered) hereby declare that I have read and understood the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994) and the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1996.

I also undertake to explain the said Act and Rules to all employees of the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ultrasound clinic/imaging centre in respect of which registration is sought and to ensure that the Act and Rules are fully complied with.

Date:

Place:

authorized to

(.....)
Name, designation and signature of the person
sign on behalf of the organisation to be registered

[SEAL OF THE ORGANISATION SOUGHT TO BE REGISTERED]

ACKNOWLEDGEMENT
[See Rules 4(2) and 8(1)]

The application in Form A-in duplicate for grant*/renewal* of registration of Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre* by (Name and address of applicant) has been received by the Appropriate Authority On (date).

*The list of enclosures attached to the application in Form A has been verified with the enclosures submitted and found to be correct.

OR

*On verification it is found that the following documents mentioned in the list of enclosures are not actually enclosed.
This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

Date:
Place:

(.....)
Signature and Designation of Appropriate Authority, or authorized
person in the
Office of the Appropriate Authority.

SEAL

ORIGINAL/DUPLICATE FOR DISPLAY
FORM B
[See Rules 6(2), 6(5) and 8(2)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION
(To be issued in duplicate)

In exercise of the powers conferred under Section 19 (1) of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994), the Appropriate Authority hereby grants registration to the Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre* named below for purposes of carrying out Genetic Counselling/Pre-natal Diagnostic Procedures*/Pre-natal Diagnostic Tests/ultrasonography under the aforesaid Act for a period of five years ending on

2. This registration is granted subject to the aforesaid Act and Rules thereunder and any contravention thereof shall result in suspension or cancellation of this Certificate of Registration before the expiry of the said period of five years apart from prosecution:

- A. Name and address of the Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*.
- B. Pre-natal diagnostic procedures* approved for (Genetic Clinic).
 - Non-Invasive
 - (i) Ultrasound
 - Invasive
 - (ii) Amniocentesis
 - (iii) Chorionic villi biopsy
 - (iv) Foetoscopy
 - (v) Foetal skin or organ biopsy
 - (vi) Cordocentesis
 - (vii) Any other (specify)
- C. Pre-natal diagnostic tests* approved (for Genetic Laboratory)
 - (i) Chromosomal studies
 - (ii) Biochemical studies
 - (iii) Molecular studies
- D. Any other purpose (please specify)

3. Model and make of equipments being used (any change is to be intimated to the Appropriate Authority under rule 13).

4. Registration No. allotted

5. Period of validity of earlier Certificate of Registration.
(For renewed Certificate of Registration only)

From To

Signature, name and designation of
The Appropriate Authority

Date:

SEAL

DISPLAY ONE COPY OF THIS CERTIFICATE AT A CONSPICUOUS PLACE AT THE PLACE OF BUSINESS

4

(26)

F-2 16

FORM C
[See Rules 6(3), 6(5) and 8(3)]

FORM FOR REJECTION OF APPLICATION FOR GRANT/RENEWAL OF REGISTRATION

In exercise of the powers conferred under Section 19(2) of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, the Appropriate Authority hereby rejects the application for grant/renewal of registration of the undermentioned Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*.

- (1) Name and address of the Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*
- (2) Reasons for rejection of application for grant/renewal of registration:

Signature, name and designation of
the Appropriate Authority with SEAL of Office

Date:
Place:

*Strike out whichever is not applicable or necessary.

4

(31)

F-2/5

FORM D
[See rule 9(2)]

FORM FOR MAINTENANCE OF RECORDS BY THE GENETIC COUNSELLING CENTRE

1. Name and address of Genetic Counselling centre.
2. Registration No.
3. Patient's name
4. Age
5. Husband's/Father's name
6. Full address with Tel. No., if any
7. Referred by (Full name and address of Doctor(s) with registration No.(s)
(Referral note to be preserved carefully with case papers)
8. Last menstrual period/weeks of pregnancy
9. History of genetic/medical disease in the family (specify)
Basis of diagnosis:
(a) Clinical
(b) Bio-chemical
(c) Cytogenetic
(d) Other (e.g. radiological, ultrasonography)
10. Indication for pre-natal diagnosis
A. Previous child/children with:
(i) Chromosomal disorders
(ii) Metabolic disorders
(iii) Congenital anomaly
(iv) Mental retardation
(v) Haemoglobinopathy
(vi) Sex linked disorders
(vii) Single gene disorder
(viii) Any other (specify)
B. Advanced maternal age (35 years or above)
C. Mother/father/sibling having genetic disease (specify)
D. Others (specify)
11. Procedure advised²⁽²⁾
(i) Ultrasound
(ii) Amniocentesis
(iii) Chorionic villi biopsy
(iv) Foetoscopy

(v) Foetal skin or organ biopsy
(vi) Cordocentesis
(vii) Any other (specify)
12. Laboratory tests to be carried out
(i) Chromosomal studies
(ii) Biochemical studies
(iii) Molecular studies
(iv) Preimplantation genetic diagnosis
13. Result of diagnosis
If abnormal give details. Normal/Abnormal
14. Was MTP advised?
15. Name and address of Genetic Clinic* to which patient is referred.
16. Dates of commencement and completion of genetic counseling.

h

(32)

F-2 15
FORM E
(See Rule 9(3))

FORM FOR MAINTENANCE OF RECORDS BY GENETIC LABORATORY

2. Name and address of Genetic Laboratory
3. Registration No
4. Patient's name
5. Age
6. Husband's/Father's name
7. Full address with Tel. No., if any
8. Referred by/sample sent by (full name and address of Genetic Clinic) (Referral note to be preserved carefully with case papers)
9. Type of sample: Maternal blood/Chorionic villus sample/amniotic fluid/Foetal blood or other foetal tissue (specify)
10. Specify indication for pre-natal diagnosis
 - A. Previous child/children with
 - (i) Chromosomal disorders
 - (ii) Metabolic disorders
 - (iii) Malformation(s)
 - (iv) Mental retardation
 - (v) Hereditary haemolytic anaemia
 - (vi) Sex linked disorder
 - (vii) Single gene disorder
 - (viii) Any other (specify)
 - B. Advanced maternal age (35 years or above)
 - C. Mother/father/sibling having genetic disease (specify)
 - D. Other (specify)
11. Laboratory tests carried out (give details)
 - (i) Chromosomal studies
 - (ii) Biochemical studies
 - (iii) Molecular studies
 - (iv) preimplantation genetic diagnosis
12. Result of diagnosis
If abnormal give details. Normal/Abnormal
13. Date(s) on which tests carried out.
14. The results of the Pre-natal diagnostic tests were conveyed to on

Place:
Date:

Name, Signature and Registration No. of the
Medical Geneticist/Director of the Institute

h

(25)

F-2

FORM F

[See Proviso to Section 4(3), Rule 9(4) and Rule 10(1A)]

FOR MAINTENANCE OF RECORD IN RESPECT OF PREGNANT WOMAN BY GENETIC CLINIC/ULTRASOUND CLINIC/IMAGING CENTRE

Name and address of the Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre.

Registration No.

Patient's name and her age

Number of children with sex of each child

Husband's/Father's name

Full address with Tel. No., if any

Referred by (full name and address of Doctor(s)/Genetic Counselling Centre (Referral note to be preserved carefully with case papers)/self referral

Last menstrual period/weeks of pregnancy

History of genetic/medical disease in the family (specify)
Basis of diagnosis:

- (a) Clinical
- (b) Bio-chemical
- (c) Cytogenetic
- (d) Other (e.g. radiological, ultrasonography etc. specify)

0. Indication for pre-natal diagnosis

A. Previous child/children with:

- (i) Chromosomal disorders
- (ii) Metabolic disorders
- (iii) Congenital anomaly
- (iv) Mental retardation
- (v) Haemoglobinopathy
- (vi) Sex linked disorders
- (vii) Single gene disorder
- (viii) Any other (specify)

B. Advanced maternal age (35 years)

C. Mother/father/sibling has genetic disease (specify)

D. Other (specify)

11. Procedures carried out (with name and registration No. of Gynaecologist/Radiologist/Registered Medical Practitioner) who performed it.

Non-invasive

- (i) Ultrasound (specify purpose for which ultrasound is to done during pregnancy)
[List of indications for ultrasonography of pregnant women are given in the note below]

Invasive

- (ii) Amniocentesis
- (iii) Chorionic Villi aspiration
- (iv) Foetal biopsy
- (v) Cordocentesis
- (vi) Any other (specify)

Any complication of procedure - please specify

h

(34)

pre-natal diagnostic procedure
(b) Ultrasonography
specify abnormality detected, if any).

Normal/Abnormal

Date(s) on which procedures carried out.

16. Date on which consent obtained. (In case of invasive)
17. The result of pre-natal diagnostic procedure were conveyed to on
18. Was MTP advised/conducted?
19. Date on which MTP carried out.

Date:
Place

Name, Signature and Registration number of the
Gynaecologist/Radiologist/Director of the Clinic

DECLARATION OF PREGNANT WOMAN

I, Ms. _____ (name of the pregnant woman) declare that by undergoing ultrasonography /image scanning I do not want to know the sex of my foetus.

Signature/Thumb impression of pregnant woman

3 Strike out whichever is not applicable or not necessary

DECLARATION OF DOCTOR/PERSON CONDUCTING ULTRASONOGRAPHY/IMAGE SCANNING

I, _____ (name of the person conducting ultrasonography/image scanning) declare that while conducting ultrasonography/image scanning on Ms. _____ (name of the pregnant woman), I have neither detected nor disclosed the sex of her foetus to any body in any manner.

Name and signature of the person conducting ultrasonography/image scanning
Director or owner of genetic clinic/ultrasound clinic/imaging centre

Important Note:

- (i) Ultrasound is not indicated/advised/performed to determine the sex of foetus except for diagnosis of sex-linked diseases such as Duchenne Muscular Dystrophy, Haemophilia A & B etc.
- (ii) During pregnancy Ultrasonography should only be performed when indicated. The following is the representative list of indications for ultrasound during pregnancy:
- (1) To diagnose intra-uterine and/or ectopic pregnancy and confirm viability.
 - (2) Estimation of gestational age (dating).
 - (3) Detection of number of foetuses and their chorionicity.
 - (4) Suspected pregnancy with IUCD in-situ or suspected pregnancy following contraceptive failure/MTP failure.
 - (5) Vaginal bleeding / leaking.
 - (6) Follow-up of cases of abortion.
 - (7) Assessment of cervical canal and diameter of internal os.
 - (8) Discrepancy between uterine size and period of amenorrhoea.
 - (9) Any suspected adnexal or uterine pathology / abnormality.
 - (10) Detection of chromosomal abnormalities, foetal structural defects and other abnormalities and their follow-up.
 - (11) To evaluate foetal presentation and position.
 - (12) Assessment of liquor amnii.
 - (13) Preterm labour / preterm premature rupture of membranes.
 - (14) Evaluation of placental position, thickness, grading and abnormalities (placenta praevia, retroplacental haemorrhage, abnormal adherence etc.).
 - (15) Evaluation of umbilical cord - presentation, insertion, nuchal encirclement, number of vessels and presence of true knot.
 - (16) Evaluation of previous Caesarean Section scars.
 - (17) Evaluation of foetal growth parameters, foetal weight and foetal well being.
 - (18) Colour flow mapping and duplex Doppler studies.
 - (19) Ultrasound guided procedures such as medical termination of pregnancy, external cephalic version etc. and their follow-up.
 - (20) Adjunct to diagnostic and therapeutic invasive interventions such as chorionic villus sampling (CVS).

F-2
11

FORM G
[See Rule 10]
FORM OF CONSENT
(For invasive techniques)

I, wife/daughter of Age years resident
..... hereby state that I have been explained fully the probable side effects and after effects of
the pre-natal diagnostic procedures.

I wish to undergo the preimplantation/pre-natal diagnostic technique/test/procedures in my own interest to avoid
the possibility of any abnormality (i.e. disease/deformity/disorder) in the child I am carrying.

I undertake not to terminate the pregnancy if the pre-natal procedure/technique/test conducted show the abnormality
disease/deformity/disorder.

I understand that the sex of the foetus will not be disclosed to me.

I understand that breach of this undertaking will make me liable to penalty as prescribed in the Pre-natal Diagnostic
Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994) and rules framed thereunder.

Date
Place

Signature of the pregnant woman.

I have explained the contents of the above to the patient and her companion (Name
Address Relationship) in a language she/they understand.

Name, Signature and/Registration number of
Gynaecologist/Medical Geneticist/Radiologist/Paediatrician
Director of the Clinic/Centre/Laboratory

Date

Name, Address and Registration number of
Genetic Clinic/Institute

SEAL

h

ab

FORM H
[See Rule 9(5)]

FORM FOR MAINTENANCE OF PERMANENT RECORD OF APPLICATIONS FOR GRANT/REJECTION/REGISTRATION UNDER THE PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (REGULATION AND PREVENTION OF MISUSE) ACT, 1994.

1. Sl. No.
2. File number of Appropriate Authority.
3. Date of receipt of application for grant of registration.
4. Name, Address, Phone/Fax etc. of Applicant.
5. Name and address(es) of Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*.
6. Date of consideration by Advisory Committee and recommendation of Advisory Committee, in summary.
7. Outcome of application (state granted/rejected and date of issue of orders - record date of issue of order in Form B or Form C).
8. Registration number allotted and date of expiry of registration.
9. Renewals (date of renewal and renewed upto).
10. File number in which renewals dealt.
11. Additional information, if any.

Name, Designation and Signature of
Appropriate Authority

Guidance for Appropriate Authority

- (a) Form H is a permanent record to be maintained as a register, in the custody of the Appropriate Authority.
- (b) * Means strike out whichever is not applicable.
- (c) On renewal, the Registration Number of the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre will not change. A fresh registration Number will be allotted in the event of change of ownership or management.
- (e) Registration number shall not be allotted twice.
- (f) Each Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ Ultrasound Clinic/Imaging Centre must be allotted a folio consisting of two pages of the Register for recording Form H.
- (g) The space provided for 'additional information' may be used for recording suspension, cancellations, rejection, application for renewal, change of ownership/management, outcome of any legal proceedings, etc.
- (h) Every folio (i.e. 2 pages) of the Register shall be authenticated by signature of the Appropriate Authority with every subsequent entry shall also be similarly authenticated.*

(Ms. K. Sujatha)
Joint Secretary to the Government of

[No.N.24026/14/2002-PND]

Footnote:- The Principal Notification was published in the Gazette of India vide No.G.S.R. 1(E) dated 1st January 1995. This is the first amendments to the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1994.

FORM "G"

(See rule 13)

FORMAT FOR DEATH REGISTER

[illegible]

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनाथ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
9वां तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-02

सं.फा. 24/विविध/डीएचएस/94/पीएफ/ए-2/25186-202 दिनांक- 16.5.08

अधिसूचना

सं.फा. 24/विविध/ एन एच /डीएचएस/94/पीएफ/ए-2/ - दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण नियमावली, 1953 का फिर से संशोधन करने के लिये नियमावली का निम्नलिखित प्रारूप, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल, दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 (1953 का दिल्ली अधिनियम 6) की धारा, 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाना प्रस्तावित करते हैं, वह इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां, जिस तिथि से जनता को उपलब्ध होती हैं, उस तिथि से तीस दिन के अवधि बीतने के पश्चात् इस संबंध में निर्धारित अवधि तक प्राप्त होने वाले किन्हीं आपत्तियों या सुझावों के साथ विचार किया जायेगा।

इस संबंध में आपत्तियां तथा सुझाव निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, दिल्ली सरकार, एफ-17, कडकड़डूमा, शाहदरा, दिल्ली-110032 को भिजवाए जाने चाहिये।

प्रारूप नियमावली

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :- (1) इन नियमों को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जा सकता है।
- ये तत्काल प्रभावी होंगे।
शर्त यह है कि जिस तिथि से ये नियम प्रवृत्त होते हैं, उस तिथि को पहले ही पंजीकृत नर्सिंग होम उक्त तिथि से नब्बे दिन के अवधि के भीतर इन नियमों का पालन करेंगे।
- नियम 6 का संशोधन : दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण नियमावली, 1953 (इसके पश्चात् "मूल नियमावली" के रूप में संदर्भित) के नियम 6 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रति स्थापित किया जायेगा अर्थात् (1) "पंजीकरण के नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्रत्येक तीसरे वर्ष जनवरी माह में फार्म ख अग्रिम में किया जायेगा और इसके साथ नियम 7 में निर्धारित शुल्क लगा होगा"।
- नियम 7 के स्थान पर नये नियम का प्रतिस्थापन :- मूल नियमावली के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :
7. 'तीन वर्ष की अवधि के लिये पंजीकरण तथा पंजीकरण का नवीनीकरण का शुल्क (1) पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये भुगतान किये जाने वाला शुल्क निम्न प्रकार से वसूल किया जायेगा :

बिस्तारों की संख्या	पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क
दस बिस्तारों तक	दो हजार रुपये
ग्यारह से तीस बिस्तार	तीन हजार रुपये

इकतीस से एक सौ बिस्तर	आठ हजार रुपये
एक सौ से अधिक बिस्तर	आठ सौ रुपये तथा एक सौ से अधिक बिस्तरों की संख्या के लिये एक सौ पच्चीस रुपये प्रति बिस्तर

(2) जहां नियम 6 के अनुसार नवीनीकरण का शुल्क यथासमय जमा नहीं कराया जाता है, वहां नवीनीकरण शुल्क की दस प्रतिशत राशि के बराबर राशि विलम्ब शुल्क के रूप में प्रतिमाह या इसके भाग के लिये जमा करानी होगी।

(3) नियम 6 के उप नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित अन्तिम तिथि से छः माह के भीतर पंजीकरण के नवीनीकरण का शुल्क जमा कराने में विफलता के परिणामस्वरूप नवीनीकरण के आवेदन-पत्र का अस्वीकरण होगा।

4. नियम 11 के स्थान पर नये नियम का प्रतिस्थापन— मूल नियमावली के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :-

11 "डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना —

यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाता है, विकृत या नष्ट हो जाता है तो वह नये प्रमाण पत्र के लिये पर्यवेक्षक प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और पर्यवेक्षक प्राधिकारी यदि उचित समझते हैं तो पांच सौ रुपये के शुल्क के भुगतान करने पर ऐसा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। इस नियम के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र पर "डुप्लीकेट" उल्लिखित होगा।

5. नियम 12 का संशोधन— मूल नियमावली के नियम 12 में —

- (i) मुख्य शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :
"12 नर्सिंग होम में दाखिल रोगी या जन्म शिशु का अभिलेख"
- (ii) उप नियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित शामिल किया जायेगा। अर्थात् "(i) किसी नर्सिंग होम का रखने वाला निम्नलिखित रखेगा —

(क) समय-समय पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार नर्सिंग होम में दाखिल रोगियों का रजिस्टर इन नियमों के साथ संलग्न फार्म "डी" में,

(ख) फार्म "डी" में प्रवेश रजिस्टर के अनुसार नर्सिंग होम में दाखिल रोगियों के नाम, सही वर्णक्रम के अनुसार,

(ग) किसी अन्य जानकारी के अतिरिक्त नर्सिंग होम में दाखिल प्रत्येक रोगी के स्वास्थ्य का अभिलेख निम्नलिखित जानकारी सहित जो पर्यवेक्षक अधिकारी को समय-समय पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा बनाये गये मार्ग निर्देशों के अनुसार चाहिये:-

1. प्रवेश संख्या
2. नाम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
3. आयु य
4. लिंग
5. व्यवसाय
6. धर्म

7. केस का प्रभारी डाक्टर
8. प्रवेश का समय व तिथि
9. छुट्टी देने की तिथि :
10. प्रवेश के समय रोग निदान
11. अन्तिम निदान
12. मामले का परिणाम/नतीजा
13. मामले का सारांश
14. जांच का अभिलेख
15. परामर्श
16. शल्यचिकित्सा प्रक्रिया का विवरण तथा संवेदनाहरण यदि किया गया हो ।
17. उपचार का अभिलेख
18. नर्सिंग देखभाल का अभिलेख
19. आईसीयू/आईसीसीयू में दाखिल रोगियों के लिये विशेष अभिलेख तथा प्रगति
20. आहार
21. यदि चिकित्सीय टीम कानूनी मामला है तो पुलिस को सूचना देने की तिथि और समय
22. पुलिस को सौंपे चिकित्सीय कानूनी मामले का सारांश

(घ) इस नियमों के साथ संलग्न फार्म "ड" में नर्सिंग होम में दाखिल प्रत्येक प्रसूति मामले और वहां पैदा हुये प्रत्येक शिशु का अभिलेख

(ङ) इन नियमों के साथ संलग्न फार्म "घ 1 तथा घ 2" में नर्सिंग होम में हुये गर्भपात, चिकित्सीय गर्भ समापन तथा मृत जन्में शिशुओं का सारा अभिलेख होगा तथा वे एमटीपी अधिनियम (एफ-1) तथा पी एन डी टी अधिनियम (एफ-2) के प्रावधानों का अनुसरण करेंगे ।

6. नियम 13 के स्थान पर नये नियम का प्रतिस्थापन : मूल नियमावली के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"13. नर्सिंग होम में हुई मृत्यु की सूचना :-
यदि कोई मृत्यु नर्सिंग होम में होती है तो नर्सिंग होम का संचालक (कीपर) मृत्यु होने के चौबीस घंटों के भीतर ऐसी मृत्यु के संबंध में पर्यवेक्षण प्राधिकारी को फार्म "जी" में, जिस स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी एमसीडी / एनडीएमसी/केन्टोमैन्ट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में नर्सिंग होम स्थित है, उस स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी अन्य जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगा ।"

7. अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन :- मूल नियमावली की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् :-

**अनुसूची
(नियम 14 देखिए)**

किसी नर्सिंग होम द्वारा पालन की जाने वाली अपेक्षाएं

1. **स्थान और आसपास :-** नर्सिंग होम का स्थान और उसके आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा होगा और किसी खुली सीवर लाइन, नाले या जनता शौचालय के निकट नहीं होगा या धुआं छोड़ने वाले या गंदी/विषैली दुर्गंध छोड़ने वाले कारखाने के निकट नहीं होगा। नर्सिंग होम के पास समय-समय पर प्रचलित नगर निगम उपविधियों एम पी डी 2021 के अनुसार आगुन्तकों के लिये पार्किंग क्षेत्र की पर्याप्त सुविधायें होंगी।
2. **भवन :-**
 - 2.1 नर्सिंग होम के लिये प्रयुक्त भवन प्रचलित नगर निगम उप विधियों का और समय-समय पर सरकार द्वारा बनाए गये ऐसे दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे और परिसर का प्रयोग सम्बद्ध कानून/कानूनों में निर्धारित भूमि प्रयोग के अनुरूप करेगा।
 - 2.2 नर्सिंग होम के कमरे सुवातित (हवादार) प्रकाश वाले होंगे और उन्हें साफ सुथरा स्वास्थ्य कर परिस्थितियों में रखा जायेगा। गर्मियों में कमरे ठण्डे रखने और सर्दियों में गर्म रखने की व्यवस्था होगी।
 - 2.3 प्रसव कक्ष और शल्य चिकित्सा मंच की दीवार तल से 1.22 मीटर (4फुट) की ऊंचाई तक इस तरह निर्मित होगी ताकि यह जलरोधक हो। फर्श ऐसे होंगे कि उन पर धूल नहीं जमी होगी। दीवारों या तलों में किसी प्रकार की छेद या सुराख/तेराड़ नहीं होंगे।
 - 2.4 प्रसव कक्ष और आपरेशन कक्ष एसेप्टिक होंगे।
 - 2.5 सेप्टिक तथा संक्रामक मामलों को अलग रखने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।
3. **रोगियों के लिये आवास, स्थान आदि :-**
 - 3.1 किसी एक विशेषज्ञता या अतिरिक्त विशेषज्ञता के लिये सुविधा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम में रोगियों तथा उनके परिचरों के लिये पर्याप्त बैठने की व्यवस्था तथा अन्य सुविधा वाला पर्याप्त प्रतीक्षा क्षेत्र स्वागत/पंजीकरण काउंटर के समीप होना चाहिये और विशेषज्ञता के अनुसार पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य नर्सिंग होम में तल क्षेत्र 7.43 वर्ग मीटर (80 वर्ग फुट) एक बिस्तर के लिये तथा कमरे में प्रत्येक अतिरिक्त बिस्तर के लिये 5.57 वर्ग मीटर (60 वर्ग फुट) से कम नहीं होना चाहिये तथा इसमें रोगियों के लिये शौचालय का क्षेत्र शामिल नहीं होगा।
 - 3.2 सघन चिकित्सा कक्ष की सुविधा वाले नर्सिंग होम में मुख्य क्षेत्र में 18.50 वर्ग मीटर (200 वर्ग फुट) प्रति बिस्तर का स्थान होना चाहिये। इसमें दवाईयां तथा उपकरणों (वेंटिलेटर, विशेष बिस्तर, सक्शन मशीन, परिवहन उपकरण, व्हील चेयर कार्ट, मोनिटर आदि) को रखने के लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिये। सघन चिकित्सा युनिटों में बड़े-बड़े सेल्फ, चौड़े दरवाजे जो बिना छुए खुले तथा बैटरी चार्जिंग के स्थान होने चाहिये। डॉक्टरों/

ड्यूटी पर स्टाफ के लिये स्थान सघन चिकित्सा कक्ष के अतिरिक्त होना चाहिये । सहायक सेवाओं के कक्ष (चेंजिंग रूम, ड्यूटी रूम, अटैंडेंट रूम) सघन चिकित्सा कक्ष के नजदीक होने चाहिये । इसमें भंडारण (एक 2/4 बैडिड पोड के लिये ; 3-4, 10 बैडिड आईसीयू के लिये) क्रेश कार्ट एल्कोब्स (इलैक्ट्रिक आउटलेट वाले) मेडिकेशन स्टेशन, रेफ्रिजरेटर, लोकेवल केबिनेट (नेरकोटिक्स) काउंटरटाप वर्क एरिया, स्टोरेज केबिनेट/द्राज, एक्सरे व्यू बॉक्स के लिये सुगमता से पहुँचा जा सकने वाला स्थान होना चाहिये ।

3.3 मुख्य सघन चिकित्सा कक्षों के क्षेत्र के अलावा आनुषंगिक क्षेत्रों में संप्रेषण (टेलिफोनों के लिये, इंटरकम्युनिकेशन सिस्टम तथा एमरजेंसी कोड अलार्म सिस्टम), लिपिकीय स्थान (फाइलिंग केबिनेट तथा द्राज) तथा युनिट के साथ सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना क्षेत्र आदि होंगे ।

3.4 नवजात शिशुओं या नवप्रसूति सुश्रुत युनिट की सुविधा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम में 4.65 वर्ग मीटर (50 वर्ग फीट) का क्षेत्र प्रत्येक नवप्रसूति बिस्तर के लिये होना चाहिये जिसमें हाथ धोने तथा गाउनिंग, फार्मूला तैयार करने, भंडार तथा डाक्टरों के लिये ड्यूटी रूम के लिये अलग क्षेत्र होना चाहिये । फर्श क्षेत्र तथा 1.22 मीटर (4 फुट) तक दीवार धोई जा सकें ।

4. आपरेशन थियेटर तथा लेबर रूम :- आपरेशन थियेटर का फर्श क्षेत्र 13.94 वर्ग मीटर (150 वर्ग फुट) तथा लेबर रूम 9.29 वर्ग मीटर (100 वर्ग फुट) प्रति टेबल से कम नहीं होना चाहिये । लेबर रूम में नवप्रसूति रिससूसीटेशन युनिट की सुविधा तथा उपकरण होने चाहियें ।

5. ड्यूटी रूम की व्यवस्था :- ड्यूटी पर नर्सिंग स्टाफ के लिये ड्यूटी रूम होगा ।

6. भंडारण स्थान :- दवाईयों, खाने का सामान, उपकरणों आदि के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जायेगा ।

7. जलापूर्ति :- नर्सिंग होम में प्रयोग किया जाने वाला पानी स्वच्छ तथा पीने योग्य गुणवत्ता का होना चाहिये ।

8. स्वास्थ्य, कपड़े तथा स्टाफ की सफाई संबंधी आवश्यकताएँ :-

8.1 नियुक्त किया गया स्टाफ संक्रामक रोगों से मुक्त होना चाहिये तथा उन्हें अपनी ड्यूटी की प्रकृति के अनुरूप स्वच्छ वर्दी प्रदान की जायेगी ।

8.2 कर्मचारियों को रोजगार दिये जाते समय चिकित्सा जाँच होगी तथा उसके पश्चात समय-समय पर जाँच की जाती रहेगी । कर्मचारियों को सभी संक्रामक बीमारियों से बचाने या संभावित खतरे वाली संक्रामक बीमारियों के लिये टीके लगाये जायेंगे ।

9. उपकरण तथा लिनन आदि :- नर्सिंग होम में -

- 9.1 पर्याप्त संख्या में कोमोड, बैडपैन तथा फलसिंग व्यवस्था वाले स्लोप सिंक होंगे तथा अनुरक्षित किये जायेंगे ।
- 9.2 हाईप्रेसर स्टेरलाइजर और औजार स्टेरलाइजर होंगे ।
- 9.3 रोगियों को सुरक्षित तथा स्वच्छ आक्सीजन देने के लिये सभी प्रकार के आवश्यक उपकरणों तथा फ्लोमीटरों से लैस प्राप्त संख्या में आक्सीजन सिलेंडरों से अबाध आक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था होगी ।
- 9.4 ट्रांसप्यूजन के उपकरण, आवश्यक उपकरण, औजार, यंत्र तथा दवाईयाँ उस स्तर तथा संख्या में होने चाहिये जो नर्सिंग होम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अनुरूप हों ।
- 9.5 प्रसूति कक्ष तथा नवप्रसूति देखभाल कक्ष की नवप्रसूति रिसर्सीटेशन युनिट में उपकरण तथा दवाईयाँ पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा समय-समय पर तैयार किए गये मार्ग दर्शक नियमों के अनुसार होने चाहिये ।
- 9.6 सघन देखभाल के लिये सुविधायें प्रदान करने के विषय में इसके लिये पर्यवेक्षण, निदानात्मक, रेडियोलॉजिकल, थेरेप्यूटिक/सहायक तथा बिस्तरों के समीप सुविधायें तथा समय-समय पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा तैयार किये गये मार्ग दर्शक नियमों के अनुसार होने चाहिये ।
- 9.7 पर्याप्त मात्रा में चादरें, गद्दे तकिए, कंबल, बिछाने वाली चादरें तथा अन्य लिनन होने चाहिये ।
- 9.8 विशेष औषधियों के लिये ताला लगी हुई अलग अलमारी होनी चाहिये ।
10. भोजन यदि नर्सिंग होम रोगियों को खुराक प्रदान करता है तो इसे स्वास्थ्यपरक स्थितियों में पकाया और परोसा जाये ।

11. नर्सिंग स्टाफ :-

- 11.1 ड्यूटी पर पूरे समय, दिल्ली नर्सिंग परिषद् के पंजीकृत कम से कम सामान्य नर्सिंग तथा मिडवाइफरी परीक्षा उत्तीर्ण, नर्स होनी चाहिये जो नर्सिंग होम के प्रत्येक दस बिस्तरों या उसके किसी भाग के लिये एक होनी चाहिये ।

बशर्ते कि पर्यवेक्षण अधिकारी पूर्वानुमोदन से नर्सिंग स्टाफ के एक भाग के स्थान पर अन्य प्रशिक्षित स्टाफ जैसे मिडवाइफ, फार्मासिस्ट, ड्रेसर आदि नर्सिंग होम की विशेष जरूरतों के अनुसार हो सकते हैं ।

- 11.2 सघन देखभाल की सुविधा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम में किसी 10 बिस्तरों वाले आईसीयू/सीसीयू में एक वर्ष के कार्य का अनुभव रखने वाली प्रशिक्षित स्टाफ नर्स होनी चाहिये । किसी विशेष समय पर 40 प्रतिशत से अधिक अनुभवहीन स्टाफ नर्स नहीं होने

चाहिये जिन्हें किसी सघन देखभाल युनिट में एक वर्ष कार्य का अनुभव न हो इस तरह एक शिफ्ट में न्यूनतम 60 प्रतिशत अनुभवी स्टाफ नर्स अवश्य ही उपलब्ध रहेंगी। स्टाफ नर्स 1:1 के अनुपात में चौबीस घंटे उपलब्ध रहेंगी तथा प्रत्येक 10 नर्सों के साथ सघन देखभाल युनिट में चौबीस घंटे एक योग्य पर्यवेक्षक रहेगा। सघन देखभाल युनिट में तैनात अर्धचिकित्सीय स्टाफ को ऐसी युनिट में कार्य का पिछला अनुभव होना चाहिये।

11.3 नवजात की देखभाल या नवप्रसूति देखभाल युनिट सेवा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम में भी 1:1 नर्स रोगी का अनुपात रहेगा।

12 रिकार्ड :- निम्नलिखित के लिये नर्सिंग होम द्वारा अलग स्टॉक रजिस्टर रखे जायेंगे;
(अ) उपकरण
(ब) ओजार और
(स) लिनन

13 डाक्टर :-

13.1 नर्सिंग होम में दिल्ली चिकित्सा परिषद् द्वारा पंजीकृत आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति का एक योग्य डाक्टर चौबीस घंटे प्रत्येक 20 बिस्तर या उसके किसी भाग की संख्या के लिये उपलब्ध रहेगा तथा संबंधित विशेषज्ञता की सेवा बुलाने पर उपलब्ध होनी चाहिये।

13.2 सघन देखभाल सेवा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम में संबंधित विशेषज्ञता आईसीयू में स्नातकोत्तर डाक्टर (एमडी) होनी चाहिये। सुपर स्पेशलिटी की सुविधा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम के मामले में संबंधित विशेषज्ञता का परामर्श बुलाने पर उपलब्ध रहेगा। संबंधित परामर्शदाता अपेक्षित स्नातकोत्तर योग्यता वाला होगा।

बशर्ते कि किसी स्नातकोत्तर डाक्टर के उपलब्ध न होने की स्थिति में, स्नातक उपाधि के पश्चात् किसी परामर्शदाता के पर्यवेक्षक में 10 बिस्तर वाले सामान्य आईसीयू/सीसीयू में एक वर्ष के कार्य अनुभव वाले डाक्टर पर भी आईसीयू/सीसीयू में रेजिडेंट डाक्टर के रूप में कार्य पर भी विचार किया जा सकता है। डाक्टरों बिस्तर का अनुपात चौबीस घंटे 1:4 का रहेगा तथा परामर्शदाता बुलाने पर आयेंगे।

14 प्राकृतिक आपदा या विनाश के समय सहयोग :-

14.1 किसी प्राकृतिक आपदा या विनाश की स्थिति में प्रत्येक नर्सिंग होम के स्वामी या संचालक को पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध किये जाने पर सहयोग देना होगा तथा प्राकृतिक आपदा या विनाश के समय पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली उपयुक्त सहायता तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध करानी होगी।

14.2 नर्सिंग होम किसी भी कारण से इलाज के लिये लाए गए घायल/गंभीर व्यक्ति को इंकार नहीं करेगा।

15 प्रभारों का प्रदर्शन :- नर्सिंग होम का संचालक सुनिश्चित करेगा कि नर्सिंग होम द्वारा नर्सिंग होम में उपलब्ध सभी सेवाओं के लिये जाने वाले प्रभार स्थायी रूप से प्रदर्शित किये जाते रहें।

16 अतिरिक्त जेनरेटर की व्यवस्था :- नर्सिंग होम का रखवाल नर्सिंग होम में बिजली जाने की स्थिति में अतिरिक्त जेनरेटर की व्यवस्था करेगा ।

17 जैव चिकित्सा कूड़े को संभालना :- नर्सिंग होम समय-समय पर यथासंशोधित जैव चिकित्सा कूड़ा (प्रबंधन एवं संभालना) नियमावली, 1998 का पालन करेगा तथा इन नियमों के अन्तर्गत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से अधिकार पत्र प्राप्त करेगा ।

18 नर्सिंग होम की सेवा में व्यवधान :- जहाँ किसी नर्सिंग होम में किसी भी कारण से सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है तो रखवाल इसके विषय में कम से कम चार सप्ताह पूर्व पर्यवेक्षक अधिकारी को इसकी सूचना देगा ।

बशर्ते कि किसी आपातकालिक स्थिति में सेवाओं में व्यवधान की स्थिति में सूचना पर्यवेक्षक अधिकारी को इस प्रकार के व्यवधान के चौबीस घंटे के भीतर देनी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

विवेक रे

(विवेक रे)

प्रधान सचिव (स्वा. एवं परि. कल्याण)

नर्सिंग होम में इनटैनसिव केयर यूनिट (सघन चिकित्सा कक्ष) में अनिवार्य उपकरणों / औषधियों की आवश्यकताओं के लिये दिशा निर्देश

गंभीर देखभाल यूनिट या गहन चिकित्सा यूनिट ऐसे रोगियों के यूनिट हैं जो अत्यधिक बीमार, अस्थिर स्थिति वाले या अत्यधिक अस्थिर स्थिति वाले रोगियों के लिये हैं जिनके लिये निरन्तर उपकरण संचालन तथा पूर्णकालिक नर्सों और विशेष प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता है। गंभीर देखभाल यूनिटों में विस्तृत रूप से हृदय रोग संबंधी यूनिट तथा गहन चिकित्सा यूनिट सम्मिलित होंगे। अत्यधिक सामान्य गहन चिकित्सा यूनिटों में मेडिकल केयर यूनिट (एम आई सी यू), सर्जिकल इनटैनसिव केयर यूनिट (एस आई सी यू) बाल चिकित्सा यूनिट देखभाल यूनिट (पीआईसीयू) न्यूरोलोजिकल गहन चिकित्सा यूनिट (न्यूरो आईसीयू), न्यूओनेटल गहन देखभाल यूनिट (एन आई सी यू) तथा बर्न यूनिट सम्मिलित है।

गहन चिकित्सा यूनिटों में निम्नलिखित सुविधायें होनी चाहिये :-

सामान्य आई० सी० यू०

(क) स्थान अपेक्षाएं

(1) मुख्य

आई० सी० यू० बैड के लिए 200 वर्ग फीट/बैड का स्थान होना चाहिए। औषधियों तथा उपकरण (वेंटिलेटर, विशेष बैड, सक्शन मशीन, वहन उपकरण, व्हीलचेयर कार्ट, मोनिटरिंग आदि) के भंडारण हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए। यह विस्तृत, बड़े-बड़े सैल्फ, खुला दरवाजा जिसमें टच लैस डोर ओपनर हो तथा बैटरी चार्जिंग के लिए स्थान होना चाहिए। डाक्टरों, नर्सों तथा ड्यूटी पर स्टाफ के लिए स्थान आई०सी०यू बैड स्थान से अतिरिक्त होना चाहिए।

सहायक सेवा कक्ष अर्थात् चेंजिंग रूम, ड्यूटी रूम, अटेंडेड रूम आईसीयू के नजदीक होना चाहिए। बिजली जाने पर वैकल्पिक बिजली आपूर्ति उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

बैड साइड (तत्काल उपलब्ध सामान) (2-4 बिस्तर वाले पोड के लिए एक, 10 बिस्तर वाले आईसीयू के लिए 3-4) क्रेश कार्ट एल्कोव्स (इलेक्ट्रिकल आउट लैट सहित)

मेडिकेशन स्टेशन

रेफ्रिजरेटर

ताले वाली केबिनेट (नाकॉटिक्स)

काउंटर टाप वर्क एरिया

भंडारण केबिनेट/दराजे

एक्स-रे- व्यू बाक्स

(ii) आनुषंगिक क्षेत्र

(क) सम्प्रेषण

हाउस टेलिफोन

इंटर कम्यूनिकेशन सिस्टम

इमरजेंसी कोड अलार्म सिस्टम

(ख) लिपिकीय स्थान (वरीयता अलग)

फाइलिंग केबिनेट्स दराजे आदि

(ग) सार्वजनिक स्थान (युनिट के साथ)

टेलिफोन (हाउस तथा सार्वजनिक)

प्रार्थना क्षेत्र

(ख) उपकरण (अनिवार्य)

(i) रिकार्डिंग डेटा स्टोरिंग तथा विश्लेषण सुविधाओं सहित उपकरण संचालन

ई सी जी मशीन/संचालन

एस पी ओ 2

डैफीब्रिलेटर सुविधा

तापमान-मल्टीपैरामीटर

ईटीसीओ

एन आई वी पी 2

इन्फ्यूजन पम्प सिरिज

डिफिकल्ट इनट्यूबेशन/एक्सट्यूबेशन कार्ट

नेबुलाइज़र (अल्ट्रासोनिक)

वैकल्पिक

कार्डिअक, ऑउटपुट

(ii) डाइग्नोस्टिक

ए बी जी मशीन, इलैक्ट्रोलायर मशीन की सुविधा हेमाटोक्रिट, के एफ टी, ग्लूकोस मापन सुविधाएं आई सी यू/अस्पताल में चौबीस घंटों उपलब्ध होनी चाहिये।

(iii) रेडियोलॉजिकल

इमेजिंग एक्स-रे, वेडसाइट अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधाएं समस्त मूलभूत इमेजिंग सुविधाएं तथा समस्त इन्वैस्टिगेटिव रेडियोलॉजिकल पद्धति उपलब्ध रहनी चाहिये। सी टी स्कैन तथा वेडसाइट इकोकार्डियोग्राफी सुविधा के लिये प्रबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

(iv) थैराप्यूटिक/सपोर्टिव

वैनटिलेटर्स

4

(v) बैडसाइड सुविधाएं

आक्सीजन आपूर्ति के लिये केन्द्रीय पाइपलाईन प्रणाली, वैक्यूम एक्शन, ब्लडप्रेसर संचालन प्रणाली, निट्रैस आक्साइड, वैनटिलेशन के लिये हवा, विद्युतीय तारों के आड़े - तिरछे बिखरे रूप से बचने के लिये पर्याप्त इलैक्ट्रिकल सौकेट्स, एयर मैटरस, व्हीलचेयर, शिफ्टिंग ट्रॉली, ओवरहैड ट्रॉली सहित एडजस्टेबल बिस्तर, डीटैचेबल बिस्तर -

विशेष आई.सी.यू.

समस्त अन्य आई.सी.यू.जैसे :- न्यूरोलॉजिकल आई.सी.यू., न्यूरोलॉजिकल आई.सी.यू., न्यूओनेटल आई.सी.यू., मेडिकल आई.सी.यू., सर्जिकल आई.सी.यू. में सामान्य आई.सी.यू. के अतिरिक्त उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण होने चाहिये।

न्यूरोलॉजी/न्यूरोसर्जरी आई.सी.यू. में सी.टी.स्कैन सुविधा होनी चाहिये।

कोरोनरी केयर यूनिट (सी सी यू) में कार्डिअक मॉनीटर तथा अस्थाई पेसिंग तथा पलूओरोसकोपी तथा इनवेसिव आरटिकुल/वीनिकुल दाब संचालन तथा इन्ट्राओरटिक बैलून काउंटर पलसेशन सुविधा के लिये सुविधा होनी चाहिये।

कोरोनरी एंजोग्राफी की सुविधा वैकल्पिक है।

ग अनिवार्य औषधियाँ तथा उपयोग हेतु आवश्यक वस्तु :-

1. औषधियाँ :- आई.सी.यू. में चौबीस घंटे अपेक्षित औषधियाँ/पलूड उपलब्ध रहने चाहिये तथा आई.सी.यू. में किसी भी समय किसी भी दवाई की कमी नहीं होनी चाहिये। अनिवार्य औषधियों की सूची नीचे दी गई है :-

(i) इन्डैक्शन/सीडेशन एजेंट

थियोपैन्टोन

केटामिन

प्रोपोफोल

मिडाजोलम

डिऊउपैम

मोरफिन

पैथीडाइन

पैन्टाजोसिने

प्रोमीथाजिन

चोरप्रोमेजिन

4

(ii) रिलैक्सेंट्स

सुएक्समैथोनिकम

बैक्यूरोनिकम

पैनक्यूरोनिकम

रोक्यूरोनियम

एटराक्यूरिकम

(iii) इनोट्रोप्स

एडरिनेलिन

नोराड्रेनालिन

डोपामाइन

डोबूटामाइन

(iv) एन्टीबायोटिक्स

(v) ब्रोनकोडिलेन्ट्स

डैरिफिलिन

एमीनोफिलिन

टरब्यूटेलिन

नेबुलिसेशन सोलूशन (आस्थालाइन, आईपरावैट, बडीकोर्ट, म्यूकोलाइटिक)

(vi) इनफ्यूजन

एस्मोलोल

नाईटोग्लिसरीन

सोडियम निट्रोप्राइड

इन्सुलिन

h

टी पी एन सोल्यूशन

मैनीटोल

(vii) अन्य औषधियाँ

मेरोपरोलोल

फूसमाइड

रैनिटाइडिन

मैटोक्लोपेरामाइड

ओनाडामसीट्रोन

स्थानीय एनैसथेटिक्स (लिडोकेन, बुपीवेकेन)

एन्टीर्यूमैटिक (एडनोसाइन, एक्लीलोकार्ड, कारडरोन, ब्रीटैलिअयम)

विटामिन के

लोमोलीक्यूलर वेटहीपेरिन

डिलीटिआजम

डिक्लोफिनैक

ट्रेमाडोल

एटरोपाइन

पी ए एम

इन्जेक्शन एविल

इन्जेक्शन डिकाट्रोन

इन्जेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन

इन्जेक्शन एटीमैटिल

इन्जेक्शन इमैसैट

h

इन्जैक्शन डिसऑक्सीजन
ग्लाइकोफोरोलेट

न्यूओस्टिगमाइन

कैल्शियम ग्लुकोनेट

सोडाबाईकार्ब

इन्जैक्शन पोटेशियम क्लोराइड

तथा सिरप पोटेशियम क्लोराइड

मैगनेशियम

मल्टीविटामिन्स

लोकल एनसकैटिक जैली

आई आइनटमैट

एन्टीसैटिक सोल्यूशन तथा आइनटमैट

क्लीनिंग / डिसइन्फेक्टिंग सोल्यूशन

एन्टीस्नेक वीनोम

कोलोइड्स (पोलीजैलिन, स्टार्च, डीस्ट्रॉस एलबूमिन)

मैक्सिलेटिन

II कन्ज्यूमेबल

इन्डोट्रैकल ट्यूब (समस्त आकारों में)

ट्रैचोसटोमी ट्यूब (समस्त आकारों में)

एल एन ए (आई एल एम ए सहित) (समस्त आकारों में)

फेस मास्क (समस्त आकार)

ओरोपैरीनजील एयरवेज (समस्त आकार)

h

नेसोफेरिजियल एयरवेज समस्त आकार

नौन टच सक्शन उपकरण

सक्शन कैथेटर्स (समस्त आकार)

गर्मी और ननी एक्सचेंजर (इटीटी, ट्रोचैक्टोमी ट्यूब के साथ प्रयोगार्थ)

इनसेनटिव स्पाईरोमीटर्स

आई/वी कैन्यूले

श्री वेज़

सी पी पी लाइन (समस्त आकार)

इनट्रा आरटीरियल कैन्यूलेक

फोलीस कैथेटर्स

नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब

सी पी ए पी मास्क

वैन्ट्यूटी मास्क

बिनेसल कैन्यूलेक

नैसल संपैक्टेकल

परक्यूटेनियस डिक्लेशन ट्रैकैओस्टोमी केट

स्टराइल ड्रेसिंग

डिस्पोजेबल ग्लोब, मास्क, सीरिज तथा नीडल, शू कवर

अस्थायी पैसिंग लीड्स 6 एफ/7एफ अस्थायी पल्स जनरेटर

चेक फ्लो (5-7एफ) तथा स्वान गंज कैथेटर

आरटीरियल पंपयर नीडल

स्टराइल ड्रेप शीट्स

(घ) अपेक्षित कर्मचारी

h

(1)

5/12/22

संबंधित विशेषज्ञता आईसीयू में स्नातकोत्तर डाक्टर (एमडी) तथा सुपर स्पेशलिटी के मामले में संबंधित विशेषज्ञता का परामर्शदाता उपलब्ध होना चाहिए संबंधित परामर्शदाता को अपेक्षित स्नातकोत्तर योग्यता संपन्न होना चाहिए। स्नातकोत्तर डाक्टर के उपलब्ध न होने पर किसी 10 बिस्तर वाले सामान्य आईसीयू/सीसीयू में किसी परामर्शदाता के पर्यवेक्षण में एक वर्ष तक कार्य का अनुभव रखने वाले किसी स्नातक डाक्टर को रेजिडेंट डाक्टर रखा जा सकता है डाक्टर का दिल्ली चिकित्सा परिषद में पंजीकरण हो तथा डाक्टरों का अनुपात 24 घंटे बिस्तरों का 1:4 का होना चाहिए तथा विशेषज्ञ बुलाए जाने पर उपलब्ध हो।

(ii) नर्सिंग कर्मचारी

ऐसी स्टाफ नर्स हों जिनकी न्यूनतम योग्यता सामान्य नर्सिंग तथा मिडवाइफरी कोर्स होना चाहिए। दिल्ली नर्सिंग परिषद के पास पंजीकृत तथा 10 बिस्तर वाले आईसीयू/सीसीयू में एक वर्ष कार्य का अनुभव हो। किसी एक समय 40 प्रतिशत से अधिक ऐसी अनुभवहीन स्टाफ नर्स नहीं होनी चाहिए जिन्हें एक वर्ष आईसीयू में कार्य का अनुभव न हो। अतः सुनिश्चित होना चाहिए कि एक पारी में न्यूनतम 60 प्रतिशत अनुभवशील स्टाफ नर्स उपलब्ध होनी चाहिए। स्टाफ नर्स 24 घंटे 1:1 के अनुपात में होगी तथा प्रत्येक 10 नर्सों पर शिक्षित पर्यवेक्षक चौबीस घंटे आईसीयू में उपलब्ध होना चाहिए।

(iii) अर्ध-चिकित्सा स्टाफ

आईसीयू में तैनात अर्ध-चिकित्सा स्टाफ को आईसीयू में कार्य का पिछला अनुभव होना चाहिए।

(ड) सामान्य सेवाएं

अग्नि सुरक्षा उपाय

वातानुकूलन/हीटिंग

h

भूमिगत विद्युत प्वाइंट

आपातकालीन पॉवर स्रोत

सर्किट ब्रेकर उपकरण

उचित प्रकाश व्यवस्था

मरीजों को अन्य अस्पताल ले जाने या बड़े-बड़े केन्द्रों में लाने-ले जाने की सुविधा आई।

सी.यू./सी.सी.यू. सहित होनी चाहिये।

ये सिफारिशें आई.सी.यू./सी.सी.यू. के लिये दिशा निदेश बनाई गई हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं तथा इनमें समय-समय पर संशोधन की आवश्यकता हो सकता है।

h

नर्सिंग होम में नवजात शिशु (न्यूबोर्न) देखभाल यूनिट नवप्रसूति (नियोनेटल) देखभाल यूनिट तथा नियोनेटल पुनर्जीवन यूनिट में अनिवार्य उपकरणों और औषधियों की मूलभूत आवश्यकता

नवजात शिशु (न्यूबोर्न) देखभाल यूनिट

- वे नर्सिंग होम जो नवजात शिशु देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं उनमें निम्नलिखित अनिवार्य उपकरण और सुविधायें होनी चाहिये :-

- प्रत्येक नवप्रसूति बिस्तर के लिये नियोनेटल चैस्टपीस सहित एक स्टैथोस्कोप
- बच्चे का वजन मापक मशीन
- आक्सीजन हूड बॉक्स तथा अन्य आक्सीजन वितरण उपकरण जैसे हम्यूडिकायर तथा रेगुलेटर
- फोटोथैरेपी यूनिट
- आक्सीजन तथा कम्प्रेस्ड एयर की निरन्तर उपलब्धता
- आक्सीजन एनॉलाइजर (आक्सीमीटर)
- नॉनइन्वेसिव ब्लड प्रेशर मानीटर
- हार्ट रेट तथा/या अपनीया मानीटर
- नवजात शिशु बचाव किट
- ट्रांसपोट इन्क्यूबेटर
- सक्शन मशीन
- एयर थर्मामीटर
- रेडीएन्ट हीट सोर्स

ऐसी नर्सिंग होम में चौबीसों घंटे बायोकेमिकल तथा हीमेटोलोजिकल जाँच के लिये अपेक्षित सुविधायें होगी जो बीमार शिशु के उपचार प्रबंधन के लिये आवश्यक हो सकती हैं। संक्रमण नियंत्रण की सुविधा होनी चाहिये जैसे अबाधित जलापूर्ति तथा संक्रमित शिशुओं को अलग रखने की व्यवस्था। गन्धे और मैले लीलन या अन्य सीमित अवशिष्ट के निपटान की सुरक्षित और पर्याप्त पद्धति।

लेबर रूम में नवप्रसूति पुनर्जीवत (नियोनोल)

- एक चालू दीवार घड़ी जिसमें सैकेंड की सुई हो या स्टाप क्लॉक।
- रेडीएन्ट हीट साधन
- दाब नियंत्रण यूपण मशीन तथा न्यूक्स एक्सट्रैक्टर की पर्याप्त संख्या।
- नवप्रसूति आधार के ब्लेज सहित दो कार्यरत स्वर यंत्रदर्शी
- सैल्फ इन्फ्लैटिंग बैग सहित आई पी पी आर के लिये अपेक्षित सुविधाएं, भलीभांति फिट किये गये नियोनेटल फेस मास्क, एन्डोट्रेक्ल ट्यूब तथा समुचित एडॉटरस्
- अनबिलिकल वेन केन्यूलेशनस् सेट
- शिशु भार मापक मशीन
- प्रसव के दौरान आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता।

नर्सिंग होम में रोगियों के अभिलेखों के रखरखाव के लिये दिशा-निर्देश

नर्सिंग होम को निम्नलिखित प्रपत्रों के दिए गए प्रारूप के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव करना होगा ।

फार्म प्रपत्र "डी" भर्ती रोगियों का रजिस्टर ।

फार्म प्रपत्र "ई" नर्सिंग होम में भर्ती प्रत्येक प्रसूति मामलों का अभिलेख ।

फार्म प्रपत्र "एफ 1-2" गर्भपातों का अभिलेख एम0 टी0 पी0 मामले, तथा

नर्सिंग होम में होने वाले मृत प्रसव का अभिलेख फार्म "जी" नर्सिंग होम में हुई मृत्यु का रिकार्ड ।

4

फार्म घ (संशोधित)
(नियम 12 देखें)

नर्सिंग होम/अस्पताल के रोगियों का रजिस्टर

भर्ती संख्या	नाम पुत्र/पुत्री/पत्नी तथा पता	आयु/लिंग	भर्ती की तिथि तथा समय	भर्ती का रोग निदान	अंतिम रोग निदान	केस की प्रभावी डाक्टर	छुट्टी/मृत्यु/लम्बा की तिथि तथा समय	एमएलसी या नहीं (हाँ/नहीं)	परिणाम या तथा टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4

(10)

फार्म 'ड'

[illegible]

पृष्ठ-1

फार्म-इ

मैं _____ (आर० एम० पी० का नाम एवं योग्यता स्पष्ट अक्षरों में)
_____ (आर० एम० पी० का पूरा नाम)
मैं _____ (आर० एम० पी० का नाम एवं योग्यता स्पष्ट अक्षरों में)
_____ (आर० एम० पी० का पूरा नाम)

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है* मेरा/हमारा सद्भाव पूर्वक विचार है कि _____
(गर्भवती महिला का पूरा नाम एवं पता स्पष्ट अक्षरों में) का गर्भपात कराना आवश्यक है।

जिसका निम्नलिखित कारण है **

* मैं/हम एतद् द्वारा सूचित करते हैं कि मैं* हम उपरोक्त महिला जिसका अस्पताल/अनुमोदित
स्थान के दाखिले रजिस्टर में _____ क्रम संख्या है गर्भपात करता हूँ/करते हैं।

आर०एम०पी० के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

* जो लागू न हो उसे काट दिया जाए

* मद संख्या (1) से (5) तक विनिर्दिष्ट कारण में से जो सही हो उसे लिखे :-

- (i) गर्भवती महिला का जीवन बचाने के उद्देश्य से।
- (ii) गर्भवती महिला के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाने से बचाने के उद्देश्य से।
- (iii) महत्वपूर्ण जोखिम को ध्यान में रखते हुए जैसे यदि बच्चा पैदा होता तो वह ऐसी शारीरिक अथवा मानसिकता असामान्यता के रूप में होता है जो कि गंभीर रूप से विकलांग हो सकता था।
- (iv) गर्भवती महिला का गर्भधारण बलात्कार के कारण हुआ है।
- (v) गर्भावस्था बच्चों की संख्या को सीमित रखने के उद्देश्य से विवाहित महिला अथवा उसके पति द्वारा प्रयोग किए गर्भनिरोधक उपायों अथवा साधनों की असफलता के परिणामस्वरूप हुआ हो।

नोट : गर्भवती महिला के वास्तविक स्थिति तथा ऐसे वातावरण को निर्धारित करने का ध्यान रखा जाए कि गर्भपात करने के लिए उसके शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाने से बचाया जा सकेगा।

आर०एम०पी० के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

h

फॉर्म-II
(विनियम 4 (5) देखें)

माह _____ की _____ जिला, दिल्ली की गर्भपात अधिनियम सूचना

1. (i) अनुमोदित संस्थानों की संख्या _____
(ii) सूचना देने वाले संस्थानों की संख्या _____
महीने का नाम _____

2. कुल एमटीपीओ मामले _____

3. कुल मामलों का विभाजन

4.

- (i) गर्भधारण की अवधि (केवल कुल संख्या दें)

a	12 सप्ताह तक	
b	12-20 सप्ताह तक	

- (ii) आयु समूह

a	15 से कम	
b	15-19	
c	20-24	
d	25-29	
e	30-34	
f	35-39	
g	40-44	
h	45 से अधिक	
i	उपलब्ध नहीं	

- (iii) महिला का धर्म

a	हिन्दु	
b	मुस्लिम	
c	ईसाई	
d	अन्य	
e	कुल	

h

23

पृष्ठ - 1

फार्म-III
(विनियम 5 देखें)
प्रवेश रजिस्टर

[illegible]

फॉर्म - 2

फार्म क
(नियम 4 (1) तथा 8 (1) देखें)
(समर्थित दस्तावेजों सहित अनुलिपि में जमा कराए)

जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र के पंजीकरण अथवा पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम उस संगठन का नाम जिसका पंजीकरण किया जाना है	
2. आवेदक का पता	
3. पंजीकृत किए जाने वाली सुविधा की किस्म (कृपया उल्लेख करें कि जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र अथवा इनमें से किसी के सम्मिलन के पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाना है)	
4. जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का दूरभाष संख्या/फैक्स संख्या/टेलीग्राफिक/टैलेक्स/ई-मेल पते सहित उनका पूरा नाम एवं पता	
5. संगठन के स्वामित्व का प्रकार (व्यक्तिगत स्वामित्व/साझेदारी/कंपनी/सहकारी/अन्य कोई, विनिर्दिष्ट किया जाए, यदि संगठन की किस्म व्यक्तिगत स्वामित्व के अतिरिक्त है तो उस स्थिति में संस्था मदों की प्रति तथा संलग्न व्यक्तियों जो कि प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं, ऐसे व्यक्तियों का नाम एवं पता प्रस्तुत करें।)	
6. संस्था की किस्म (सरकारी अस्पताल/नगर अस्पताल/सार्वजनिक अस्पताल/निजी अस्पताल/निजी नर्सिंग होम/प्राइवेट क्लिनिक/प्राइवेट प्रयोगशाला/अन्य कोई)	
7. विशेष पूर्व प्रसव निदान पद्धति/जांच जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाना है (क) इनवेसिडव (i) एमनीओ सेटेसिस/जरायु अंकुर एसपाइरेशन/कैरोमोशोमल/जीव रसायन/मोलीक्यूलर अध्ययन (ख) नॉन इनवेसिडव : अल्ट्रासोनोग्राफी इसे खाली छोड़ दें यदि पंजीकरण केवल जैनेटिक परामर्श केन्द्र के लिए ही चाहिए।	
8. प्रत्येक उपकरण के मेक एवं मॉडल सहित उपलब्ध उपकरण (अलग पेपर पर सूची)	
9. (क) परामर्श केन्द्र में उपलब्ध सुविधाएं (ख) क्या निम्नलिखित जाँचों के लिए प्रयोगशाला/क्लिनिक में सुविधाएं उपलब्ध हैं या होंगी :- (i) अल्ट्रासाउंड (ii) एमनीओ सेरेसिस (iii) जरायु अंकुर एसपाइरेशन	

(iv) फोटोस्कोपी (v) फोटल बायोस्पी (vi) कार्डोसेटेंसिस क्या निम्नलिखित के लिए प्रयोगशाला/क्लिनिक में सुविधाएं उपलब्ध हैं :- (i) गुण सूत्रीय अध्ययन (ii) जीव रसायन अध्ययन (iii) आणविक अध्ययन (iv) प्रीम प्लांटेशन जैनेटिक निदान	
10. कर्मचारियों के नाम योग्यताएं अनुभव तथा पंजीकरण संख्या (अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत करें)	
11. यह उल्लेख करें कि जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र/इमेजिंग केन्द्र नियम 3 में निर्धारित अपेक्षाओं को पंजीकरण के लिए पूरा करते हैं।	
12. केवल नवीकरण आवेदनों के लिए (क) पंजीकरण संख्या (ख) वर्तमान पंजीकरण प्रमाण पत्र के जारी होने एवं समाप्ति की तारीख	
13. संलग्नकों की सूची (कृपया संलग्नकों/समर्थित दस्तावेजों की सूची इसके साथ संलग्न करें।)	

h

घोषणा

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ० _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____

आयु _____ वर्ष पता _____
(पंजीकृत किए जाने वाले संस्थान का नाम बताएं) इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियम एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) तथा प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियम एवं दुरुपयोग निवारण) नियमावली, 1996 को पढ़ा है और समझ लिया है।

मैं शपथ लेता हूँ कि उक्त अधिनियम तथा नियमावली के विषय में जैनेटिक काउंसलिंग केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र के सभी कर्मचारियों को बता दूंगा जिनके अंतर्गत पंजीकरण करवाया गया है तथा सुनिश्चित करता हूँ कि अधिनियम तथा नियमावली का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

तिथि :

स्थान:

व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा हस्ताक्षर जिसे
संस्थान की तरफ से पंजीकृत किया गया है जिसका
पंजीकरण किया जाना है

पावती

(नियम 4 (2) तथा 8(1) देखें)

जैनेटिक काउंसलिंग केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का पंजीकरण प्रदान करने/नवीकरण के लिये दो प्रतियों में फार्म 'क' में आवेदन पत्र _____ (आवेदक का नाम और पता) उपयुक्त अधिकारी ने प्राप्त कर लिया है तिथि _____

*फार्म 'क' में आवेदन के साथ अनुलग्नकों की सूची को प्रस्तुत किए गए अनुलग्नकों से जाँच करके सही पाया गया है।

या

*जाँच करने पर पाया गया कि सूची में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न नहीं है।
इस पावती से आवेदक को पंजीकरण प्रदान करने/नवीकरण का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं होता।
(_____)

समुचित अधिकारी के कार्यालय में समुचित
अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा पदनाम

तिथि :

स्थान:

मुहर

h

प्रदर्शन हेतु मूल/डुप्लीकेट
फार्म ख
(नियम 6 (2), 6 (5) तथा 8 (2) देखें)
पंजीकरण प्रमाण पत्र
(दो प्रतियों में जारी किया जाए)

1. पूर्व प्रसव निदान तकनीक (विनियम तथा दुरुपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 19 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुचित प्राधिकारी _____ उपरोक्त अधिनियम के अधीन दिनांक _____ को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए जैनेटिक काउंसलिंग/पूर्व प्रसव निदान पद्धति/पूर्व प्रसव निदान जाँच/अल्ट्रासोनोग्राफी करने के उद्देश्य से निम्नलिखित जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग सेंटर का पंजीकरण करता हूँ।
2. यह पंजीकरण उपरोक्त अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के अनुसार किया जाता है तथा इसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर अभियोजन के अतिरिक्त पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित किया जाएगा या रद्द किया जाएगा।

- क. फार्म ग का (1) लें
- ख. पूर्व प्रसव निदान पद्धति (जैनेटिक क्लिनिक) के लिए अनुमोदित नॉन इनवेसिव
- (i) अल्ट्रासाउंड इनवेसिव
 - (ii) एमनीयोसेंटसिस
 - (iii) जरायु अंकुर बायोप्सी
 - (iv) फोइटो स्कॉपी
 - (v) भ्रूण त्वचा या अंग बायोप्सी
 - (vi) कॉरडोसेटेसिस
 - (vii) अन्य कोई (उल्लेख करें)
- ग. जैनेटिक प्रयोगशाला के लिए अनुमोदित प्रसव पूर्व निदान जाँच
- (i) गुणसूत्र अध्ययन
 - (ii) जीव रसायन अध्ययन
 - (iii) आणविक अध्ययन
- घ. अन्य कोई उद्देश्य (कृपया उल्लेख करें)

3. प्रयोग किए गए उपकरणों मॉडल तथा मेक (किसी भी प्रकार के परिवर्तन से नियम 13 के अधीन समुचित प्राधिकारी को सूचित किया जाए)
4. आबंटित पंजीकरण संख्या

फार्म ग

(नियम 6 (3), 6(5) तथा 8(3) देखें)

पंजीकरण करने/नवीकरण के लिये आवेदन पत्र को रद्द करने के लिये फार्म

पूर्व प्रसव निदान तकनीक (विनियम तथा दुरुपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1994 की धारा 19(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समुचित प्राधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित जैनेटिक परामर्श केन्द्र/* जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लीनिक/अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/इमेजिंग केन्द्र के पंजीकरण/नवीकरण के आवेदन को रद्द करता हूँ।

- (1) जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लीनिक/अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/इमेजिंग केन्द्र का नाम एवं पता
- (2) पंजीकरण करने/नवीकरण के लिये आवेदन

दिनांक :

समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम तथा पदनाम कार्यालय मुहर सहित

* जो लागू न हो, काट दिया जाए।

फार्म - घ
(नियम 9 (2) देखें)
जैनेटिक परामर्श केन्द्र द्वारा रिकार्ड के रखरखाव के लिए फार्म

1.	जैनेटिक परामर्श केन्द्र का नाम एवं पता	
2.	पंजीकरण संख्या	
3.	रोगी का नाम	
4.	आयु	
5.	पति/पिता का नाम	
6.	पूरा पता, दूरभाष सहित, यदि कोई हो	
7.	द्वारा भेजा गया (डॉक्टर/जैनेटिक परामर्श केन्द्र का पूरा नाम व पता) (रेफरल नोट को केस पेपरों के साथ सुरक्षित रखा जाए) सैल्फ रेफरल	
8.	अंतिम महावारी तारीख/गर्भावस्था के सप्ताह	
9.	परिवार में जैनेटिक/मेडिकल रोगों का पूर्ववृत्त (उल्लेख करें) निदान का आधार (क) क्लिनिकल (ख) जीव रसायन (ग) साइटोजैनेटिक (घ) अन्य (रेडियोलॉजिकल, अल्ट्रासोनोग्राफी इत्यादि का उल्लेख करें)	
10.	पूर्व प्रसव निदान के लिए विशेष अनुदेश क. पहले हुए बच्चा/बच्चे (i) गुणसूत्र संबंधी खराबी (ii) चयापचयी खराबी (iii) विकृति (iv) मानसिक खराबी (v) वंशानुगत एनीमिया (vi) लिंग खराबी (vii) सिंगल जैनी खराबी (viii) अन्य कोई (उल्लेख करें) ख. एडवांस मातृत्व आयु (35 वर्ष या अधिक) ग. माता/पिता/सहोदर जिन्हें जैनेटिक रोग हो (उल्लेख करें) घ. अन्य (उल्लेख करें)	
11.	प्रक्रिया सलाह (i) अल्ट्रासाउंड (ii) एमनीओसेंटेसिस (iii) जरायु अंकुर बायोस्पी (iv) फोटोस्कॉपी	

	(v) भ्रूण त्वचा या अंग बायोप्सी (vi) गुणसूत्र (vii) अन्य कोई (उल्लेख करें)	
12.	किए गए प्रयोगशाला जाँच (i) गुणसूत्रीय अध्ययन (ii) जीव रसायन अध्ययन (iii) आणविक (iv) प्रीम प्लांटेशन जैनेटिक निदान	
13.	निदान का परिणाम यदि असामान्य हैं तो विवरण दें सामान्य/असामान्य	
14.	एमटीपी सलाहकार	
15.	उस जैनेटिक क्लिनिक का नाम व पता जहाँ रोगी भेजा गया।	
16.	जैनेटिक परामर्श का प्रारंभ तथा अंत का विवरण	

फार्म डू (ई)
(नियम 9 (3) देखें)

1. जैनेटिक प्रयोगशाला द्वारा अभिलेखों के रखरखाव के लिये फार्म
2. जैनेटिक प्रयोगशाला का नाम एवं पता
3. पंजीकरण संख्या
4. रोगी का नाम
5. आयु
6. पति/पिता का नाम
7. पूरा पता, दूरभाष सहित, यदि कोई हो
8. द्वारा भेजा गया/द्वारा नमूना भेजा गया (जैनेटिक क्लिनिक का पूरा नाम एवं पता)
(रैफरल नोट को केस पेपरों के साथ सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाये)
9. नमूने का प्रकार : मातृ रक्त/ जरायु अंकुर नमूना/एमनीओटिक फ्लूड/भ्रूण का रक्त
या अन्य भ्रूण टिशु (उल्लेख करें)

(क) पहले हुये बच्चा/बच्चे

- (i) गुणसूत्र खराबी
- (ii) चयापचयी खराबी
- (iii) विकृति
- (iv) मानसिक खराबी
- (v) वंशानुगत एनीमिया
- (vi) लिंग खराबी
- (vii) सिंगल जैनी खराबी
- (viii) अन्य कोई (उल्लेख करें)

(ख) एडवांस मातृत्व आयु (35वर्ष या अधिक)

(ग) माता/पिता/सहोदर जिन्हें जननिक रोग हो (उल्लेख करें)

(घ) अन्य (उल्लेख करें)

10. किए गये प्रयोगशाला जाँच (विवरण दें)

- (i) गुणसूत्र अध्ययन
- (ii) जीव रसायन अध्ययन
- (iii) आणविक अध्ययन
- (iv) प्रिडिक्शन प्लॉटिंग जैनेटिक निदान

11. निदान का परिणाम

यदि असामान्य हो तो विवरण दें

सामान्य/असामान्य

12. वह तारीख जिसमें जाँच की गई

पूर्व प्रसव निदान जाँचों का परिणाम.....को दिनांकको भेजा गया ।

नाम, हस्ताक्षर एवं चिकित्सा जैनेटिक पंजीकरण
सं./संस्था के निदेशक

स्थान :

दिनांक :

h

फार्म ड (ई)
(नियम 9 (3) देखें)

1. जैनेटिक प्रयोगशाला द्वारा अभिलेखों के रखरखाव के लिये फार्म
2. जैनेटिक प्रयोगशाला का नाम एवं पता
3. पंजीकरण संख्या
4. रोगी का नाम
5. आयु
6. पति/पिता का नाम
7. पूरा पता, दूरभाष सहित, यदि कोई हो
8. द्वारा भेजा गया/द्वारा नमूना भेजा गया (जैनेटिक क्लिनिक का पूरा नाम एवं पता)
(रिफरल नोट को केस पेपरों के साथ सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाये)
9. नमूने का प्रकार : मातृ रक्त/ जरायु अंकुर नमूना/एमनीओटिक फ्लूड/भ्रूण का रक्त
या अन्य भ्रूण टिशु (उल्लेख करें)
- (क) पहले हुये बच्चा/बच्चे
 - (i) गुणसूत्र खराबी
 - (ii) चयापचयी खराबी
 - (iii) विकृति
 - (iv) मानसिक खराबी
 - (v) वंशानुगत एनीमिया
 - (vi) लिंग खराबी
 - (vii) सिंगल जैनी खराबी
 - (viii) अन्य कोई (उल्लेख करें)
- (ख) एडवांस मातृत्व आयु (35वर्ष या अधिक)
- (ग) माता/पिता/सहोदर जिन्हें जननिक रोग हो (उल्लेख करें)
- (घ) अन्य (उल्लेख करें)
10. किए गये प्रयोगशाला जाँच (विवरण दें)
 - (i) गुणसूत्र अध्ययन
 - (ii) जीव रसायन अध्ययन
 - (iii) आणविक अध्ययन
 - (iv) प्रिइम प्लांटेशन जैनेटिक निदान
11. निदान का परिणाम
यदि असामान्य हो तो विवरण दें सामान्य/असामान्य
12. वह तारीख जिसमें जांच की गई
पूर्व प्रसव निदान जांचों का परिणाम.....को दिनांकको भेजा गया ।

नाम, हस्ताक्षर एवं चिकित्सा जैनेटिक पंजीकरण
सं./संस्था के निदेशक

स्थान :
दिनांक :

h

- (vi) अन्य कोई उल्लेख करें
12. प्रक्रिया की कोई जटिलता (कृपया उल्लेख करें)

प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया
(विवरण दें)

(ख) अल्ट्रासोनोग्राफी (सामान्य/असामान्य)
(पता लगाई गई असामान्यता, यदि कोई है, स्पष्ट करें)

15. वे तिथियाँ जब प्रक्रिया पूरी की गई ।
16. सहमति प्राप्त करने की तिथि (आक्रामक के मामले में)
17. प्रसव-पूर्व निदान प्रक्रिया के परिणाम को (तिथि) को बताए गए ।
18. क्या एमटीपी की सलाह दी गई/की गई ?
19. एमटीपी करने की तारीख ।

दिनांक:

स्थान :

स्त्री रोग विज्ञानी/रेडियोलॉजिस्ट/
क्लीनिक के निदेशक का नाम, हस्ताक्षर
तथा पंजीकरण संख्या

गर्भवती की घोषणा

मैं सुश्री..... (गर्भवती का नाम) घोषणा करती हूँ कि अल्ट्रासोनोग्राफी/
इमेज स्कैनिंग आदि करवाकर मैं भ्रूण का लिंग नहीं जानना चाहती हूँ ।

गर्भवती के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

3. जो लागू या आवश्यक न हो, उसे काट दें

अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेज स्कैनिंग करने वाले डॉक्टर/व्यक्ति की घोषणा
मैं..... (अल्ट्रासोनोग्राफी) करने वाले व्यक्ति का नाम) घोषणा करता हूँ कि
सुश्री..... (गर्भवती) की अल्ट्रासोनोग्राफी करते समय मैंने किसी भी व्यक्ति को न ही
भ्रूण का लिंग बताया है और न ही मैंने पता लगाया है ।

अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले व्यक्ति जेनेटिक क्लीनिक/
अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/इमेजिंग क्लीनिक के निदेशक/
स्वामी का नाम तथा हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण नोट :

- (i) अल्ट्रासाउंड भ्रूण का लिंग पता लगाने के लिये नहीं किया गया/सलाह दी गई है यह डेकेन मस्कुलर डिस्ट्राफी, हिमोफीलिया ए एवं बी आदि लिंग-सापेक्ष रोगों के निदान के लिये किया गया है ।
- (ii) गर्भावस्था में अल्ट्रासोनोग्राफी जब बताई गई हो तभी की जानी चाहिये । गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड के लिये निम्नलिखित संकेतक सूची है ।

1. इंड्रा-यूट्राइन एवं/या एक्टोपिक गर्भाधान एवं स्वस्थ होने की पुष्टि
2. गेस्टेशनल आयु का पूर्वकलन (तिथि)
3. भ्रूणों की संख्या एवं उनकी कोरियोनिस्सिटी का पता लगाना
4. आइ यू सी डी होने पर गर्भावस्था या गर्भनिरोधक असफल/ एम टीपी असफल होने पर संभावित गर्भावस्था
5. योनि रक्त स्राव/स्राव
6. गर्भपात मामलों की अनुवर्ती परीक्षा
7. आन्तरिक ओ एस की सर्वाइकल कनाल तथा व्यास का निर्धारण करने के लिये
8. योनि आकार एवं अन्तर्विच की अवधि के बीच विसंगति
9. कोई संभावित एडिने क्सल या यूट्राइन पैथोलोजी/असामान्यता
10. क्रामोसोम संबंधी असामान्यता का पता लगाना, गर्भ का स्वरूप संबंधी दोष तथा अन्य असामान्यताएँ एवं अनुवर्ती
11. भ्रूण उपस्थिति एवं स्थिति का निर्धारण
12. लिफ्टर एमनी का निर्धारण
13. अवधि पूर्व प्रसव/अवधि पूर्व प्रीमेच्योर रपचर ऑफ मेमब्रेन्स
14. प्लेसेंटल स्थिति, मोटाई, ग्रेडिंग तथा असामान्यताओं का मूल्यांकन (प्लेसेंटा प्रीविया, रेट्रोप्लेसेंटल, हेमरेज, असामान्य एडेरेंस आदि)
15. गर्भनाल का मूल्यांकन-उपस्थिति, डालना, नकेल घेरा, वाहिनियों की संख्या तथा ट्रूनाट की उपस्थिति
16. पिछले सिजेरियन कटाई के निशानों का मूल्यांकन
17. भ्रूण विकास मानदण्डों का निर्धारण भ्रूण भार तथा भ्रूण स्वास्थ्य
18. रंग स्राव जाँच तथा डूप्लेक्स डापलर अध्ययन
19. अल्ट्रासाउंड आधारित प्रक्रियाएँ जैसे चिकित्सीय गर्भपात, बाह्य सिफालिक वर्जन आदि एवं अनुवर्ती
20. निदान संबंधी एडजंक्ट एवं थेरेप्यूटिक इन्वेसिव इंटरवेंशन जैसे जीर्ण विलस सेम्पलिंग (सी वी एस)

प्रपत्र - छ
(नियम 10 देखें)
सहमति का प्रपत्र
(अपवचन तरीको के लिये)

मैं.....पत्नी/पुत्री.....आयु.....
वर्ष निवासी.....एतद्वारा उल्लेख करती हूँ कि मैंने संभावित साइड
प्रभावों तथा पूर्व-प्रसव निदान पद्धतियों के बाद के प्रभावों को पूर्ण रूप से रूपवर कर दिया है।

मैं बच्चे में, जो मेरी देखरेख में है। किसी भी प्रकार की असामान्यता (जैसे :- बीमारी/विकृति/
खराबी की संभावना का पता लगाने के लिये अपनी इच्छा से प्रिइम प्लांटेशन/पूर्व-प्रसव निदान
तकनीक/जांच पद्धतियों अपनाना चाहता हूँ।)

मैं समझता हूँ कि भ्रूण के लिंग के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं होगी।
मैं समझता हूँ कि इस शपथ का उल्लंघन करने पर मैं दण्ड का उत्तरदायी हूँ जैसा कि पूर्व-प्रसव
निदान तकनीक (विनियम तथा दुरुपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) में तथा उसके
अधीन निर्मित नियमावली में निर्धारित है।

दिनांक :
स्थान :

गर्भवती महिला के हस्ताक्षर :

मैंने उपरोक्त तथ्यों के बारे में मरीज को तथा उसके सहयोगी की उसकी/उनकी भाषा में स्पष्ट
रूप से समझा दिया है/स्पष्ट कर दिया है.....(नाम.....पता.....
सम्बन्ध)

स्त्री रोग विशेषज्ञ/
चिकित्सा जैनेटिसिस्ट/रेडियोलोजिस्ट

दिनांक:

जैनेटिक क्लिनिक/संस्था का नाम, पता
तथा पंजीकरण संख्या

मुहर

h

फॉर्म - ज

(नियम 9 (5) देखें)

पूर्व-प्रसव नैदानिक तकनीक (विनियम तथा दुरुपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीकरण करने/रद्द करने के लिए आवेदनों के स्थायी अभिलेख के रखरखाव के लिए प्रपत्र

1. क्रम संख्या
2. समुचित प्राधिकारी की फाइल संख्या
3. पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख
4. आवेदक का नाम, पता, फोन/फैक्स इत्यादि
5. जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का नाम एवं पता
6. सलाहकार समिति द्वारा विचार किए जाने एवं सिफारिश (संक्षेप में) की तारीख
7. आवेदन की स्थिति (दिया गया प्रपत्र ख तथा ग में) रद्द किया गया तथा आदेश अभिलेख जारी करने की तारीख
8. आबंटित पंजीकरण संख्या तथा समाप्ति की तारीख
9. नवीकरण (नवीकरण की तारीख तथा जब तक नवीकरण किया गया)
10. फाइल संख्या जिसमें नवीकरण किया गया
11. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो

समुचित प्राधिकारी का नाम,
पदनाम तथा हस्ताक्षर

- (क) प्रपत्र 'क' एक स्थायी अभिलेख है जो समुचित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रजिस्टर के रूप में रखा जाए।
- (ख) *साधन काट दिए जाएं, जो लागू न हों।
- (ग) नवीकरण पर जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र की पंजीकरण संख्या परिवर्तित नहीं होगी। एक नया पंजीकरण संख्या स्वामित्व अथवा प्रबंधन में परिवर्तन के कारण आबंटित किया जाएगा।
- (घ) पंजीकरण संख्या दो बार आबंटित नहीं की जाएगी।
- (ङ) प्रत्येक जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र को एक फोलियो दिया जाएगा जिसमें प्रपत्र 'ज' के अभिलेख के लिए रजिस्टर के दो पृष्ठ होंगे।

- (च) अतिरिक्त सूचना के लिए निर्धारित स्थल निलंबन अभिलेख, निरसन, नवीकरण के लिए आवेदन को रद्द करना स्वामित्व/प्रबंधन में परिवर्तन, किसी प्रकार की अन्य कानूनी कार्यवाही इत्यादि के लिए प्रयुक्त किया जाए।
- (छ) रजिस्टर के प्रत्येक फोलियों (2 पृष्ठ) समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा तारीख सहित प्रमाणित होगी तथा प्रत्येक प्रविष्टि भी उसी तरह प्रमाणित होगी।

(सुश्री के० सुजाता राव)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
संख्या 24026/14/2008 पीएनडीटी सैल

पाद : मूल अधिसूचना 01 जनवरी, 1996 के हीएसआर 1(ई) के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई।

203

no